संपादकीय जागरण

गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 : कार्तिक कृष्ण - 3 वि. 2082

विश्वास ही संबंधों का आधार होता है

भरोसा डिगाने वाला रवैया

मध्य प्रदेश और राजस्थान में विषाक्त कफ सीरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौतों पर जांच और कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं, वे यदि बहुत भरोसा नहीं जगातीं तो इसके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। एक तो लोगों को चिंतित करने वाले इस गंभीर मामले में कथित ठोस कार्रवाई शिथिल ढंग से हो रही है और दूसरे, समस्या यानी विषाक्त दवा के बनने व बिकने की दोषपूर्ण प्रक्रिया को जड़ से ठीक करने के लिए वैसे प्रयास नहीं हो रहे, जैसे होने ही नहीं, दिखने भी चाहिए थे। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि उन कारणों की तह तक जाने की चेष्टा क्यों नहीं की जा रही है, जिनके कारण तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल की ओर से तैयार कफ सीरप कोल्ड्रिफ की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं हो सका। इस नाकामी का नतीजा यह हुआ कि विषाक्त कफ सीरप बनी और उसकी आपूर्ति भी हो गई। आखिर इस जानलेवा नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे जवाबदेह कब बनाया जाएगा? इस पूरे मामले में खेद की बात यह भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उतना सचेत और संवेदनशील नहीं दिख रहा, जितना अपेक्षित है। क्या उसकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वह राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को केवल सुझाव देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेगा? यह सही है कि दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण राज्य सरकारों की एजेंसियां करती हैं, लेकिन क्या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ को यह नहीं देखना चाहिए कि यह काम सही तरह से हो रहा है या नहीं? आखिर ऐसी नियामक संस्था किस काम की, जो राज्यों की एजेंसियों को सही तरह काम करने के लिए बाध्य न कर सके?

यदि कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में दोषी लोगों को कठोर दंड का भागीदार बनाकर कोई नजीर स्थापित नहीं की गई तो दोयम दर्जे की दवाओं के निर्माण का सिलसिला थमने वाला नहीं। घटिया किस्म की दवाओं के निर्माण की गुंजाइश छोड़ने का मतलब है विषाक्त और नकली दवाओं के निर्माण की भी राह खुली रखना। यह अक्षम्य ही नहीं आत्मघात है, क्योंकि इससे लोगों का दवाओं पर से ही भरोसा उठ जाएगा। यह व्यवस्था में किसी बड़ी खामी का प्रमाण है कि हर माह जो ड्रग अलर्ट जारी होता है, उसमें कई दवाओं के सैंपल फेल पाए जाते हैं। एक ऐसे समय जब देश में पहले से ही खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण हो रहा है, तब केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसा न होने देने के लिए कोई ठोस उपाय न करना लोगों के भरोसे को डिगाने वाला तो है ही, देश की बदनामी कराने वाला भी है। क्या भारत घटिया किस्म की दवाओं का निर्माण करके खुद को दुनिया की फार्मेसी होने का दावा कर सकता है?

भीड़ प्रबंधन जरूरी

दिल्ली में दीपावली और छठ के अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए अभी से भीड़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू किया जाना सर्वथा उचित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ अधिक होने के दौरान भगदड़ होने की पूर्व में घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नई दिल्ली समेत राजधानी के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के प्रति गंभीरता दिखाया जाना बेहद आवश्यक है। रेलवे प्रशासन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ सात हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया तैयार कर रहा है, साथ ही आनंद विहार टर्मिनल पर भी अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, ताकि प्लेटफार्मों पर भीड़ न एकत्रित होने पाए।

> रेलवे अस्थायी प्रतीक्षालय बनाने के साथ प्रबंध करे कि यात्री को जिस ट्रेन से जाना हो, वह उसी प्लेटफार्म पर पहुंचे

प्लेटफार्मों पर अधिक भीड़ हो जाने के कारण विगत फरवरी माह में ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में दीवाली व छठ के समय जब बड़ी संख्या में यात्री पूर्व की ओर जाते हैं, उस समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। रेलवे प्रशासन को होल्डिंग एरिया और अस्थायी प्रतीक्षालय बनाने के साथ ही इस बात के विशेष प्रबंध करने चाहिए कि यात्री को जिस ट्रेन से जाना है, वो सीधे उस ट्रेन से संबंधित प्लेटफार्म पर ही पहुंचे। इससे प्लेटफार्मों पर अधिक भीड़ एकत्रित नहीं हो पाएगी। साथ ही, आखिरी समय में किसी ट्रेन का प्लेटफार्म बदले जाने पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए। इन उपायों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी यात्रा को सुखद बना सकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जोहो का अरट्टई एप वाट्सएप का भारतीय विकल्प बनने में सक्षम है?

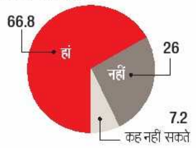

आज का सवाल

क्या ब्रिटिश पीएम स्टार्मर का भारत दौरा देश की अर्थव्यवस्था में वैश्विक भरोसे को दर्शाता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

एक-दूसरे की जरूरत बने भारत-ब्रिटेन

हर्ष वी. पंत

एक समय भारत-ब्रिटेन के रिश्ते ऐतिहासिक संबंधों और प्रवासियों से तय होते थे, लेकिन अब वे व्यापक रणनीतिक साझेदारी से निर्धारित हो रहे हैं

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर और उनके साथ 125 सदस्यीय विशाल प्रतिनिधिमंडल भारत आ चुका है। बतौर प्रधानमंत्री यह उनका पहला भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐतिहासिक ब्रिटिश दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से स्टार्मर के भारत दौरे पर नजरें टिकी हुई थीं। वैश्विक उथलपुथल और टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान ने भी इस दौरे का महत्व और बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के ब्रिटिश दौरे पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इस दौरे पर उनकी प्रगति की समीक्षा के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को नए आयाम दिए जाने की व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के इतने बड़े दल के साथ स्टार्मर का आना इस दौरे की महत्ता को ही दर्शाता है। इस समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जिन चुनौतियों से जूझ रही है उन्हें देखते हुए यह स्वाभाविक है कि उनसे निपटना सरकार की प्राथमिकता में होगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए स्टार्मर चाहेंगे कि वे इस दौरे को अधिक से अधिक सार्थक बनाकर ही स्वदेश लौटें।

स्टार्मर के दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा से ही यही संकेत मिलते हैं कि आर्थिक-रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध इसके मूल में हैं। चाहे दौरे के लिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का चयन हो या उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात, सीईओ फोरम में भागीदारी हो या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में सहभागिता या भारतीय फिल्म निर्माण से जुड़े केंद्रों का अवलोकन, इन सभी गतिविधियों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जुलाई में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे पर जिस मुक्त व्यापार समझौते पर बात बनी थी, उसे प्रभावी बनाने से जुड़ी चर्चा भी इस दौरे के एजेंडे में शामिल है। इस बीच, ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की बात भी प्रमुखता से हो रही है, जिससे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे ब्रिटेन की आर्थिकी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

यह दौरा उस पहलू को भी रेखांकित करता है कि भारत-ब्रिटेन संबंध अतीत की औपचारिकताओं से आगे बढ़कर व्यावहारिकता और परस्पर लाभ एवं विश्वास पर केंद्रित हो चले हैं। एक समय दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक संबंधों और प्रवासियों से तय होते थे, लेकिन अब ये उन बंदिशों से बाहर निकलकर भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी जैसी पहल से निर्धारित हो रहे हैं। इसके तहत दोनों

अवधेश राजपूत

देशों ने वर्ष 2035 तक कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके जरिये व्यापार एवं निवेश, तकनीकी समन्वय एवं रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा प्रयास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का उन्नयन और लोगों के बीच बेहतर सामाजिक संपर्क जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरे पर इन पहलुओं की समीक्षा होना स्वाभाविक है। इसमें भी व्यापार एवं निवेश और सामरिक रणनीति के ही मुख्य रूप से केंद्र में रहने के आसार हैं।

दोनों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ाकर जल्द ही 42 अरब पाउंड तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका अहम होने वाली है। करीब तीन साल के अथक प्रयासों के बाद अमल में आया यह व्यापार समझौता इतनी ठोस बुनियाद पर किया गया है कि अब जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर चर्चा हो रही है, उसमें यही समझौता मानक बन गया है। इससे मिलने वाले परस्पर लाभ को इसी से समझा जा सकता है कि जहां ब्रिटेन के एल्कोहल उद्योग एवं वाहन उद्योग की भारत जैसे बड़े एवं उभरते बाजार में पहुंच बनेगी, वहीं भारत के कपड़ा, चमड़ा एवं रत्न-आभूषण जैसे व्यापक श्रम खपत वाले उद्योगों को ब्रिटेन जैसे आकर्षक बाजार में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के इस दौर में यह समझौता और अधिक उपयोगी साबित होता दिख रहा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते समन्वय के बीच कुछ गतिरोध अभी भी बने हुए हैं। जैसे व्यापार समझौते के बावजूद ब्रिटेन में भारत के स्टील एवं फर्टिलाइजर उत्पादों को लेकर कुछ हिचक का माहौल है। इसके पीछे इन उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को एक कारण बताया जा रहा है। इसी तरह भारत में ब्रिटिश कानूनी सेवाओं को लेकर भी विरोध के स्वर सामने आए हैं। व्यापार समझौते के बाद उम्मीद बंधी थी कि भारतीय पेशेवरों के लिए ब्रिटेन जाने की राह और सुगम होगी, लेकिन उसमें अपेक्षित रूप से सकारात्मकता नहीं देखी जा रही है। संभव है कि स्टार्मर के दौरे पर इन बिंदुओं को लेकर भी कुछ चर्चा के साथ कोई स्वीकार्य समाधान निकालने की दिशा में प्रयास किए जाएं।

सामरिक सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में बना हुआ है। चूंकि दोनों देश कई बिंदुओं पर साझा सोच रखते हैं, इसलिए सहयोग का मोर्चा भी सुगम दिखता है। समकालीन वैश्विक परिस्थितियों को भांपते हुए ब्रिटेन ने भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने का समझदारी भरा रुख अपनाया है। इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव उसे एक स्वाभाविक साझेदार बनाता है, जो पिछले कुछ समय में ब्रिटेन के साथ बढ़ रही सक्रियता में नजर भी आ रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों को लेकर भी दोनों देश एकसमान दृष्टिकोण रखते हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अंकुश से लेकर सामुद्रिक आवाजाही को सुगम एवं सुरक्षित बनाने से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थायित्व और संतुलन को लेकर भी दोनों देश एक ही धरातल पर दिखते हैं। सामरिक मोर्चे पर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में रक्षा तकनीक साझेदारी और रक्षा उत्पादन को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है। साथ ही खुफिया सूचनाओं को साझा करने की राह में भी अवरोध दूर किए जाने के पूरे प्रयास होंगे। बदलते वैश्विक ढांचे और परिस्थितियों में भारत-ब्रिटेन साझेदारी की निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका होगी। स्टार्मर का यह दौरा इस साझेदारी को गति प्रदान करने का काम करेगा।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

भारत की दृष्टि हैं प्राचीन पांडुलिपियां

डा. सुशील पांडेय

हमारी प्राचीन पांडुलिपिया राष्ट्र की जीवन स्मृति और उसकी सभ्यता के पहचान की नीव हैं

पिछले दिनों ज्ञान भारतम् मिशन की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया और नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग पांडुलिपियों में बिखरे भारतीय ज्ञान के संरक्षण, उनके डिजिटलीकरण और प्रसार के साथ विदेश चली गई मूल कृतियों को वापस लाने का प्रयास शामिल है। इस घोषणापत्र में मूल पांडुलिपियों को वापस प्राप्त करने और उन्हें विदेश से लाने और उनकी डिजिटल प्रतियां सुरक्षित करने, शोध और राष्ट्रीय गौरव के लिए उन तक पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। भारत अब तक दुनिया भर से चोरी या फिर तस्करी के द्वारा देश के बाहर गईं 600 से अधिक धरोहरों को वापस ला चुका है। इनमें अकेले अमेरिका से ही 559 धरोहरों को वापस लाया गया है। पांडुलिपियां किसी राष्ट्र की जीवन स्मृति और उसकी सभ्यता की पहचान की नींव होती हैं। भारत जैसी संस्कृति वाले राष्ट्र के पास पांडुलिपियों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें लगभग एक करोड़ ग्रंथ हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पांडुलिपियां ताड़ पत्र, हस्तनिर्मित कागजों, शंटी की छालों, कपड़ों, चर्मपत्र, बर्च (भोजपत्र), ताम्रपत्र के रूप में सुरक्षित हैं, जिनका संरक्षण आधुनिक तकनीक से करने के साथ-साथ शोधकर्ताओं तक पहुंच को आसान बनाना आवश्यक है। ये सभी पांडुलिपियां मूल स्रोत के रूप में हस्तलिखित होती थीं, जो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से पहले सूचनाओं को रिकार्ड करने का साधन थीं। मध्यकाल और आधुनिक काल में विदेशी आक्रांताओं ने इन्हें नष्ट तो किया, लेकिन आजादी के बाद इनके महत्व को न समझना और इनका संरक्षण न किया जाना दुखद है। प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भारतीय इतिहास में भी उचित स्थान नहीं मिल पाया। भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति केवल राजनीतिक नहीं थी, जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन में दिखती है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, लोक चेतना, मानवता और नैतिकता पर आधारित जीवन दृष्टि, प्रकृति के

समृद्ध प्राचीन भारतीय ज्ञान को मिलती स्वीकार्यता ● फाइल

साथ सामंजस्य और वैज्ञानिक चेतना से युक्त दृष्टि भारतीय जीवन का मूल आधार थी। भारत की दार्शनिक पद्धतियां आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक चेतना से युक्त थीं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में सभी समाजों के लिए मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान थीं। जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने धार्मिक दृष्टिकोण से राजनीतिक इतिहास लिखा और आक्रांताओं की नीतियों को वैधता प्रदान की।

आधुनिक काल में अंग्रेजी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक मानसिकता से भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारतीय चिंतनधारा को अवरुद्ध करके पश्चिमी मूल्य और संस्कृति को श्रेष्ठता प्रदान करने के साथ-साथ औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना था। आजादी के अमृतकाल में भारतीय समाज अपने अतीत के प्रति आग्रही दिख रहा है और अपनी मूल चिंतन धारा को नए संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीयता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए आधार प्रदान किया है। आज भारतीय इतिहास को शोधकर्ता नई दृष्टि और संदर्भों के साथ-साथ वैज्ञानिक शोधों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिक और मूल स्रोतों के साथ इतिहास सामने आ रहा है, जिससे अतीत की भ्रांति भरे विमर्श अप्रासंगिक हो रहे हैं। पूर्वाग्रह से लिखा गया इतिहास वैज्ञानिक दृष्टि और स्रोतों के साथ आज प्रस्तुत करने से झूठा साबित हो रहा है। पुरातात्विक उत्खनन से भारतीय सभ्यता के नए पक्ष स्पष्ट हुए हैं। भारतीय शासकों की विजय और जनकल्याणकारी शासन के नए पक्ष सामने आ रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय ज्ञान पर शोधपीठों की स्थापना हो रही है और वैज्ञानिक संस्थान भी प्राचीन ज्ञान की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं।

भारतीय जीवन पद्धति, आयुर्वेद और योग को संपूर्ण विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर रहा है। यूनेस्को भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को विश्व विरासत के रूप में स्वीकार कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्ष का चिंतन-मनन, महान विद्वानों और चिंतकों का शोध, भारत की वैज्ञानिक धरोहर शामिल हैं, जो भारतीय पांडुलिपियों में आसानी से खोजी जा सकती हैं। ये पांडुलिपियां केवल अतीत की धरोहर नहीं हैं, अपितु भविष्य के भारत की दृष्टि और दृढ़ संकल्प हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा लंबे समय से चले आ रहे बौद्धिक चिंतन, परस्पर विमर्श और तार्किकता पर आधारित लोक स्वीकृति का परिणाम है। भारत का निर्माण उसके विचारों आदर्शों एवं मूल्यों से हुआ है। भारत की पांडुलिपियां समूची मानवता की विकास यात्रा का पदचिह्न है। कोई भी सभ्यता अपने मूल आदर्श और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ती है। पांडुलिपियों का संरक्षण और इसके आधार पर इतिहास लेखन राष्ट्र निर्माण की नई परिभाषा प्रस्तुत करेगा। स्व का बोध और अतीत की महान विरासत भारतीयता के मूल्यों को मजबूत करेगी और राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प पूर्ण करेगी। काल्पनिक स्रोतों पर आधारित पूर्वाग्रह के आधार पर लिखा गया इतिहास भारतबोध को लगातार कमजोर करता रहा है। पांडुलिपियों के आधार पर लिखे गए इतिहास को तार्किक और वैश्विक स्वीकृति प्राप्त होगी।

(लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्राध्यापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चिंतन का महत्व

मनुष्य जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं चिंतन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा-परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते भर हैं। जिज्ञासा और आत्मपरीक्षण ही वह कसौटी है, जो विचार को जीवित रखती है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया।

डेसकार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यह कथन चिंतन को अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव रह जाएगा। चिंतन न केवल मनुष्य को अलग पहचान देता है, बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? डेसकार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना एक जिम्मेदारी है।

रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। गांधीजी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है।

कैलाश मांजू बिश्नोई

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बढ़ानी होगी अपने उत्पादों की गुणवत्ता

'आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने लचर प्रशासन तंत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। देश मे नकली और लचर गुणवत्ता वाली दवाओं के कारोबार की खबरें वर्षों से आ रही हैं, फिर भी उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। इसके चलते लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अतीत में सरकार ने ऐसी कोई नजीर बनने वाली कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लग पाता। आवश्यकता है कि दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियां और दवाओं की जांच करने वाले अधिकारियों की भूमिका को भी और जवाबदेह बनाना होगा। केवल दवाएं ही नहीं, बल्कि भारत के तमाम उत्पाद विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए वैश्विक बाजारों में हमारे उत्पाद अपनी छाप नही छोड़ पा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भरता को लेकर किया जाने वाला आह्वान अपेक्षित रूप से परवान नहीं चढ़ पाएगा।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, जरगांव (उन्नाव)

जस्टिस पर जूता

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश करने का प्रकरण ज्वलंत है। इसकी पृष्ठभूमि में खजुराहो के जावरी मंदिर की भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को समुचित रूप में लाकर पूजा के अधिकार को बहाल करने संबंधी एक याचिका का सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करना है और इसमें मामले में दिए गए मुख्य न्यायाधीश के बयान को किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता और वकील का कृत्य निंदनीय व यथा विधान दंडनीय है। हालांकि इस घटना से कुछ प्रश्न जरूर उभर कर आते हैं, जिन पर सुसंगत और प्रबुद्ध वर्ग की ओर से गहन मंथन अपेक्षित है। प्रथम तो यह कि जब सुप्रीम कोर्ट तमाम ऐसे प्रकरणों पर दखल देती रहती है, जो कार्य विभाजन में सीधे सीधे उसकी परिधि में न होकर अन्य स्तंभ के कार्य क्षेत्रांतर्गत होते हैं, तो भगवान की मूर्ति को भी पूर्व मौलिक स्थिति में लाने का यदि आदेश दे देते, तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होता। यदि ऐसा नहीं भी किया था, तो परवर्ती कटाक्ष करने से तो बच ही सकते थे। दूसरी बात यह भी है कि न्यायधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रचलित कोलेजियम पद्धति के चलते जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और घूम फिरकर कुछ गिने-चुने परिवारों के लोग ही उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के जज होते रहते हैं। इस पद्धति की बड़ी आलोचना होती है और ऐसा विश्व के किसी देश मे नहीं है। यह पद्धति संविधान में भी उल्लिखित नहीं है। तीसरे यह कि ऐसी कानूनी व्यवस्था कर दी गई है कि इन बड़े जजों पर गंभीर से भी गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार और लैंगिक दुराचरण के आरोप लगने पर कोई कार्यवाही नही होती, जिससे जनता में आक्रोश है। एक चौथी बात यह भी है कि ये जज प्रायः सत्ता के पक्ष में निर्णय देते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भारी भरकम पद प्राप्त कर लेते है, जिससे जनता सहज ही शंकालू हो जाती है कि पद से उपकृत ये जज क्या सेवाकाल मे निष्पक्ष रहे होंगे! इस तरह के सवाल आम आदमी के मन उठते जरूर हैं।

रघोत्तम शुक्ल, रिटायर्ड पी सी एस, लखनऊ

सुरक्षित यातायात के सुप्रीम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सभी राज्यों को पैदल यात्रियों और मोटर रहित वाहनों के लिए सुरक्षित आवागमन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के निर्माण, रखरखाव और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए छह महीने का समय दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इन नियमों में पैदल चलने वालों और गैर-मोटर चालित वाहनों (जैसे साइकिल, रिक्शा आदि) की आवाजाही को स्पष्ट रूप से विनियमित किया जाए। देश के महानगरों में फुटपाथ पूर्णतया अवैध कब्जे का शिकार हो चुके हैं और लोगों का सड़क पर चलना मजबूरी बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली भी इसका अपवाद नहीं है। दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों की बड़ी समस्या है। स्थानीय बाजार और एप्रोच रोड अवैध कब्जे से पट जाते हैं, जिससे सुरक्षित आवागमन के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। राज्य सरकारों को इस संदर्भ में सभी संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस कार्य योजना बनाना चाहिए। सभी छोटे-बड़े शहरों में सड़कों के रखरखाव की समस्या बनी रहती है, इसलिए दुर्घटनाएं भी होती हैं। यदि मोटर रहित वाहनों को सड़कों पर चलने दिया जाए तो उसकी भी एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। पैदल यात्री सड़कों पर चलेंगे तो दुर्घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय और कॉलोनी की सड़कों पर नो वेंडर जोन घोषित कर देना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पोस्ट

उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय प्रशंसनीय और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। प्रियंक कानूनगो@KanoongoPriyank

पाकिस्तानी आर्थिकी इतनी खस्ताहाल है कि फाइजर, प्रोक्टर एंड गैंबल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना काम वहां से समेट रही हैं। कारपोरेट अमेरिका के लिए पाकिस्तान बोझ बन चुका है। फिर भी, ट्रंप पाकिस्तान को तवज्जो दे रहे हैं। मोनिका वर्मा@TrulyMonica

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कहा कि मैं मुंबई में ब्रिटिश उद्यमों को आगे बढ़ाने आया हूं, क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्यमों की वृद्धि हमारे देश में लोगों के लिए अधिक रोजगारों का जरिया बनेगी। क्या भारत को डेड इकोनमी कहने वाले ट्रंप के कानों तक यह बात पहुंचेगी?

राहुल शिवशंकर@RShivshankar

बिहार में प्रमुख दलों को शायद अहसास था कि सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दल बढ़-चढ़ कर मांग करेंगे। इसीलिए इस काम को अंतिम समय तक के लिए टाल कर रखा गया, ताकि ऐन वक्त पर कोई पाला न बदल सके। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

ओवरटाइम कर रहे इंद्र देव इस बार,
प्रलय ढा रहे हर तरफ दे पानी की धार।
दे पानी की धार प्रकट हों फिर गिरधारी,
तब शायद प्रस्थान करें बादरिया कारी!
कटने को है धान चाहिए अब सन शाइन,
होना चहिए बंद इंद्र का ओवरटाइम!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 84

****

मोदी ने कहा-सामाजिक न्याय के प्रतीक थे रामविलास पासवान

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पांचवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया और कहा कि वे जनसेवा के लिए समर्पित थे। मोदी ने कहा कि वे बिहार के एक लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित और शोषित समुदायों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान ने पूरा जीवन समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित कर दिया। श्रद्धांजलि अर्पित कर शाह ने कहा कि पासवान ने छात्र जीवन से ही वंचितों के अधिकारों की वकालत की। शाह ने एक्स पर कहा, ''रामविलास का करुणामय व्यक्तित्व और जनसेवा का संकल्प सभी की स्मृतियों में सदैव रहेगा।

पीएम मोदी • फाइल फोटो

हमेशा समाज के वंचित और शोषित समुदायों के कल्याण के लिए काम किया, राष्ट्र निर्माण में योगदान हमेशा याद रहेगा

सीट शेयरिंग पर बोले चिराग-पिता ने सिखाया, कदम-कदम पर लड़ना सीखो

महासमर बिहार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल मची है। दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन चल रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सबकी निगाहें चिराग पर टिकी हैं।

बुधवार को चिराग दिल्ली से पटना पहुंचे। सीट शेयरिंग पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल से चिराग बचते रहे। सिर्फ इतना कहा कि इंतजार कीजिए ना, अभी बहुत शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है-पापा हमेशा कहा करते थे- जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। चिराग ने एक्स हैंडल पर पिता रामविलास के संकल्प को पूरा करने का प्रण लिया। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना पिता ने देखा था, उसे अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है।

चिराग पासवान • फाइल फोटो

बिहार चुनाव में केंद्र सरकार पर भी लागू होगी आदर्श आचार संहिता

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में चुनाव की आदर्श आचार संहिता (माडल कोड आफ कंडक्ट-एमसीसी) के प्रविधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं।

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के तुरंत बाद यह चुनाव कोड लागू किया। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। बुधवार को जारी एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा, ''आदर्श आचार संहिता केंद्र में मौजूद राजग सरकार पर भी लागू होगी, जब तक कि यह बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों से संबंधित है।'' चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा कि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी निवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या पिकेटिंग नहीं होनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने को कहा, निजी निवासों के बाहर कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए

मांझी की चेतावनी, 15 सीटें नहीं मिलीं तो एक पर भी नहीं लड़ेंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : एनडीए में टिकट बंटवारे का पेच बुरी तरह फंस गया है। चिराग पासवान की ना-नुकूर के बीच अब केंद्रीय मंत्री एवं हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मांझी ने बुधवार को पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता 'रश्मिरथी' से कृष्ण की चेतावनी वाले हिस्से की पंक्तियां साझा कीं। मीडिया से बात कर स्पष्ट किया कि अगर उनकी पार्टी को 15 सीटें नहीं मिलती हैं, तो वह एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे।

मांझी ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट पर कविता पोस्ट कर लिखा-' हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असि न उठाएंगे।' उनकी इस पोस्ट में आग्रह और चेतावनी दोनों हैं। पोस्ट में 15 ग्राम को विस की 15 सीटों से जोड़कर देखा जा रहा है।

जीतन राम मांझी • फाइल फोटो

एक नजर में

तेजस्वी ने जनता से मोबाइल पर की बात, पूछा-माहौल ठीक है न

पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के एक नए अंदाज में जुटे हैं। वे रैंडम मोबाइल नंबरों पर काल कर आम नागरिकों से फीडबैक ले रहे हैं। पूछ रहे हैं कि "माहौल ठीक है न?" और कौन-सा प्रत्याशी लोगों को बेहतर लग रहा है। साथ ही, वे जनता से राजद के पक्ष में मतदान की भी अपील कर रहे हैं। तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर दो लोगों से बातचीत की आडियो क्लिप साझा की है, जिसमें वे मधुबनी और दरभंगा जिले के नागरिकों से संवाद करते सुनाई दे रहे हैं। मधुबनी जिले के राजनगर सुरक्षित सीट के सतीश कुमार से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने वहां के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की। सतीश ने प्रो. विष्णुदेव राम और उमेश राम के नाम सुझाए। (राब्यू)

चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी देंगे चाचा पारस

पटना: दो दिन पहले भतीजे चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात करने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बुधवार को पलट गए। कहा कि जहां-जहां चिराग की रालोजपा के उम्मीदवार होंगे, वहां हम बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। (राब्यू)

दांव पर उत्तर बिहार के 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा

मिथिलांचल के सात, तिरहुत के पांच नेता को परखेंगे वोटर

अजय पांडेय • जागरण

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर बिहार के दोनों चरण महत्वपूर्ण होंगे। इसबार 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मिथिलांचल के सात और तिरहुत के पांच मंत्री हैं। इनमें भाजपा कोटे से आठ और जदयू से चार हैं। छह नवंबर को पहले चरण में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा की 31 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें सात मंत्री कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री डा. राजू सिंह, जाले से नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, दरभंगा नगर से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी, सरायरंजन से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं।

11 नवंबर को दूसरे चरण में पांच झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, फुलपरास से परिवहन मंत्री शीला मंडल, बेतिया से पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी, हरसिद्धी से गन्ना एवं उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान और रीगा से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद हैं।

कुछ सीटों पर घोषणा की औपचारिकता: बेतिया से भाजपा विधायक रेणु देवी का टिकट तय माना जा रहा। हालांकि, सांसद डा. संजय जायसवाल के करीबी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व इरकान के पूर्व निदेशक दीपेंद्र सर्राफ उनकी चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता और डा. राजू सिंह की टिकट घोषणा की औपचारिकता है। मोतीलाल प्रसाद को पार्टी एक मौका और दे सकती है। समस्तीपुर में विजय कुमार चौधरी लगातार दो टर्म से जीत दर्जकर रहे, वहीं महेश्वर हजारी भी पार्टी के मजबूत नेता हैं। इनकी सीट बदलने को लेकर पार्टी जोखिम नहीं लेगी। हरिसिद्धि से भी भाजपा चेहरा बदलने की तैयारी में नहीं है।

जाले में ऊहापोह तो बहादुरपुर-गौड़ाबौराम में अदला-बदली की चर्चा: जाले से जीवेश कुमार को लेकर जरूर ऊहापोह है। यू-ट्यूबर से मारपीट व मुकदमा सहित अन्य कुछ मामलों में नाम आने के बाद उम्मीदवार बदलाव की भी सुगबुगाहट है। बहादुरपुर से जदयू विधायक मदन सहनी की सीट में एकबार फिर बदलाव हो सकता है। जदयू उन्हें 2015 की तरह गौड़ाबौराम से उतारने पर विचार कर सकता है। वहां से भाजपा की स्वर्णा सिंह विधायक हैं। एनडीए के दोनों घटक दल अदला-बदली कर सकते हैं। वहीं, नीतीश मिश्रा का टिकट झंझारपुर से कन्फर्म माना जा रहा।

पहले चरण में कांटे की टक्कर वाली सीटों पर होगा मुकाबला

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में छह नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच करीब-करीब बराबर बंट गई थीं, जहां महागठबंधन को मामूली बढ़त मिली थी। इस बार इन सीटों पर फिर से जोरदार संघर्ष तय है, लेकिन समीकरणों में कई बदलाव ने मुकाबले को और पेचीदा बना दिया है।

पिछली बार इन 121 में से राजग को 59 सीटें मिली थीं। बाद में लोजपा का एक विधायक जदयू में सम्मिलित हो गया था तो यह आकड़ा 60 पर पहुंच गया था। इसमें भाजपा को 32, जदयू को 23 और विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) को चार सीटें मिली थीं। वीआइपी तब राजग का हिस्सा थी। महागठबंधन को 61 सीटों पर सफलता मिली थी। उसमें राजद को 42, कांग्रेस को आठ, भाकपा-माले को सात तथा भाकपा और माकपा को दो-दो सीटों पर जीत मिली थीं। चुनाव परिणाम पर गौर करें तो क्षेत्रवार प्रदर्शन में भी बाजी बंटी रही। दरभंगा और तिरहुत प्रमंडल में एनडीए ने बढ़त बनाई थी, जबकि मगध और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन का प्रभाव अधिक देखने को मिला। इस बार दोनों गठबंधनों ने एक-दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत जिन 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, उनमें 66 सीटें एनडीए के पास थीं। 49 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। यहां एनडीए कुछ भारी पड़ा था। 243 सीटों की लड़ाई में हर सीट महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

पहले चरण की 121 सीटों पर पिछली बार हुई थी जोरदार भिड़ंत, एनडीए पर बीस पड़ा था महागठबंधन

इस बार जन सुराज पार्टी की एंट्री

इस चुनाव में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी भी कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इससे विशेष तौर पर उन सीटों पर असर पड़ सकता है, जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर कम था।

कांग्रेस ने बढ़ाया राजद पर दबाव, तय किए 25 प्रत्याशियों के नाम

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम आने में अब महज पांच सप्ताह बचे हैं, लेकिन महागठबंधन का समीकरण अभी भी उलझा हुआ है। छोटे सहयोगी दलों की बड़ी मांगों ने बड़े दलों के लिए स्थिति को जटिल बना दिया है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की मौजूदगी में वर्किंग कमेटी की बैठक कर अपने हिस्से की संभावित सीटों में से 25 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं।

कांग्रेस का यह कदम न सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर राजद पर दबाव बढ़ाने वाला है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि यदि उसकी शर्तों पर सहमति नहीं बनती है तो वह पहले चरण की सीटों पर अपने प्रत्याशियों की एकतरफा घोषणा कर सकती है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस यह रहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्थिति को सिर्फ सहयोगी दल तक सीमित न रखे, बल्कि गठबंधन में निर्णायक भूमिका निभाए। शीर्ष नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को अपनी सीटों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए। हालांकि सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया कि अपने हिस्से की संभावित सीटों पर पार्टी के भीतर विमर्श पूरा हो चुका है और कई सीटों पर अंतिम मुहर भी लग गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे की संयुक्त घोषणा 11 अक्टूबर को हो सकती है। उधर, राजद नेता तेजस्वी यादव विकासशील इंसान पार्टी की ऊंची सीट दावेदारी से असहज हैं। अब कांग्रेस के आक्रामक रुख ने उनकी चुनौती और बढ़ा दी है। यदि महागठबंधन के भीतर सहमति नहीं बनती है तो गतिरोध को दूर करने के लिए सोनिया गांधी और लालू प्रसाद को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

सोनिया गांधी •फाइल फोटो

- कांग्रेस ने रणनीतिक दबाव बनाकर तैयार कर रखी है संभावनाओं की जमीन
- राजद के लिए हर कदम पर संतुलन साधना अब बन गया है बड़ी चुनौती

ज्योति विधायक बनने के लिए इतना गिरेंगी, उम्मीद नहीं थी : पवन

जासं, लखनऊ: गायक व अभिनेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बाद बुधवार को कहा, 'वह (पत्नी) एक-दो महीने पहले यह अपनापन क्यों नहीं दिखा रही थीं। वह विधायक बनने के लिए इतना गिर सकती हैं, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि हमारी बेटी को विधायक बना दीजिए, फिर जो करना है करिये, लेकिन यह संभव नहीं है।'

लखनऊ में पत्रकारों से पवन ने कहा कि लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन परिवार की जो भी बात होती है, कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं। मैं कम बोलता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हर बात में सफाई दूं।' वहीं पवन सिंह के आरोपों पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लखनऊ में कहा, 'पवन जी को अगर बच्चा चाहिए होता, तो वह मुझे गर्भपात की दवा नहीं खिलाते। अगर वह पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।'

आपरेशन सिंदूर से सहमे पाक को फिर हमले का डर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पांच महीने पहले आपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब भी इस सैन्य अभियान से सहमा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि उस पर भारत फिर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से इस डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ युद्ध का खतरा वास्तविक है। इसके साथ ही मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे मंत्री ने यह दावा तक कर डाला कि भविष्य में अगर कोई सशस्त्र संघर्ष हुआ तो उनका देश ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेगा। उनका यह बड़बोलापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयानों के बाद आया है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मंगलवार को समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में यह टिप्पणी उस सवाल पर की, जिसमें उनसे भारतीय नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हालिया बयानों के बारे में पूछा गया था। उन्होंने दावा किया कि भारत मुगल शासक औरंगजेब के शासन के सिवाय कभी एकजुट नहीं रहा। जबकि अल्लाह के नाम पर बना पाकिस्तान मई में हुए संघर्ष के दौरान कई आंतरिक मुद्दों के बावजूद एकजुट रहा। ख्वाजा का यह दावा सच से कोसों दूर है। वहीं प्रेट्र के अनुसार, पाक सेना ने भारत को गीदड़ भभकी दी। कहा कि हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

- पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा-भारत से युद्ध का खतरा वास्तविक
- देख रहे सपने, दावे में कहा-इस बार हासिल करेंगे पहले से ज्यादा बड़ी जीत

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ • फाइल फोटो

आइएमएफ से मिला पैकेज और पाक ने शुरू की हथियारों की खरीद

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली: भारी आर्थिक बदहाली से गुजर रहा पाकिस्तान अर्थव्यवस्था बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से मई, 2025 में एक अरब डालर की मदद मिलने के कुछ ही महीने बाद हथियारों की खरीदारी में जुट गया है। मंगलवार को अमेरिका ने पाकिस्तान को 2.5 अरब डालर मूल्य के एयर-टू-एयर मिसाइल सिस्टम (एआइएम-120 एएमआरएएएम) खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही भारत की इस आशंका को बल मिला है कि जब भी पाकिस्तान को आइएमएफ से बेल-आउट पैकेज दिया जाता है, तो वह इसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में करता है। आइएमएफ की शर्तों की बात करें तो पाकिस्तान सीधे तौर पर उससे मिली आर्थिक मदद से रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकता। लेकिन, पुराने रिकार्ड कुछ और ही संकेत देते हैं।

स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपरी) का डाटा बताता है कि वर्ष 1980-2023 के बीच जब भी पाकिस्तान को आइएमएफ से आर्थिक मदद दी गई है, तब उसका हथियार आयात 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

आजम चुप, अखिलेश की शायरी में छिपा राज

जागरण संवाददाता, रामपुर : 'मेरा घर गली में है, जहां बरसात में पानी भर जाता है। किसी बड़े आदमी का आना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।' 23 सितंबर को जेल से रिहाई के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के ऐसे जज्बाती तंज भरे बयानों और बसपा में जाने के उठ रहे सवालों ने सियासी गलियारों में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। उम्मीद थी कि बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब उनकी मुलाकात होगी तो तमाम तहें खुल जाएंगी। खुली भीं, यह तय हो गया कि फिलहाल आजम सपा छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन बंद कमरे में हुई दो घंटे की मुलाकात के बाद जिस तरह आजम खामोशी ओढ़े रहे और अखिलेश भी शायराना अंदाज में गूढ़ बातें छिपाते दिखे, उससे साफ है कि अभी और परतें खुलना बाकी हैं।

मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक्स अकाउंट पर बयां किया -'क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की...।' यानी भावनाओं का इतना गहरा आदान-प्रदान कि किसी बात की जरूरत नहीं पड़ी। सपा के दो दिग्गजों के बीच डेढ़ साल बाद हुई मुलाकात सख्त शर्तों के दायरे में हुई। दोनों मीडिया के सामने आए। अखिलेश ने आजम को पार्टी का दरख्त बताया। साफ किया कि समय न मिलने के कारण हम आजम से जेल में मिलने नहीं जा सके। 2027 में सपा सरकार बनने पर आजम पर दर्ज केस वापस लेने की बात कही।

- डेढ़ साल बाद सपा दिग्गजों के बीच हुई करीब दो घंटे तक अकेले में मुलाकात
- अखिलेश बोले- गिले-शिकवे दूर हुए, सरकार बनने पर वापस होंगे आजम पर लगे झूठे मुकदमे

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व महासचिव आजम खां • सौ. एक्स अकाउंट

आजम-शिवपाल खेल न कर दें, अखिलेश को है ये डर

राब्यू, जागरण • लखनऊ : प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री व सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की राजनीतिक मजबूरी है। उन्हें इस बात का डर है कि शिवपाल सिंह और आजम मिलकर कोई खेल न कर दें।

'बंगाल सात दिनों में पूरी करे एसआइआर की तैयारी'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: चुनाव आयोग की दिल्ली से आई विशेष टीम ने बुधवार को एक बैठक में राज्य के जिलाधिकारियों को साफ कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) समेत सभी चुनावी तैयारियां सात दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए। किस जिले में कार्य कितना आगे बढ़ा है इसकी भी बारीकी से जांच की जाए।

वर्ष 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग की विशेष टीम मंगलवार की रात को कोलकाता पहुंची। टीम में उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, आयोग की आइटी शाखा की महानिदेशक सीमा खन्ना, आयोग के सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल हैं। बुधवार सुबह ज्ञानेश ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में हर जिले में किस तरह की तैयारी हुई है, इस पर चर्चा की गई है।

बंगाल में जिलेवार होगी गणना फार्म की छपाई: उपचुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया है कि एसआइआर की अधिसूचना के प्रकाशन के चार से पांच दिनों के भीतर जिलेवार गणना फार्म की छपाई का कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में फार्म अलग-अलग छपवाने होंगे। ज्ञानेश ने जिलाधिकारियों से यह भी जानने को कहा कि क्या उनके संबंधित जिलों में छपाई के लिए बुनियादी ढांचा है। गौरतलब है कि बिहार में, फार्म एक ही जगह से छपकर प्रत्येक जिले में भेजे जाते थे। बंगाल में निर्देश दिए गए हैं कि गणना प्रपत्र प्रत्येक जिले में अलग से मुद्रित किए जाएंगे।

- एसआइआर की तैयारी की समीक्षा को कोलकाता पहुंची है आयोग की विशेष टीम
- उप चुनाव आयुक्त ने कहा, लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

'ममता बनर्जी सरकार की तालिबानी मानसिकता'

नई दिल्ली, प्रेट्र: बंगाल में अपने नेताओं पर हुए हमलों को लेकर भाजपा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने बुधवार को ममता बनर्जी की आलोचना कर आरोप लगाया कि उनकी सरकार राज्य में "तालिबानी मानसिकता" के साथ शासन कर रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता पर भाजपा नेताओं पर हमले की घटनाओं को छिपाने का भी आरोप लगाया।

पीएम से कहूंगी शाह पर हमेशा न करें भरोसा: ममता

राब्यू, जागरण • कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से कहेंगी कि गृह मंत्री अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत कीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन वे सबसे बड़े मीरजाफर साबित होंगे। सावधान रहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह भाजपा के कहे अनुसार काम कर रहा है? सब कुछ अमित शाह के आदेश पर हो रहा है।

एटीएम से निकलेगा राशन, पीडीएस दुकान नहीं जाना पड़ेगा

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन एटीएम से ही निकल जाएगा। वह भी 30 किलो अनाज महज 30 सेकेंड में। सुनने में यह आपको अजीब जरूर लगेगा, मगर यह हकीकत में होने जा रहा है। दरअसल, बुधवार को आयोजित मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लांच किया, जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष किया गया। इस एटीएम की विशेषता यह है कि यह बायोमीट्रिक तकनीक के माध्यम से संचालित होगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का राशन कोटा 15 किलोग्राम है तो मशीन उसे सूचित करेगी। यदि वह उस समय केवल पांच किलोग्राम राशन लेना चाहता है तो शेष राशन को वह सुविधा अनुसार बाद में ले सकता है। राज्य सरकारें एरिक्सन कंपनी से इस प्रकार के एटीएम लगाने के लिए संपर्क कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के कई शहरों में सरकार ने ये एटीएम लगवाए हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को इंडियन मोबाइल कांग्रेस में लांच राशन एटीएम • जागरण

- एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लांच किया, प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष दी प्रस्तुति
- सुविधा अनुसार कोटे का राशन ले सकेंगे, 30 सेकेंड में 30 किलो तक अनाज मिलेगा

24 घंटे उपलब्ध होगी सेवा

एरक्सिन कंपनी के अनुसार, एक मशीन की क्षमता 500 किलोग्राम तक है। बायोमीट्रिक आधार से जुड़े होने के कारण, उपभोक्ता कहीं भी अपने राशन का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी।

अब रोबोट करेगा रेलवे की सुरक्षा

एरिक्सन ने प्रधानमंत्री के सामने रोबोट की मदद से रेलवे की सुरक्षा की भी प्रस्तुति दी। यह रोबोट खास तकनीक से लैस होगा जिसमें कैमरे भी लगे होंगे।

****

गृह मंत्री अमित शाह ने जोहो पर बनाया नया ईमेल आइडी

अमित शाह ● फाइल फोटो

- गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
- जोहो भारत में विकसित तकनीकी प्लेटफार्म है

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना ईमेल पता बदल दिया है। उन्होंने स्वदेशी प्लेटफार्म जोहो मेल पर अपना नया ईमेल आइडी बना ली है। यह स्वदेशी तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है और डिजिटल आत्मनिर्भरता के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अमित शाह ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, 'नमस्ते सभी को, मैंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरा नया ईमेल पता amitshah.bjp@zohomail.in नोट करें। भविष्य में ईमेल द्वारा संपर्क करने के लिए इसी पते का उपयोग करें। जोहो पूरी तरह भारत में विकसित एक तकनीकी प्लेटफार्म है, वैश्विक साफ्टवेयर परिदृश्य को बदल रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति दे रहा है। कुछ दिन पहले, केंद्रीय रेल एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जोहो मेल अपनाया और इसे दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन साझा करने के लिए एक अच्छा मंच बताया। उन्होंने लोगों से देशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपने सभी अधिकारियों को जोहो आफिस सूट का उपयोग करने का निर्देश दिया है। सरकारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अधिकारियों को इस नए प्लेटफार्म से परिचित होना चाहिए। जोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने आभार व्यक्त किया।

औषधि निरीक्षक के पद खाली, प्रयोगशालाओं की भी कमी, कैसे हो दवाओं की जांच

- मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चों की मौतों ने राज्यों की औषधि नियंत्रण व्यवस्था की पोल खोली
- छत्तीसगढ़ में दवा की जांच की सुविधा नहीं, झारखंड में सिर्फ एक लैब, बिहार में जांच में देरी

जागरण टीम, नई दिल्ली : जहरीला कफ सीरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों ने राज्यों की औषधि नियंत्रण व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अधिकतर राज्यों में औषधि नियंत्रक का ही पद खाली है, जिन पर दवाओं की जांच करने की पूरी जिम्मेवारी होती है। राज्य लैब की कमी झेल रहे हैं। नतीजा सैंपल दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और जांच में देरी होती है।

यूपी के 13 जिलों में एक भी औषधि निरीक्षक नहीं: उत्तर प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के 109 में से 32 पद रिक्त चल रहे हैं। कई औषधि निरीक्षकों के पास दो जिलों का प्रभार है। मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, महराजगंज, देवरिया, फर्रुखाबाद, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, कासगंज सहित 13 जिले ऐसे हैं, जहां एक भी औषधि निरीक्षक नहीं हैं। इससे समझा जा सकता है कि दवाओं की जांच व नमूने लिए जाने का काम किस कदर प्रभावित हो रहा होगा। मंडल मुख्यालय वाले जिलों में दो-दो औषधि निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में एक-एक निरीक्षक ही हैं। मुरादाबाद, गोरखपुर व झांसी मंडल मुख्यालय पर भी औषधि निरीक्षक नहीं हैं।

मप्र में औषधि निरीक्षकों के 96 पदों में 79 ही पदस्थ: मध्य प्रदेश जहां पिछले एक महीने में जहरीले कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत हो गई, वहां औषधि निरीक्षकों के 96 पदों में से 79 ही पदस्थ हैं। कफ सीरप मामले के बाद यहां पदस्थ शोभित कोष्टा को निलंबित किए जाने के बाद उप औषधि नियंत्रक का एक पद रिक्त हो गया है। प्रदेश में दवाओं के सैंपल की जांच के लिए वर्ष 2024 तक एकमात्र लैब भोपाल में थी। इस वर्ष से इंदौर और जबलपुर में लैब प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में हर वर्ष सात हजार से अधिक सैंपल जांच के लिए आते हैं। 2024 में 7211 सैंपल भोपाल स्थित लैब में आए, पर क्षमता कम होने के कारण 4398 सैंपलों की जांच ही हो पाई। इनमें 51 सैंपल अमानक पाए गए।

पंजाब के पास अपनी लैब, कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री नहीं

पंजाब में सरकार के पास अपनी लैब है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ और दिल्ली की निजी लैब से भी दवाओं की जांच कराई जाती है। सरकार का दावा है कि राज्य में करीब 100 फार्मा कंपनियां हैं। सभी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों से जब भी दवा का बैच निकलता है, उसकी लैब टैस्टिंग होती है। कफ सीरप से बच्चों की मौत के बाद राज्य में कोल्ड्रिफ को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, अब तक कहीं से यह जानकारी नहीं मिली है कि यह दवा वहां बिकती भी थी।

हिमाचल में एक लैब, जहां सभी दवाओं की जांच संभव नहीं: हिमाचल प्रदेश में दवाओं की जांच के लिए औषधि निरीक्षकों के 44 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 39 ही पदस्थ हैं। बद्दी में इसी वर्ष 32 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब निर्मित की गई है। प्रदेश में दवाओं की अभी रैंडम जांच की जाती है। संदेह होने की स्थिति में उसे जांच के लिए लैब भेजा जाता है। बद्दी लैब से जांच रिपोर्ट आने में चार से पांच दिन लग रहे हैं। इसकी क्षमता कम होने से प्रदेश में बनने वाली सभी दवाओं की जांच संभव नहीं है।

बिहार में सीरप जांच के लिए अभी मंगाया जा रहा रसायन: बिहार में कफ सीरप के रसायनों की जांच की व्यवस्था तो है, पर पटना के अगमकुआं में विकसित अत्याधुनिक औषधि प्रयोगशाला में जांच के लिए आवश्यक रसायन ही नहीं हैं। प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी सह माइक्रो बायोलाजिस्ट डा. सत्येंदु सागर ने बताया कि जांच के लिए आवश्यक केमिकल की खरीद का आर्डर दिया चुका है। दो-तीन दिनों में केमिकल और नमूनों के आते ही कफ सीरपों की जांच शुरू हो जाएगी।

उत्तराखंड में लैब है, मगर जांच रिपोर्ट आने में होता है विलंब

उत्तराखंड के देहरादून में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है। यहां छह मशीनें हैं, लेकिन दवाओं की जांच रिपोर्ट आने में समय लगता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित कफ सीरप को लेकर जारी गाइडलाइन के क्रम में राज्य में औषधि प्रशासन और खाद्य संरक्षा की टीमें लगातार औचक निरीक्षण अभियान चला रही हैं। कफ सीरपों के 148 नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अब तक एक भी नमूने की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार 10 अक्टूबर से रिपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी।

झारखंड में सिर्फ एक लैब, उसमें भी स्टाफ की भारी कमी: झारखंड में दवा की जांच की ठोस व्यवस्था नहीं है। रांची में लैब है, लेकिन वहां सीमित जांच हो पाती है। सिर्फ चार आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे लैब चल रही है। जमशेदपुर समेत कई जिलों से दवाओं के कुछ नमूने जांच के लिए कोलकाता सेंट्रल लैब और गुवाहाटी क्षेत्रीय लैब भेजे गए थे, जिनमें 77 सैंपल बिना जांच के वापस लौटा दिए गए, क्योंकि वहां पहले ही ही बड़ी संख्या में नमूने जांच के लिए पड़े हैं। पूरे राज्य में औषधि निरीक्षकों के 42 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 12 पद खाली हैं। छत्तीसगढ़ में दवा की जांच की सुविधा नहीं है। यहां से नमूना जांच के लिए कोलकाता भेजा जाता है। वहां से रिपोर्ट आने में एक से तीन महीने तक लग जाते है। हालांकि, सहायक ड्रग कंट्रोल के राज्य में 20 पद हैं, जो पूरे भरे हुए हैं।

एक नजर में

भारतीय क्रिकेट टीम कहने से रोकने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 'भारतीय क्रिकेट टीम' कहने से रोकने के बीसीसीआइ को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? जो टीम हर जगह जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या यह टीम इंडिया नहीं है? अगर यह टीम इंडिया नहीं है, तो बताएं कि यह टीम इंडिया क्यों नहीं है। याचिकाकर्ता को इस तरह की याचिका दायर करने पर फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि जनहित याचिका न्यायालय के समय की सरासर बर्बादी है। (जासं)

राहुल गांधी के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बहस पूरी

वाराणसी: अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में रह रहे सिखों को लेकर दिए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को बहस पूरी हो गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने बहस आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित करते हुए 17 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है। (जासं)

अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांगी अनुमति

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अन्य वकील सुभाष चंद्रन केआर ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अनुमति मांगी है। घटना के बाद बार काउंसिल आफ इंडिया ने 71 वर्षीय राकेश किशोर का बार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। (प्रेट्र)

महादेव सट्टा एप मामले में 12 आरोपितों को जमानत

रायपुर : महादेव सट्टा एप मामले में ढाई साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद 12 आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एमएम सूदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत मंजूर की। आरोपितों में निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, निलंबित कांस्टेबल भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव, सुनील दम्मामी, अमित अग्रवाल, रितेश यादव, भारत ज्योति, विश्वजीत राय, राहुल वकटे और नीतीश दीवान शामिल हैं। (नईदुनिया)

कोर्ट से संत रामपाल को मिली बड़ी राहता

चंडीगढ़: हाई कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे संत रामपाल को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस सेठी की खंडपीठ ने रामपाल के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला रामपाल द्वारा दाखिल हलफनामे को देखते हुए किया। (राब्यू)

आंध्र में पटाखा फैक्टरी में आग से सात लोगों की मौत

रायवरम: आंध्र के बीआर आंबेडकर कोनासीमा जिले में एक पटाखा फैक्टरी में आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पुलिस को संदेह है कि दोपहर करीब एक बजे हुई यह घटना पटाखा निर्माण फैक्टरी में लापरवाही के कारण हुई। पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। शवों की जानकारी जुटाई जा रही है। (प्रेट्र)

जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया बेहद हैरान करने वाला

बच्चों की मौत भी न खोल पाई मंत्रालय की 'नींद'

नीलू रंजन ● जागरण

- शुक्रवार को दे दी थी कफ सीरप को क्लीन चिट, बाद एडवाइजरी जारी कर निश्चिंत हो गया
- तमिलनाडु की जांच में डीईजी मिलने की पुष्टि के बाद भी खानापूर्ति में जुटा रहा मंत्रालय

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरान करने वाला है। कफ सीरप से मौत की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पहले तो बच्चों को कफ सीरप देने में सावधानी बरतने को लेकर एडवाइजरी जारी कर निश्चिंत हो गया। बाद में जब तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ ब्रांड के कफ सीरप में जहरीला रसायन मिलने की पुष्टि हुई तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आनलाइन बैठक कर राज्यों को दवाइयों की जांच और निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया। मंत्रालय के अधिकारी स्वास्थ्य को राज्य सूची का विषय होने का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहला बयान शुक्रवार को जारी किया गया। बताया गया कि नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी (एनआइवी) और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) के विशेषज्ञों ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर कई ड्रग्स के सैंपल लिए। मंत्रालय ने दावा किया कि दवाओं के सैंपल की जांच में किसी में डायथीलिन ग्लाइकाल (डीईजी) नहीं मिला। यानी सभी कफ सीरप को क्लीन चिट दे दी। सीरप देने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अगले दिन शनिवार को तमिलनाडु की जांच में कोल्ड्रिफ में डीईजी मिलने की पुष्टि होने के बाद मंत्रालय में हड़कंप मच गया। एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें फिर दावा किया गया कि मध्य प्रदेश से सीडीएससीओ द्वारा लिए गए कफ सीरप के छह सैंपल में डीईजी नहीं मिला और देश के ड्रग कंट्रोलर द्वारा लिए गए 13 सैंपल में से तीन की रिपोर्ट आई है, जिनमें डीईजी नहीं है। मंत्रालय ने दावा किया कि जिन 19 सीरप के सैंपल लिए गए हैं, उनकी निर्माण इकाइयों की जांच शुक्रवार से ही की जा रही है। इसके बाद ही रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य सचिव की आनलाइन बैठक की गई। बुधवार को मंत्रालय ने बताया कि सीडीएससीओ ने कोल्ड्रिफ बनाने की कंपनी का लाइसेंस रद करने का निर्देश तमिलनाडु के ड्रग नियामक को दे दिया है। कोरोना के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय में रहते हुए अहम भूमिका निभाने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि स्वास्थ्य को राज्यों का विषय कहकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत दवाओं पर निगरानी के पूरे तंत्र की विफलता है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके अधीन आने वाली नियामक एजेंसियां भी शामिल हैं।

मरते रहे बच्चे, सोया रहा मप्र का प्रशासनिक तंत्र

नागपुर में कोल्ड्रिफ सीरप की बोतल लिए नीलेश सूर्यवंशी, जिनका तीन वर्षीय बच्चा मेडिकल कालेज में भर्ती है ● रायटर

- कलेक्टर ने सिर्फ छिंदवाड़ा में प्रतिबंध लगाया, औषधि निरीक्षकों ने सैंपल तक नहीं लिए
- छिंदवाड़ा से सैंपल हाथों-हाथ भेजने की जगह स्पीड पोस्ट से भोपाल भेजे गए, तीन दिन लगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 26 सितंबर तक आठ बच्चों की जान जा चुकी थी, इसके बाद भी छिंदवाड़ा से संदिग्ध कफ सीरप के सैंपल हाथों-हाथ भेजने की जगह परंपरागत स्पीड पोस्ट से भोपाल भेजे गए। इन्हें 283 किमी दूर भोपाल पहुंचने में तीन दिन लग गए, जबकि इन्हें छह से आठ घंटे में पहुंचाया जा सकता था।

उधर, छह बच्चों की मौत होने तक सरकारी तंत्र सोया रहा। यह माना जाता रहा कि किसी बीमारी से बच्चों की किडनी खराब हो रही है। नागपुर में बच्चों की किडनी की बायोप्सी में डीईजी मिलने के बाद तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 29 सितंबर को कोल्ड्रिफ पर प्रतिबंध लगाया। कफ सीरप के सैंपल तक नहीं लिए। चार सितंबर को पहले बच्चे की मौत के एक माह बाद छह अक्टूबर को ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटाया गया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और दो ड्रग इंस्पेक्टरों को निलंबित किया गया।

स्वास्थ्य विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहली बार उपचार करा रहे बच्चों का हालचाल जानने मंगलवार शाम नागपुर पहुंचे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डा. नरेश गुनाडे को पद से हटा दिया है। केंद्रीय औषधि मानक एवं नियंत्रण संगठन की वर्ष 2023 की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि चार वर्ष से छोटे बच्चों को कफ सीरप नहीं देने संबंधी चेतावनी बोतल के लेबल पर छपी होनी चाहिए, पर इसका पालन कोई राज्य नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि मैं भरे मन से कह सकता हूं और हम सबको लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है और कोई अपना जाता है तो कष्ट होता है।

राजस्थान में अब पेट साफ करने वाली सीरप में भी मिली गड़बड़ी

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में मुख्यमंत्री निश्शुल्क योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली खांसी की दवा से चार बच्चों की मौत और दो दर्जन से अधिक के बीमार होने के बाद अब पेट साफ करने वाली दवा में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जयपुर के सरकारी जयपुरिया अस्पताल में मरीजों को दी गई लैक्टुलोज साल्युशन सीरप में फंगस पाया गया है। इसके बाद दवा की आपूर्ति रोक दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने संबंधित दवा के बैच को जांच के लिए भेजा है। मामले की जांच के लिए डा. विनोद गुप्ता और डा. राजेंद्र वर्मा की दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जानकारी के अनुसार हाल ही में अस्पताल में पहुंचे लैक्टुलोज साल्युशन सीरप के स्टाक में फंगस जैसी गंदगी देखी गई।

दो पीढ़ियों से घर में चल रहा था नकली दवा का कारोबार, मुकदमा

बिरहाना रोड स्थित नील वाली गली में श्री लक्ष्मी फार्मा ● जागरण

जागरण संवाददाता, कानपुर: बिरहाना रोड में थोक दवा मार्केट के सामने नील वाली गली में नकली दवा बनाने व बेचने का कारोबार कई पीढ़ियों से चल रहा था। यहां से नकली दवाएं उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के साथ हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अन्य क्षेत्रों तक भेजी जा रही थीं। मंगलवार को औषधि विभाग व लुधियाना नारकोटिक्स टास्क टीम की छापेमारी में 28.85 लाख की नकदी के साथ बड़ी मात्रा में नकली दवाएं, दवा बनाने व उसकी पैकेजिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री पकड़े जाने के बाद जांच में यह बात पता चली है। औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने मेडिकल स्टोर को सील कर कलक्टरगंज थाने में आरोपित संचालक राहुल अग्रवाल व उसकी पत्नी पायल के विरुद्ध बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है।

औषधि निरीक्षक के अनुसार, दुकान से फरार होने वाला संचालक राहुल कई वर्षों से नकली दवा का काम कर रहा है। वर्ष 2004 में उसके पिता रामगोपाल अग्रवाल पर ट्रांसपोर्ट नगर में नकली दवाओं के साथ पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। एसीपी कलक्टरगंज आशुतोष सिंह ने बताया कि श्री लक्ष्मी फार्मा मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर में मानक के विरुद्ध दवाएं मिलने के मामले में आरोपित संचालक व उसकी पत्नी पर औषधियों में मिलावट, मिलावटी दवाओं की बिक्री, धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। नील वाली गली स्थित भवन के भूतल में मेडिकल स्टोर व तीसरी मंजिल पर नकली दवाएं बन रही थीं। औषधि अधिकारियों के अनुसार, मार्केट में जिस दवा की अधिक मांग रहती है, उसे नकली दवा के कारोबारी बनाकर बाजार में बेचते थे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिली पांच प्रकार की दवाओं के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता की हकीकत सामने आएगी। उधर, आरोपित संचालक की बेटी वर्तिका अग्रवाल से लुधियाना नारकोटिक्स टास्क टीम ने घंटों पूछताछ की व अपने साथ ले गई।

बिना डाक्टर के पर्चे के दवाइयों की बिक्री पर हो कठोर कार्रवाई: आइएमए

जासं, लखनऊ: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की अध्यक्ष डा. सरिता सिंह ने अपील की है कि केवल सीरप ही नहीं, कोई भी दवा बिना डाक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर से बिक्री न हो। यदि बिना चिकित्सीय सलाह के कोई फार्मेसी से दवा की बिक्री होती है तो उसके खिलाड़ी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी घटना न होने पाए।

पीड़ित व समाज केंद्रित दिशानिर्देश तय करने की याचिका हुई खारिज

- शीर्ष कोर्ट ने मौत की सजा वाले मामलों में सुनाया फैसला
- याचिका खारिज करते हुए कहा, इसमें कोई मेरिट नहीं दिखता

नई दिल्ली, प्रेट्र: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जघन्य अपराधों में मौत की सजा पाए मामलों में पीड़ितों और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश बनाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "हमें इस विविध आवेदन में कोई मेरिट नहीं दिखता।"

केंद्र सरकार ने जनवरी, 2020 में शीर्ष अदालत में यह आवेदन दायर किया था और तर्क दिया था कि वर्तमान में मौत की सजा से जुड़े दिशानिर्देश केवल अभियुक्त और दोषी-केंद्रित हैं। उसने कहा था कि न्यायालय को ऐसे मामलों में, जो 'न्यायालय के सामूहिक विवेक को झकझोर देते हैं', पीड़ितों और समाज के हितों को भी ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश तय करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मांगी थी, जिनकी याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने 2014 में मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की फांसी से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। ये दिशानिर्देश 2014 में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किए गए थे। शीर्ष न्यायालय ने जनवरी, 2020 में स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र की याचिका पर विचार करते समय शत्रुघ्न चौहान के मामले से जुड़े दोषसिद्धि और सजा के मुद्दे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 2014 का मामला अंतिम निर्णय ले चुका है क्योंकि पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिकाएं दोनों पहले ही खारिज हो चुकी हैं। केंद्र ने तर्क दिया था, 'मृत्युदंड की सजा पाए दोषी के लिए उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक उपायों का लाभ उठाने की कोई समय सीमा नहीं है।

'रेल दुर्घटनाओं में तकनीकी खामियों में वैध मुआवजा खारिज न किया जाए : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तकनीकी खामियों के कारण रेल हादसों में वैध मुआवजा खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और रेलवे दावा न्यायाधिकरण, भोपाल के उस आदेश को रद करते हुए की, जिसमें एक कथित रेल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की विधवा और बेटे को मुआवजा देने से इन्कार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार व एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि रेलवे अधिनियम के तहत कार्यवाही किसी आपराधिक मुकदमा की तरह नहीं होती, जिसमें उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है।

कारों की तस्करी मामले में अभिनेताओं के यहां ईडी के छापे

कोच्चि, प्रेट्र: भूटान से भारत में लक्जरी कारों की तस्करी के मामले में ईडी ने बुधवार को केरल और तमिलनाडु में अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल तथा कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। ईडी ने इस दौरान एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर के वाहन मालिकों, ऑटो वर्कशाप व व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कुल 17 परिसरों पर छापेमारी की गई। इनमें सुपरस्टार ममूटी से जुड़ा एक परिसर भी शामिल है जो आरोपित अभिनेता दुलकर सलमान के पिता हैं। ईडी जल्द पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज करेगी ताकि आरोपों की जांच की जा सके।

सीबीआइ ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 40 स्थानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने बुधवार को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के सिलसिले में कई राज्यों में 40 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि नौ पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनसे कथित तौर पर 4.5 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल और बंगाल में की गई। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध निरोधक निकाय आइ4सी से शिकायत मिलने पर सीबीआइ ने 15,000 से ज्यादा आइपी एड्रेस के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 40 साइबर अपराधियों का पता लगाया।

बिहार में जीटी रोड पर तीसरे दिन भी रहा महाजाम

मंगलवार को सात घंटे के महाजाम के बाद बुधवार की शाम कोलकाता-दिल्ली एनएच 19 पर शिवसागर के पास दोबारा लगे जाम में फंसे वाहन ● जागरण

- डेहरी से शिवसागर तक सात स्थानों पर चल रहा काम, 65 किमी में था जाम का प्रभाव
- अधिकारियों ने निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त डायवर्जनों के शीघ्र निर्माण का दिया निर्देश

जासं, डेहरी आनसोन (रोहतास): बिहार में कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (जीटी रोड) पर एक हफ्ते में तीसरे दिन भी महाजाम रहा। जाम के कारण कई राज्यों के हजारों यात्री परेशान हुए। बच्चे दूध के लिए बिलबिलाते दिखे। मालूम हो कि सोमवार की बाद फिर मंगलवार की सुबह लगभग सात घंटे तक डेहरी आन सोन से शिवसागर के बीच 32 किमी तक गाड़ियां टस से मस नहीं हुई, जिसका प्रभाव औरंगाबाद व कैमूर की ओर लगभग 65 किमी तक देखा गया। महाजाम से बुधवार को दिन में राहत मिली, लेकिन फोरलेन सड़क को सिक्सलेन बनाने और फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति के कारण शाम होते ही वाहनों की गति पर दोबारा ब्रेक लग गया। चार-पांच किमी की दूरी पर वाहनों की कतार लगती रही। गत दस दिनों में तेज वर्षा के कारण एनएच पर कुम्हऊ गेट, ताराचंडी धाम व चेनारी मोड़ के पास पुल-पुलिया निर्माण स्थलों के डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इससे भी यातायात पर प्रभाव पड़ा है। डेहरी से शिवसागर के बीच सात स्थानों पर कार्य चल रहा है। जाम की समस्या को देख बुधवार को एनएचएआइ के पदाधिकारियों ने डायवर्जनों का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। एनएचएआइ प्रशासन ने राजमार्ग पर फ्लाईओवर एवं सिक्स लेन निर्माण कार्य का काम एक कंपनी को दिया है। फ्लाईओवर एवं मरम्मत का कार्य 30 सितंबर 2024 तक ही पूरा किया जाना था परंतु 50 प्रतिशत तक ही पूरा किया जा सका है।

सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए बढ़ा जान का खतरा

जितेंद्र शर्मा ● जागरण

सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए यात्रियों का आंकड़ा

वर्ष	मारे गए कुल यात्री	मारे गए पैदल यात्री	प्रतिशत में
2016	1,50,785	15,746	10.44
2017	1,47,913	20,457	13.83
2018	1,51,417	22,656	14.96
2019	1,51,113	25,858	17.11
2020	1,31,714	23,483	17.83
2021	1,53,972	29,124	18.9
2022	1,68,491	32,825	19.5
2023	1,72,890	35,221	20.4

नई दिल्ली: देश के विभिन्न हिस्सों में बन रहे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा सकती हैं, लेकिन यह विकास इस तरह आंखें मूंदकर किया जा रहा है कि पैदल यात्रियों के चलने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए चिंता जताते हुए यदि विस्तृत आदेश दिया है तो उसका आधार वे आंकड़े भी हैं, जो बताते हैं कि पैदल यात्रियों के लिए सड़कों पर जान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह भी अचंभित करने वाला है कि इनकी मौत के लिए भारी वाहनों से अधिक दोपहिया वाहन जिम्मेदार हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण पैदल यात्री सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगरा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन द्वारा उठाए गए विषय का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने पैदल यात्रियों की सड़क हादसे में मृत्यु पर आंकड़ों सहित तुरंत समुचित कदम उठाने का सुझाव भी दिया है। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,890 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 35,221 यानी 20.40 प्रतिशत पैदल यात्री थे। मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर पैदल यात्रियों की मृत्यु दोपहिया वाहनों के कारण हुई है। कुल मृत पैदल यात्रियों में 28.26% की जान दोपहिया वाहन, 24.78% की मृत्यु कार, टैक्सी, वैन आदि के कारण, जबकि 15.23% की जान ट्रक-लारी और 6.03 प्रतिशत की मृत्यु बस की टक्कर से हुई। कोर्ट ने कहा कि इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि संबंधित प्राधिकरण पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित चलने और सड़क पार करने का स्थान सुनिश्चित करें। पैदल यात्रियों की मृत्यु के लिए फुटपाथ की कमी को बड़ी वजह बताया।

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

न्याय में समय

न्यायपालिका को लेकर इन दिनों चल रही चर्चाएं विचारणीय हैं। इनमें एक बड़ी शिकायत है कि मुकदमों के निपटारे में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे अत्यंत दुखद स्थिति बताया है और इसके लिए कुछ अधिवक्ताओं की आलोचना की है। न्यायाधीशों को यह शिकायत है कि कई अधिवक्ता न्यायालय की निष्पक्ष सहायता नहीं करते हैं। वाकई यह बात बहुत हद तक सही है कि पूरी तैयारी के अभाव में मुकदमे तारीख-दर-तारीख खिंचते चले जाते हैं। अदालतों में लगातार कार्य का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। यह रोचक बात है कि लगे हाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक दिन के कार्यों का ब्योरा भी दिया है। एक दिन में अदालत में 91 नए मामले आए, जबकि 182 सूचीबद्ध मामले थे और छह विविध प्रकार के आवेदन थे। इन तमाम मामलों को देखने के लिए अदालत के पास तय समय महज 300 मिनट है। वैसे भी उच्च न्यायालय तक वही मामले पहुंचते हैं, जो जटिल किस्म के होते हैं, अर्थात उन्हें जल्दी निपटाना आसान नहीं होता है।

इस पूरे मामले में एक बात सकारात्मक है कि जरूरत से ज्यादा समय लेने या समय बर्बाद करने वाले वकीलों की न्यायालय ने आलोचना की है। न्यायपालिका में यह उम्मीद की जाती है कि वकील किसी भी मुकदमे को ऐसे रखेंगे कि न्यायाधीशों को किसी फैसले तक पहुंचने में सुविधा होगी। क्या यह सही नहीं है कि अनेक वकील मामलों को जल्दी निपटाने के बजाय बहस या कागजी खानापूर्ति का लंबा रास्ता अख्तियार करते हैं? क्या यह सही नहीं है कि ज्यादातर न्यायालयों में अधिकतर मुकदमों में केवल तारीख देकर काम निपटा दिया जाता है? तारीख लेने का काम कौन करता है, यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर दोनों पक्ष के वकील तैयारी के साथ आएं, तो जल्दी सुनवाई होती है। यह हमारे यहां सांविधानिक व्यवस्था है कि किसी अपराधी की दलीलों को भी तफ्सील से सुना जाता है। इसलिए आमतौर पर बड़े अपराधियों के वकील भी बड़े होते हैं, जो मुकदमे को जल्दी न्याय तक पहुंचने से रोकने के तमाम जतन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अदालतों की यह कमी आम लोगों की समझ में नहीं आती है। अंग्रेजों के जमाने से आज तक लोग यही मानते हैं कि अदालत का चक्कर बुरा होता है। न्याय पाने में पीढ़ियां खप जाती हैं। अनेक आरोपी बाहर घूमते पाए जाते हैं, तो अनेक निरपराध लोग जेल में पड़े रहते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनेक वकीलों से जुड़ी एक कमी पर उंगली रखी है, ठीक उसी तरह से तमाम कमियों को निशाना बनाने की जरूरत है।

जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की एक कमी पर उंगली रखी है, ठीक उसी तरह से तमाम कमियों को निशाना बनाने की जरूरत है। यह समझने वाली बात है कि इंसाफ जब वक्त पर नहीं मिलता है, तब अदालतों पर लोगों का इकबाल भी कम होता है। अनेक वकीलों के ही नहीं, बल्कि उनके प्रभाव में आने वाले अन्य लोगों के मन में भी अदालत के प्रति सम्मान कम होता है। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर समग्रता में सोचने की जरूरत है। अपने देश की अदालतों में 11 करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 63 लाख से ज्यादा और सर्वोच्च न्यायालय में 86 हजार से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई चल रही है। लाखों लोग न्याय के इंतजार में बैठे हैं। ऐसे में, पूरी न्यायपालिका में हर किसी को यह सोचना होगा कि वह अपने पूरे समय का सदुपयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए कैसे कर सकता है? शायद फिजूल के विवादों से बचने का एक बड़ा समाधान यही है कि अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखा जाए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 09 अक्तूबर, 1950

कुष्ठ निवारण का काम

भारत को जिन महाव्याधियों से लड़ना है और मुक्ति प्राप्त करनी है, उनमें कुष्ठ को मुख्य स्थान देना होगा। कुष्ठ छूत से फैलने वाला रोग है। वह घोर यंत्रणादायक तो है ही, रोगी के अंगों को विकृत बना देता है।

जब रोग आगे बढ़ जाता है तो रोगी हाथ-पांव से बेकार हो जाता है और दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता है। तीर्थ स्थानों में हम कुष्ठ रोगियों की भारी भीड़ देखते हैं। यात्री, जो तीर्थों में पुण्य कमाने जाते हैं, कुष्ठ रोगियों की भीड़ को देखकर घृणा से मुंह मोड़ लेते हैं और दया के नाम पर दो-चार पैसे उनकी ओर फेंककर अपनी संतप्त आत्मा को संतोष दे लेते हैं। किन्तु जैसा कि टंडन जी ने इस वर्ष की कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है, रास्तों में पड़े हुए लूले-लंगड़े और उनमें कुष्ठ रोगी भी शामिल हैं, समाज की दुर्बलता का परिचय देते हैं। उनको चिकित्सा सदनों और आश्रमों में रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज के अन्तःकरण को कुष्ठ रोगियों का निराश्रित अवस्था में पड़े रहना असह्य होना चाहिए। कुष्ठ रोगियों की हमारे बीच में मौजूदगी हमारी मानवीय भावनाओं को जबर्दस्त चुनौती है। यदि हम पहले की भांति उनकी उपेक्षा करते जायेंगे, तो अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य को लजायेंगे।

भारत में कुष्ठ रोग की व्यापकता की अब तक जो सरसरी जांच-पड़ताल की गई है, उसके अनुसार हमारे यहां कुष्ठ रोग से प्रभावित 10 लाख रोगी होंगे। इनमें से दो लाख रोगी ऐसे हैं, जो अपने रोग को दूसरों तक फैलाने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। इनमें से आज चिकित्सा सदनों में रखने की व्यवस्था केवल 14 हजार रोगियों के लिए है, अर्थात् प्रति 15 रोगियों में से एक को हम चिकित्सालयों में रख पा रहे हैं। चिकित्सालय कुष्ठ रोगियों की सेवा और सहायता करने का जो काम कर रहे हैं, उसकी हर हालत में प्रशंसा ही करनी पड़ेगी, किन्तु जब तक अन्य कुष्ठ रोगी अपने रोग को फैलाने की स्थिति में रहेंगे, तब तक कुष्ठ चिकित्सा-सदनों का काम अधूरा ही रहेगा। वे एक ओर से गड्ढे को भरने की कोशिश करेंगे और दूसरी ओर से गड्ढा और भी गहरा होता जायेगा और इस प्रकार कुष्ठ रोग की समस्या कभी हल नहीं होगी। कुष्ठ चिकित्सा के जो केन्द्र देश में स्थापित हैं, उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से रोगी पहुंचते हैं।

नई सुबह का इंतजार करता मणिपुर

जी जी द्विवेदी | मेजर जनरल (सेवानिवृत्त)

यहां स्कैन करें

प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद कुछ सकारात्मक गतिविधियां हुई हैं, मगर हमारी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' तभी फलीभूत हो सकती है, जब पूर्वोत्तर स्थिर और कलह से मुक्त हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर की मणिपुर यात्रा से वहां के लोगों को यह संकेत गया है कि इस अशांत प्रदेश में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मणिपुर 3 मई, 2023 से ही अशांत है, जब हाईकोर्ट ने इंफाल घाटी में बसे बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने का आदेश दिया था। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसे अल्पसंख्यक 'कुकी-जो' समुदायों ने इस आदेश को जमीन पर अपने अधिकारों और दूसरे अवसरों के लिए खतरा मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया।

इस मुद्दे को लेकर भड़की हिंसा में वहां 260 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए, जिन्हें 280 राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी गहराने के कारण राज्य दो भागों में विभाजित हो गया है। मैतेई घाटी क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, तो कुकी चुराचांदपुर, सेनापति और तेंगनौपाल जैसे पहाड़ी जिलों में हावी हैं। दोनों ही पक्षों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं और वे अपने-अपने इलाकों में मजबूत किलेबंदी कर चुके हैं। मणिपुर एक युद्धक्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जहां एक बफर जोन बनाकर और सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिये हालात को संभाला गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कुकी समुदाय अपने लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश मांग रहा है। मणिपुर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। जनता के बीच आम धारणा यही है कि सब कुछ तयशुदा हुआ और केंद व राज्य, दोनों ही सरकारें मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के बजाय फौरी निदान पर जोर देती रही हैं। इस वर्ष फरवरी से ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। हालांकि, हिंसा का स्तर वहां कम हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाल ही में, कुकी-जो बागी समूहों द्वारा 'ऑपरेशन निलंबन' समझौते पर दोबारा दस्तखत करने जैसी कुछ सकारात्मक बातें हुई हैं। हालांकि, मैतेई समुदाय के संरक्षक संगठन 'सीओसीओएमआई' ने इस समझौते की यह कहकर आलोचना की है कि यह सशस्त्र कुकी-जो संगठनों को वैधता प्रदान करता है। एनएच-2 से नाकेबंदी हटाए जाने की भी खबरें थीं, हालांकि, कुकी संगठनों ने इन खबरों का खंडन कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का अपने भाषण में जिक्र किया और स्थानीय शासन को मजबूत करने का आश्वासन भी दिया। पर चूंकि राजनीतिक पुनर्गठन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए यह स्पष्ट है कि केंद्र का दृष्टिकोण राज्य का विभाजन किए बिना, जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और लोगों में विश्वास बहाल करना है। वर्तमान में, मैतेई समाज ऐसे किसी भी कदम को लेकर संशय में है, जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकता है और इसके विभाजन का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर के नौजवानों की भूमिका पर जोर दिया, क्योंकि मणिपुर में खेल-संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और यह जातीय भेदभाव से परे होने का एहसास कराती है। उन्होंने यहां महिला सशक्तीकरण की भी खूब सराहना की।

अपनी संक्षिप्त यात्रा में प्रधानमंत्री ने बातचीत और सुलह की पुरजोर अपील की और इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए शांति अनिवार्य शर्त है। चुराचांदपुर और इंफाल के अपने दो भाषणों में उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि लोगों, विशेषकर युवाओं की आकांक्षाएं इस हिंसा की काली छाया में दबने न पाएं। हिंसा के कारण विस्थापित परिवारों के लिए उन्होंने 7,000 आवास निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने 3,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज और राहत कोष के लिए 500 करोड़ रुपये भी दिए। सड़क, रेल और आईटी जैसे संपर्क साधनों को एकता का सूत्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के भौतिक और राजनीतिक विभाजन को पाटने का प्रयास किया। राज्य में एक अरब डॉलर से भी अधिक के निवेश वाली बड़ी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने हिल्स पर स्थानीय शासन को मजबूत करने की मांग पर भी आश्वासन दिया। हालांकि, मैतेई समाज ऐसे किसी भी कदम को लेकर संशय में है, जो मणिपुर के विभाजन का कारण बन सकते हों।

यह विडंबना है कि अंतर्निहित सामाजिक विभाजन के कारण मणिपुर में हिंसा का एक इतिहास रहा है। मगर मैतेई-कुकी वर्तमान संघर्ष ने जटिलताओं को और बढ़ा दिया है। इस विभाजन को पाटना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह समाज के हर तबके में गहरे तक उतर गया है और बुनियादी सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहा है। यहां तक कि संस्थाओं का भी ध्रुवीकरण हो गया है। नतीजतन, राहत और पुनर्वास के उपाय भी पक्षपात करने के आरोपों के घेरे में आ गए हैं। यदि बफर जोन और अस्थायी राहत शिविरों की मौजूदा स्थिति बनी रही, तो मणिपुर के स्थायी रूप से खंडित होकर अलग-अलग इकाई में बदल जाने का खतरा है।

सीमावर्ती राज्य होने के कारण मणिपुर के सुरक्षा संबंधी निहितार्थ भी हैं, क्योंकि अशांत पड़ोस के साथ-साथ इस क्षेत्र में चीन का साया मंडरा रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी व घुसपैठ के कारण स्थानीय जन-सांख्यिकी पर बढ़ता दबाव अतिरिक्त चुनौती पेश करते हैं। विदेशी ताकतें भी सक्रिय हैं। ऐसे में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की सुरक्षा की समीक्षा आवश्यक है। परंपरागत रूप से देखा जाए, तो मैतेई समुदाय कभी विभाजन का समर्थक नहीं रहा है, वहीं कुकी भी राज्य में सामाजिक सौहार्द के साथ रहने के पक्षधर रहे हैं। ऐसे में, मौजूदा तनाव के माहौल से ऊपर उठकर आंतरिक मतभेदों को आम सहमति से सुलझाया जाना चाहिए।

इस राज्य को सहानुभूति और मदद वाले हाथ से दलदल से निकलने के लिए व्यावहारिक नीति की आवश्यकता है। वर्तमान में, दोनों समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए नागरिक समाज को आगे आना होगा। समस्या के समाधान के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना एक सकारात्मक कदम होगा। हमारी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' तभी फलीभूत हो सकती है, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थिर और आंतरिक कलह से मुक्त हो। शांति की राह अवश्य कठिनाइयों से भरी है, मगर मणिपुर को नए सवेरे का इंतजार है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

संचार क्रांति के करामाती दौर में भी डटकर खड़ा डाकघर

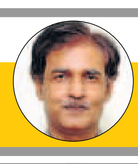

अरविंद कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

संचार और सूचना-क्रांति ने पूरी दुनिया में डाकघरों को निस्तेज किया है। चिट्ठियां आखिरी सांसें ले रही हैं। फिर भी भारत में डाकघर अपनी उपयोगिता कायम रखे हुए हैं। गौर करने की बात है कि भारत में ही विश्व में सबसे अधिक 1,64,972 डाकघर हैं, जिसमें से 1,49,478 डाकघर ग्रामीण अंचलों में हैं। हमारा हर डाकघर औसतन 7,753 व्यक्तियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। विश्व में इस समय डाकघरों की संख्या करीब 6.40 लाख है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर देशों में डाकघर कम होते जा रहे हैं, पर भारत में बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए डाकघर आज भी खुल रहे हैं।

हर साल 9 अक्तूबर को विश्व डाक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व डाक संघ की मातृ संस्था 'जनरल पोस्टल यूनियन' 9 अक्तूबर, 1874 को स्थापित हुई थी। भारत 1 जुलाई, 1876 को इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। वैसे, आधुनिक रूप में 1 अक्तूबर, 1854 को स्थापित भारतीय डाक सुख-दुख में लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा और एक दौर में यह संचार क्षेत्र की धड़कन बन गया। डाक, बैंकिंग, जीवन बीमा और मनीऑर्डर या रिटेल सेवाओं के जरिये इसका लोगों के साथ जुड़ाव कायम रहा। पहले चिट्ठियां, मनीऑर्डर, शुभकामना संदेश, तार व परीक्षाफल की सूचनाएं डाक के माध्यम से मिलती थीं। आज वह बात नहीं, पर डाक सेवाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया से लेकर आर्थिक व वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में डाक विभाग ने खुद को बदला है।

देश में डाकघर खातों की संख्या करीब 35.67 करोड़ है, जिसमें अकेले 26 करोड़ बचत खातों में 12.68 लाख करोड़ रुपये की रकम जमा है।

भारतीय डाक का गौरवशाली अतीत रहा है। 1727 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में पहला डाकघर स्थापित होने के कई साल बाद बंगाल प्रेसीडेंसी में 1774 में, मद्रास (अब चेन्नई) में 1786 और बॉम्बे (मुंबई) प्रेसीडेंसी में 1793 में जीपीओ खुला। डाक सेवाओं में एकरूपता के तहत भारतीय डाकघर अधिनियम साल 1837 में बना, फिर व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम सन् 1854 में अस्तित्व में आया। भारतीय डाक के इतिहास में 1 जुलाई, 1968 एक अहम पड़ाव बना, देश में डाकघरों की संख्या एक लाख हो गई। एक लाखवां डाकघर बिहार में खुला था।

संचार क्रांति से पहले डाक विभाग पर सबसे अधिक बोझ चिट्ठियों का होता था। लेकिन चिट्ठियां कम होने लगीं, तब भी यह विभाग बना रहा। आज भी 576 करोड़ से अधिक डाक सामग्रियां आ रही हैं और कुरियर सेवा की चुनौतियों के बावजूद स्पीड पोस्ट में भारतीय डाक की बाजार हिस्सेदारी 40 फीसदी बनी हुई है। इसकी वित्तीय सेवाएं आज भी मजबूत हैं। वित्तीय सेवाओं में डाकघरों ने आम जनता का भरोसा बरकरार रखा है। समय के साथ यह बदला भी है और अब देश के किसी भी सीबीएस डाकघर में लोग अपने खाते से लेन-देन कर सकते हैं। एटीएम, ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं ने डाकघरों को आधुनिक बैंकों की श्रेणी में ला दिया है। डाकघरों में निवेश सबसे आसान और सौ फीसदी सुरक्षित हैं। बैंकिंग क्षेत्र की तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय डाकघर के खातों की संख्या करीब 35.67 करोड़ है, जिसमें अकेले 26 करोड़ बचत खातों में 12.68 लाख करोड़ रुपये की रकम जमा है। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की गति भी बहुत तेज है।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग की कई लंबित योजनाओं को साकार करने में खास रुचि ली है। वह इस विभाग को शक्ति और कमजोरी, दोनों अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वह संचार राज्यमंत्री का दायित्व पहले निभा चुके हैं। डाक विभाग के कायाकल्प के साथ साल 2029 तक इसे लाभ में लाने पर उनका विशेष जोर है। हालांकि, यह एक जटिल काम है, क्योंकि डाक विभाग का आर्थिक मोर्चा चुनौतियों भरा है।

डाक विभाग के राजस्व व्यय का 89.3 प्रतिशत वेतन, भत्ते और पेंशन मद में खर्च होता है। शेष 11 फीसदी स्थापना और अन्य व्यय हैं। सरकार भारतीय डाक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक बनाने के लिए डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने, बीमा व अन्य सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ रही है। जाहिर है, इन सबसे भारतीय डाक एक बड़ी शक्ति फिर से बन सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कहां है आपकी सरहद

जिम्मेदारी का नाम लेते ही एक सवाल सामने आता है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में आपको भिन्न-भिन्न विषयों और व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा, तब आप किन-किन बातों की जिम्मेदारी लेंगे? दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी लेने के संबंध में भी बहसें अविश्वसनीय रूप से लंबी खिंचती जाती हैं- कौन बिजली का बटन दबाए? थाली-कटोरी कौन साफ करे? कौन पानी भरे?

इसी तरह, एक रात शंकरन पिल्लै और उनकी पत्नी के बीच दरवाजे का ताला कौन लगाए, इस विषय पर विवाद छिड़ गया। काफी देर की बहस के बाद दोनों एक फैसले पर पहुंचे- दोनों में से जो पहले एक भी लफ्ज बोलेगा, वही उठकर ताला लगाएगा।

कई सालों से साथ रहने के कारण एक-दूसरे की ताकत और कमजोरी से दोनों ही वाकिफ थे। यदि शंकरन मुंह खोलकर 'खाना खिला दो' कहते या उनकी पत्नी 'खाने के लिए उठो' कहतीं, तो ताला लगाने की जिम्मेदारी आ जाती, इस डर के मारे दोनों भूखे रहकर मौन व्रत का पालन करते रहे। आधी रात को कुछ बदमाशों की नजर खुले घर पर पड़ी, तो वे अंदर घुस गए। हॉल में बैठे दंपति को देखकर डर गए। लेकिन ये दोनों बिना मुंह खोले, चुपचाप तमाशा देखते रहे। यह देखकर चोरों को हैरानी भी हुई। जो भी चीजें हाथ लगीं, बटोर लीं। मेज पर रखा भोजन भी खा लिया। मगर इन दोनों के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी।

चोरों में से एक ने साहस बटोरकर शंकरन पिल्लै की पत्नी के कान से कर्णफूल उतार लिए। इस पर भी उस नारी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह देखकर अगला बदमाश हैरत में आ गया। उसने पास पड़ा चाकू उठाया और शंकरन पिल्लै की मूंछें उड़ाने की तैयारी करने लगा। अब तक काठ के देवता की भांति बैठे शंकरन पिल्लै लाचार होकर चिल्लाए, 'अच्छा ठीक है, मैं ही उठकर ताला लगाता हूं।' शंकरन पिल्लै की तरह गर्दन पर चाकू पहुंचने के बाद ही जिम्मेदारी स्वीकार करनी है क्या? यह अक्ल पहले आई होती, तो जीवन सुधर न जाता?

भूकंप में गुजरात के कई मकान धराशायी हो गए। सुनामी में तमिलनाडु के समुद्र तट पर कई मकान बह गए। ऐसे मौकों पर क्या आप ये सब विपदाएं किसी और के साथ घट रही हैं, ऐसा मानकर चुप रहते? आपके अंदर जो मानवता है, वह प्रत्येक घटना का पुरजोर उत्तर देती है। जिम्मेदारी की भावना इसी को कहते हैं। आपके अंदर ही नहीं, हर आदमी के अंदर जब यह भावना मौजूद रहती है, तब प्रश्न ही नहीं उठता कि आप जिम्मेदार हैं या नहीं? सवाल यही है कि क्या आपके ध्यान में मैं जिम्मेदार हूं, ऐसी भावना है? आपने अपनी उत्तरदायित्व भावना के लिए कहां सरहद तय कर रखी है?

आपके अंदर जो मानवता है, वह प्रत्येक घटना का उत्तर देती है, इसे ही जिम्मेदारी की भावना कहते हैं। हर आदमी में जब यह भावना मौजूद हो, तब प्रश्न ही नहीं उठता कि आप जिम्मेदार हैं या नहीं?

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

गैरी कास्परोव | पूर्व शतरंज चैंपियन

मैं एक ऐसे देश (रूस) से हूं, जहां गुंडों द्वारा बंदूक की नोक पर लोगों को सड़क पर घसीटना आम बात है। इस बात की चिंता किए बगैर कि लोग आपको उन्मादी कहेंगे, हमें इसके विरुद्ध लड़ना होगा।

अनुलोम-विलोम
ग्रीन पटाखे

पटाखों के बिना भला कैसी दीपावली

हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हरित पटाखे छोड़ने की इजाजत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। यह एक रवैया सा बनता जा रहा है कि जो भी हिंदू पर्व-त्योहारों के उत्साह और रौनक से जुड़ी चीजें हैं, उनका पर्यावरण के खिलाफ घोषित कर दो। कभी जल-प्रदूषण के नाम पर नदी किनारे किसी आयोजन पर रोक लगाने की मांग उठने लगती है, तो कभी पेयजल संकट के नाम पर होली को सूखी होली मनाने की दलीलें पेश की जाने लगती हैं। अब दीपावली पर पटाखे न छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही हरित पटाखे चलाने की इजाजत दी थी और फिर उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में, स्वाभाविक ही हिंदू चिढ़ जाते हैं। होना तो यह चाहिए था कि सरकारें पटाखे व रंग जैसी चीजों को अधिक सुरक्षित और अनुकूल बनाने पर विशेष शोध करातीं, ताकि लोगों की भावनाओं और त्योहारों का उल्लास अक्षुण्ण रहता, मगर अब एक ही रास्ता दिखता है। हर मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चले जाओ और वहां से रोक हासिल कर लो। क्या गाड़ियों के चलने से प्रदूषण नहीं फैलता? फैक्टरियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण नहीं होता या निर्माण कार्यों से प्रदूषण नहीं होता? तो क्या सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए?

रामाज्ञा पंडित, टिप्पणीकार

मेरी बेटी चौथी कक्षा में थी। एक दिन स्कूल से लौटकर बोली- पापा, हम आवाज करने वाले पटाखे नहीं चलाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ। पता चला, स्कूल में टीचर ने पूरी क्लास को समझाया है। अगर मैंने डांट-डपटकर रोका होता, तो उस समय वह मजबूरी में भले मान जाती, लेकिन उसके मन में गुस्सा भरता जाता। यही हुआ है, पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर। शिक्षित करने, पटाखा इंडस्ट्री को रेगुलेट करके कम प्रदूषण वाले पटाखे बनवाने आदि की जगह कोर्ट से प्रतिबंध का ऑर्डर लाया गया, जिसकी हैसियत अब एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं बची है। पटाखे प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं हैं, लेकिन कुछ लिबरल साथियों, गैर-सरकारी संगठनों और कुछ मूर्ख अधिकारियों ने दीर्घकालिक योजनाओं की जगह पटाखों पर ताली बजाऊ भाषणों को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लिया। नतीजा- प्रतिक्रिया। एक पक्ष को मौका मिला इसे हिंदू विरोधी घोषित कर देने का। काले बाजार में घटिया पटाखे बन-बिक रहे हैं। प्रदूषण एक बड़ा मसला है, ताली बजाने से हल नहीं होगा, पर इसके आगे बढ़ने को न तो लोग तैयार हैं, न सरकार।

अशोक कुमार पांडेय, लेखक

प्रदूषण की मारी दिल्ली को और न सताएं

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देना चाहती है। हालांकि, इसकी मंजूरी के लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा रखी है। पर्यावरणविद् व विशेषज्ञ दिल्ली सरकार के ताजा रुख से नाराज हैं और कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

दीपावली का त्योहार सर्दियों की शुरुआत के साथ ही आता है। इसके बाद के दिनों में दिल्ली शहर का क्या बुरा हाल होता है, जगजाहिर है। लोगों को सांस लेने तक में कठिनाई महसूस होने लगती है। हालात इस कदर बदतर हो जाते हैं कि कभी शहर की गाड़ियों को सड़कों से कम करने के लिए सम-विषय फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, तो कभी स्कूल बंद करने पड़ते हैं। पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा खेतों में जलाई जाने वाली पराली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग होने लगती है। ऐसे में प्रदूषण का एक बड़ा और गैर-जरूरी कारक पटाखे को जलाने की अनुमति मांगना हास्यास्पद और गैर-जिम्मेदाराना ही माना जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पटाखों के साथ इसके पक्ष में दिए जा रहे बयानों पर भी रोक लगे।

ग्रीन पटाखों के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे एकदम बेतुके और तथ्यों से परे हैं। कहा जा रहा है कि ये पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रदूषण नहीं बढ़ाते। जबकि अध्ययनों से यह बात आम हो चुकी है कि परंपरागत पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों में प्रदूषक तत्व मात्र 30 प्रतिशत कम होते हैं। जाहिर है, इन पटाखों से 70 प्रतिशत प्रदूषण फैलता ही है। बाजार में उपलब्ध ज्यादातर तथाकथित ग्रीन पटाखों में वही प्रतिबंधित रसायन पाए गए हैं, जो पारंपरिक पटाखों को जहरीला बनाते हैं, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट, लेड (सीसा), आर्सेनिक आदि। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट में पाया गया था कि ये 'ग्रीन' कहे जाने वाले पटाखे, प्रतिबंधित पटाखों से अलग नहीं पहचाने जा सकते हैं और वे जाली लेबल के साथ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। ऐसे में, अगर अनुमति दी जाती है, तो अधिकारियों के लिए यह पता लगाना नामुमकिन होगा कि कौन ग्रीन पटाखे जला रहा है और कौन नहीं? दिल्ली सरकार की यह कोशिश असल में पराली जैसी चीजों पर लगे प्रतिबंधों से पूरी तरह विरोधाभासी है और राजधानी को प्रदूषणकारी वातावरण में वापस लाने जैसी है। यह चंद लोगों को खुश करने के लिए राजधानी के बुजुर्गों-बच्चों और बीमार लोगों की सेहत से खिलवाड़ है।

अद्वैत कृष्ण, छात्र

निवेश के हुनर से सबकी तरक्की

तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक आकर्षक करियर विकल्प बनकर उभरा है। कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए ढेरों संभावनाएं भी हैं, जिन्हें फाइनेंस और बिजनेस की जानकारी है। डिग्री के साथ तकनीकी दक्षता और बाजार की समझ हो, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। कैसे? बता रही हैं श्वेता राकेश

सीफए इंस्टीट्यूट के 2025 ग्रेजुएट आउटलुक सर्वे के अनुसार भारत में 38 फीसदी स्नातकों की करिअर प्राथमिकता फाइनेंस है, वहीं एक अन्य सर्वे के अनुसार 43 फीसदी बीबीए छात्र फाइनेंस में करिअर चाहते हैं। दरअसल परंपरागत मौकों के साथ ही फाइनेंस सेक्टर में कुछ नए करिअर भी समय के साथ शामिल हुए हैं, जो देश और विदेश में मौकों की राह खोलते हैं। ऐसा ही एक विकल्प है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का।

साल 2022-23 के दौरान लगभग 20 साल के युवा अप्पल्ला साईकिरण की खूब चर्चा हुई। वह अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐप की वजह से मशहूर हुए। साईकिरण की तरह कई युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि यह एक पूर्णकालिक करियर है। हालांकि आईटुआई फंडिंग.कॉम के को-फाउंडर वैभव पांडे की मानें, तो इस क्षेत्र में प्रतियोगिता भी खूब है। पर, उनके अनुसार, 'चुनौतियां हैं, तो मौके और आय भी शानदार है।'

क्या होता है काम

पारंपरिक बैंकिंग से अलग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों, सरकारों और संस्थाओं को पूंजी जुटाने (जैसे आईपीओ, बॉन्ड), विलय-अधिग्रहण और जटिल वित्तीय मामलों में सलाहकारिता, योजना, रणनीति, बिक्री और कानूनी नियमों के अनुपालन संबंधी काम देखते हैं।

क्या हो राह

ग्रेजुएट होना जरूरी है। फाइनेंस, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्नातक या बीए (इकोनॉमिक्स) या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इस क्षेत्र में आ सकते हैं। कई निवेश बैंक स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। वैभव पांडे के अनुसार, 'इस क्षेत्र में आना है, तो एमबीए करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अधिकतर कंपनियां मैनेजमेंट कॉलेजों से कैंपस प्लेसमेंट में उम्मीदवारों का चयन करती हैं। अगर एमबीए का रास्ता नहीं लेना चाहते, तो कॉमर्स या फाइनेंस की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ सर्टिफिकेशन और संबंधित स्किल लेकर इंटर्न या एंट्री लेवल पर एनालिस्ट जैसे पदों से शुरुआत करनी होगी। समय के साथ अनुभव से उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं।'

इसमें चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए), फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट (एफआरएम) आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

कुछ एआई स्किल्स सीखें

- मैक्रोस, वीबीए कैपीलोट जैसी एआई फीचर्स सीखें। पायथन के साथ पांडांज, नमपाइ और मैटप्लॉटलिब जैसे टूल्स सीखें। ये डाटा एनालिसिस और ग्राफ बनाने में के लिए बेहद उपयोगी हैं। इनकी मदद से फाइनेंस डाटा के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन बनाना सीखें।

यहां मिलेंगे अवसर

एक अनुमान के अनुसार देश में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की 300 से ज्यादा कंपनियां हैं। आमतौर से फिनटेक कंपनियां फंडिंग और स्ट्रैटेजी में विशेषज्ञों की मांग करती हैं। बिग 4 फर्म्स यानी डेलॉइट, केपीएमजी, पीडब्लूसी और अर्न्स्ट ऐंड यंग कंसल्टिंग कंपनियां इस क्षेत्र की नामी कंपनियां हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रिस्क एनालिस्ट, ट्रेजरी मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं।

विदेश में भी खुलेंगी राहें

फाइनेंस, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों की जानकारी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल और पायथन जैसे तकनीकी कौशल और सीएफए जैसे अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट वैश्विक स्तर पर मान्य हैं। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां विदेश में इंटर्नशिप के अवसर देती हैं। लिंक्डइन, एलुमनी नेटवर्क के जरिए नेटवर्किंग भी मददगार होती है।

सर्टिफिकेशन के प्रमुख मंच

- एनएसई एकेडमी **nseacademy.com/CIIB**
- बीएसई इंस्टीट्यूट **bsebti.com**
- द वॉल स्ट्रीट स्कूल **thewallstreetschool.com**
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स **nism.ac.in**
- एनआईएफएम, नई दिल्ली **nifm.in**

कुछ ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स

- फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग (कोर्सेरा)
- कॉरपोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट (एडेक्स)
- एमबीए इन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस (अपग्रैड)
- एआई पावर्ड एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कोर्स लिंक्डइन लर्निंग से कर सकते हैं।

शुरुआती वेतन

- अपग्रैड के अनुसार नए स्नातक औसतन 5 लाख रुपये सालाना कमाते हैं। जैसे-जैसे पेशेवर आगे बढ़ते हैं, अपने अनुभव और फर्म के आधार पर औसतन 18.5 लाख रुपये सालाना तक अर्जित कर सकते हैं।

विशेषज्ञ की राय

फाइनेंस व मार्केट रिसर्च का ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा भी है। गणित, अकाउंटिंग, एडवांस्ड एक्सेल, डाटा रिसर्च जैसे तकनीकी कौशल के साथ कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन जैसे सॉफ्ट स्किल भी होने चाहिए। फाइनेंशियल कंपनी में मार्केट रिसर्च, डाटा इंटरप्रिटेशन में इंटर्नशिप करते हैं, तो इंडस्ट्री की समझ बढ़ती है। एनएसई पोर्टल से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फाइनेंस में बीबीए हैं, तो 3 से 4 लाख और बीकॉम हैं, तो 5 से 6 लाख रुपये सालाना कमा सकते हैं। **-डॉ.संजीव कुमार आचार्य**, सीनियर करिअर काउंसलर

जॉब/करिअर

- दिल्ली पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है।
  कुल पद : 2861
  अंतिम तिथि: 16 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : आयोग की वेबसाइट **ssc.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन करें।
- दिल्ली सबऑर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।
  कुल पद : 1180
  अंतिम तिथि: 16 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : बोर्ड की वेबसाइट **dsssb.delhi.gov.in** पर जाएं।
- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना में पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
  कुल पद : 1799
  अंतिम तिथि: 26 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **bpssc.bihar.gov.in** पर लॉगइन करें।
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची (झारखंड) में अप्रेंटिस की रिक्तियां निकली हैं। इसके तहत फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन आदि ट्रेड में भर्तियां होंगी।
  कुल पद : 1180
  अंतिम तिथि: 24 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **centralcoalfields.in** पर जाना होगा।
- कर्मचारी चयन आयोग ने कॉन्स्टेबल ड्राइवर (पुरुष) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मदवारों से आवेदन मांगे हैं।
  कुल पद : 737
  अंतिम तिथि: 15 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : आयोग की वेबसाइट **ssc.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
  कुल पद : 702
  अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट **btsc.bihar.gov.in** पर जाएं।
- स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
  कुल पद : 7565
  अंतिम तिथि: 21 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **ssc.gov.in** पर लॉगइन करें।
- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर आवेदन का अवसर है।
  कुल पद : 368
  अंतिम तिथि: 14 अक्तूबर 2025
  आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **rrbahmedabad.gov.in**

(**नोट :** आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

विदेश में पढ़ने के लिए देने होंगे कुछ टेस्ट

एक्सपर्ट टिप्स

आशीष आदर्श, करिअर काउंसलर

- **मैं इस वर्ष ग्रेजुएशन पूरा करूंगी। विदेश से मास्टर्स करना चाहती हूं। टॉफेल में अच्छा स्कोर करना बेहतर होगा?** **-कात्यायनी**

भारत से जो भी स्टूडेंट्स विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको एक ऐसा इंग्लिश कोर्स पूरा करना जरूरी है, जो यह प्रमाणित करे कि आप विदेश जाकर अंग्रेजी में अपना कोर्स सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी तक टॉफेल यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज लोकप्रिय रहा है। आईईएलटीएस यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को भी विश्व भर के अनेक उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए मान्यता दी गई। इस कड़ी में एक और इंलिश परीक्षा का नाम जुड़ गया है - सेल्ट यानी द सीक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यदि आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या सिंगापुर जा रहे हैं, तो आईईएलटीएस या सेल्ट को चुन सकते हैं और यदि आपकी योजना लंदन, अमेरिका या कनाडा जाने की है, तो टॉफेल या सेल्ट में बैठने की तैयारी करें। आईईएलटीएस का संचालन ब्रिटेन के ब्रिटिश काउंसिल द्वारा किया जाता है, जबकि टॉफेल को अमेरिका स्थित एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस यानी ईटीएस आयोजित करता है। परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको आईईएलटीएस, सेल्ट या टॉफेल की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

- **किसी बैंक से एजुकेशनल लोन किस प्रकार मिल सकता है? मार्गदर्शन करें।** **-प्रह्लाद कुमार**

भारतीय बैंक भारत से लेकर विदेश में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कम दरों पर एजुकेशनल लोन देते हैं। आप कुल तीन कैटेगरी में एजुकेशनल लोन प्राप्त कर सकते हैं :

- अधिकतम 4 लाख रुपये तक का लोन चाहते हैं, तो आपको न तो किसी गारंटर की आवश्यकता है और न ही किसी कोलेटरल यानी गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति की आवश्यकता है। यदि आपका दाखिला किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में हो गया है, तो इस आधार पर बैंक आपको एजुकेशनल लोन देने पर विचार कर सकता है।
- यदि आप 4 लाख से अधिक और 7.5 लाख रुपये से कम तक का लोन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आर्थिक रूप से संपन्न किसी एक गारंटर की आवश्यकता है। कोलेटरल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- देश या विदेश में पढ़ने के लिए 7.5 लाख रुपये से अधिक एजुकेशनल लोन के लिए एक ओर आपके पास एक आर्थिक रूप से संपन्न गारंटर होना चाहिए, वहीं लोन ली गयी राशि के लिए कोई कोलेटरल भी प्रस्तुत करना होगा। यदि विदेश में भी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहें, तो इसी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। कॉलेज से सिलेक्शन लेटर, अप्रूवल लेटर और फीस डिटेल्स लेकर बैंक में संपर्क कर सकते हैं।

एक अच्छा रिज्यूमे आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है, लेकिन आत्मविश्वास न हो, तो यहां हर सवाल चुनौती लगने लगता है।

चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखें

टिप्स

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में सिर्फ 32 फीसदी नौकरी चाहने वाले खुद को इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार मानते हैं, जबकि शुरुआती पेशेवरों में यह संख्या 29 फीसदी तक कम हो जाती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी के बावजूद आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही हो, तो उसे कैसे दूर करें-

कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास

- **इंटरव्यू को टेस्ट न समझें :** खुद को साबित करने की चिंता छोड़कर, सामने वाले से ईमानदार और संतुलित बातचीत करने पर ध्यान दें। इससे आत्मसंदेह खत्म होगा तो आत्मविश्वास अपनेआप बढ़ेगा।
- **ऑनलाइन या ऑफलाइन :** ऑनलाइन इंटरव्यू में तकनीकी तैयारी और कैमरे के सामने सहजता जरूरी है, जबकि ऑफलाइन इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज और समय की पाबंदी अहम होती है। दोनों ही स्थितियों में मॉक इंटरव्यू आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं।
- **इंटरव्यू में भी सीख :** हर इंटरव्यू खुद को समझने और बेहतर करने का मौका देता है। परिणाम चाहे जो हो, इसे सीखने और विकास का अवसर मानें।

छोटी सफलताओं पर गौर करें : इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट होना पहला महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने जैसा है। इसे अपनी सफलता की तरह लें। इससे आप आत्मविश्वास के साथ आगे की तैयारी कर सकेंगे।

शारीरिक हाव-भाव सुधारें : हाथों को क्रॉस करना, आंखें मिलाने से बचना, बोलने में लड़खड़ाना आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं। आई-कॉन्टेक्ट बनाए रखें, सीधा और सहज बैठें और साफ शब्दों में बात करें। ये छोटे-छोटे बदलाव बिगड़ी बात भी संभाल सकते हैं।

एआई से तैयारी में मदद : Interviewsby.ai, Apna.co, Huru.ai जैसे एआई-आधारित टूल इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद करते हैं। यह उम्मीदवारों को असली इंटरव्यू जैसा अनुभव देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

आप भी पूछें सवाल : इंटरव्यू सिर्फ सवाल-जवाब का दौर नहीं है, बल्कि कंपनी के बारे में जानने-समझने का मौका भी है। अंत में अपनी भूमिका से जुड़े सवाल पूछना आपकी गंभीरता और तैयारी दिखाता है। **फीचर डेस्क**

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा, ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है।

वृष : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। बातचीत में संतुलित रहें। लंबे समय के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सुस्वादु भोजन में रुचि बढ़ सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक : मन में निराशा और असंतोष हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आय वृद्धि होगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। क्रोध से बचें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी।

मीन : अपनी भावनाओं को वश में रखें। संयत रहें। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पिता का साथ प्राप्त होगा।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

09 अक्तूबर, गुरुवार, **शक संवत् :** 17, आश्विन सौर शक 1947, **पंजाब पंचांग :** 24, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम :** 16, रबि-उल्सानी, 1447, **विक्रमी संवत :** कार्तिक कृष्ण तृतीया रात्रि 10.55 मिनट तक, भरणी नक्षत्र रात्रि 08.03 मिनट तक। वज्र योग रात्रि 09.32 मिनट तक, पश्चात सिद्धि योग। चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 01.24 मिनट तक उपरांत वृष राशि में। **सूर्य दक्षिणायन।** शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.39 मिनट से रात्रि 10.55 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरे बेडरूम में बिस्तर सही दिशा में है। रंग भी सही है, फिर भी मुझे नींद ढंग से नहीं आती है। कृपया कोई समाधान बताएं। – श्यामा सहाय, मुजफ्फरपुर

- आपका बेड का सिरहाना दक्षिण दिशा में है जो कि सही है। बेडरूम का रंग हल्का क्रीम है, यह भी ठीक है। यदि आपके बेड के पीछे कोई खिड़की है तो ये समस्या का बड़ा कारण हो सकता है।
- आपके सिर के पीछे कोई लोहे की अलमारी है, तो यह भी नींद की समस्या देता है।
- आपके पैरों के सामने कोई दरवाजा है तो उसका भी असर नींद पर पड़ेगा।
- यदि पैरों के सामने कोई बड़ी या ऊंची अलमारी है, तो भी नींद प्रभावित होगी।

वर्ग पहेली : 8113

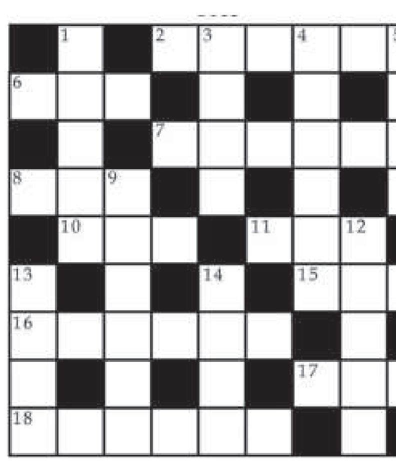

बाएं से दाएं
2. प्रभाव करना; काम करना (3,3)
6. मानदंड; स्तर (3)
7. जांचना; पहचान करना (3,3)
8. लोहे को सोने में बदलने वाला तथाकथित पत्थर; स्पर्शमणि (3)
10. अंधकार; अंधेरा; अज्ञान; पाप (3)
11. आकर्षक; मुग्ध करने वाला; मोहजनक; सुंदर (3)
15. डाली; पतली शाखा (3)
16. इश्तिहार देने वाला; प्रचार करने का इच्छुक; विज्ञापन देने वाला (6)
17. ओट; घेरा; प्राचीर; भीत (3)
18. आकुंठित करना; लज्जायुक्त करना; शर्मसार करना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. लगातार; निरंतर; सतत; हमेशा; सदैव (5)
3. अपने नाम पर आई हुंडी मान्य करना; स्वीकार करना (4)
4. कनकनाने का भाव; कनकनापन; चिड़चिड़ाहट (6)
5. सूंड; तुलसी (4)
9. बाद का; समय के बाद; समय के उपरांत (6)
12. बुलवाना; सुनवाना; संदेशा भिजवाना (5)
13. ज्यों का त्यों; बिना उलट फेर का; जो व्याकुल न हो; शांत; व्यवस्थित (4)
14. भलमनसाहत; शिष्ट व्यवहार; सात्विक व्यवहार (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8112

1 प	2 ह	रे	3 दा	र	■	4 त	■	5 क
■	ता	■	म	■	6 बु	नि	या	द
7 आ	शा	8 ज	न	9 क	■	क	■	म
रा	■	ल	■	था	■	■	10 हा	नि
ध	■	11 न	शा	क	र	12 ना	■	का
13 ना	ती	■	■	र	■	यि	■	ल
क	■	14 आ	■	15 ना	16 भ	का	17 ट	ना
18 र	ण	क्षे	त्र	■	धु	■	ल	■
ना	■	प	■	19 दे	र	कि	ना	र

सुडोकू : 8095

* आसान

7								9
		9	8		4	5		
3			7		2			8
		7	5		3	2		
	3			2			5	
		8	6		9	4		
1			9		6			4
		4	2		8	1		
8								5

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3०3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8094

3	6	5	2	7	1	8	4	9
7	1	9	8	4	5	3	2	6
4	8	2	9	6	3	1	7	5
6	4	1	7	2	9	5	3	8
2	5	7	3	1	8	9	6	4
8	9	3	6	5	4	7	1	2
1	3	4	5	9	2	6	8	7
9	2	6	1	8	7	4	5	3
5	7	8	4	3	6	2	9	1

संक्षिप्त खबरें

बरसात का पानी भरने से मोटर खराब

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली एनचेटे सोसाइटी में मंगलवार देर रात हुई बारिश का पानी पंप हाउस में भर गया। इससे पंप हाउस की मोटर खराब हो गई। लोगों का आरोप है कि हल्की बारिश में भी पंप हाउस में जल भराव हो जाता है। कई बार मोटर खराब हो चुकी है, लेकिन रखरखाव प्रबंधन ध्यान नहीं रखा जाता है। सोसाइटी में रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रखरखाव प्रबंधन की तरफ से उनकी सुविधाओं में कटौती की जा रही। मंगलवार रात शाम में हुई तेज बारिश का पानी पंप हाउस में भर गया। साथ बेसमेंट में लीकेज की समस्या हो गई है। बुधवार सुबह मोटर चलाने के लिए कर्मचारी पहुंचे तो वहां पर पानी भरा हुआ था। इससे मोटर खराब हो गई। उन्हें ठीक करने के लिए भेजा गया है। बाद में प्रबंधन ने किराये की मोटर से आपूर्ति की गई। कई बार एनबीसीसी के अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

ऑटो पार्ट्स की दुकान से लाखों का सामान चोरी

नोएडा। फेज वन थानाक्षेत्र स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान से चोर लाखों रुपए के पुर्जे, लैपटॉप तथा सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर चोरी कर ले गए। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया दिल्ली के रहने वाले उत्सव जैन ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उनकी सेक्टर-16 ऑटो मार्केट में न्यू एसजे इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान है। वह एक सितंबर की शाम को दुकान बंद कर अपने घर गए। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्हें शटर का ताला टूटा मिला। दुकान से क्लच प्लेट, ब्रेक पैड बेरिंग कार के अन्य पार्ट्स और लैपटॉप गायब था। उन्होंने जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालनी चाहिए तो पता चला कि चोर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पीड़ित की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब खंगाला गया तो घटना के समय दो संदिग्ध घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखे। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पड़ोसी पर किशोरी को भगा ले जाने का आरोप

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलपुर गांव में किराये के मकान में रहनी वाली किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तुगलपुर गांव में 15 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ किराये पर रहती है। उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि किशोरी शुक्रवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। परिजनों का आरोप है कि कि पड़ोस के एक घर में किराये पर रहने वाला अभय कुमार किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम किशोरी की तलाश में जुटी है।

पड़ोसी दंपति पर मारपीट करने का आरोप

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कस्बे में रहने वाली महिला ने पड़ोसी दंपति और उनके बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उनके पति के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कस्बे के बाल्मीकि मोहल्ले में रहने वाली महिला सुनीता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने पड़ोस में रहने वाले सुभाष, उनकी पत्नी सुनीता और बेटे विशाल पर बिना वजह गाली-गलौज करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

बंदरों के हमले से दहशत में लोग

गाजियाबाद। गोविंदपुरम इलाके में बंदरों की दहशत लगातार बढ़ रही है। आएदिन बंदरों के काटने के मामले होने से लोगों में दहशत का माहौल है। बुधवार को गोविंदपुरम के पार्क में एक युवक पर बंदरों ने हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह भाग कर जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्कों में बंदर झुंड बनाकर रहते हैं। इस कारण दहशत का माहौल रहता है। स्थानीय निवासी नवाब और कपिल गुप्ता ने बताया कि निगम और वन विभाग में से कोई भी बंदर नहीं पकड़ रहा है। लोगों ने बंदरों को पड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है।

मिल से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ हंगामा

मोदीनगर। मोदीनगर स्थित मोदी चीनी मिल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर सपा नेताओं ने तहसील में बुधवार को हंगामा किया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा के जिलाध्यक्ष सतेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर सुबह 11 बजे तहसील में पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने बताया कि मोदी शुगर मिल की चिमनी प्रदूषण कर रही है। मिल के आसपास स्थित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एसडीएम को ज्ञापन देते हुए सपा कार्यकताओं ने प्रदूषण निगरानी समिति और नियमों का पालन कराने का मांग की। एसडीएम ने जांच कराकर कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया है। इस दौरान सचिन दीक्षित, दिनेश प्रधान, प्रमोद, रविंद्र, राकेश शर्मा आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पार्लर जाने के लिए निकली युवती लापता

मोदीनगर। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी से युवती संदिग्ध हालात में लापता हो गई। परिवार ने कॉलोनी निवासी एक युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी छह अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से बोलकर निकली थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन नहीं मिली। परिवार ने कॉलोनी के ही रहने वाले युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, युवती के पिता की तरफ से कॉलोनी निवासी अभिषेक के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके आधार पर पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है।

कूड़ा डालने का विरोध करने पर महिला से मारपीट

मोदीनगर। मोदीनगर स्थित गांव सीकरी खुर्द में घर के सामने कूड़ा डालने का विरोध करने पर मारपीट कर महिला का हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव सीकरी खुर्द निवासी गीता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 29 सितंबर को सफाईकर्मी नाली की सफाई करने के बाद कूड़ा उसके घर के बाहर छोड़ दिया। उसके पूछने पर सफाईकर्मी ने बताया कि उनके पड़ोसी के कहने पर कूड़ा यहां किया गया है। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी घर से बाहर आया और महिला के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। आरोपियों ने महिला का हाथ तोड़ दिया और भविष्य में दोबारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर गांव निवासी झाब्बर, पप्पू और अनुज के खिलाफ मोदीनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

फैक्ट्री बेचने का झांसा देकर 16 लाख हड़पे

मोदीनगर। मोदीनगर में स्थित एक फैक्ट्री बेचने के नाम पर दो लोगों से 16 लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव कादराबाद निवासी अरुण कुमार नेहरा की तरफ से मोदीनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें उसने बताया कि बागपत बडौत की शिक्षक कॉलोनी निवासी सत्येंद्र सोलंकी मोदीनगर में सारा रोड पर फैक्ट्री है। सत्येंद्र सोलंकी ने जमीन सहित फैक्ट्री बेचने के लिए अरुण से बातचीत की। जिस पर दोनों के बीच 20 लाख रुपये में सौदा हुआ। एग्रीमेंट के दौरान अरुण और उसके दोस्त आदेश त्यगी निवासी मेरठ ने आठ-आठ लाख रुपये के चेक सत्येंद्र को दिए। चार लाख रुपये बैनामा के दौरान देना तय हुआ। आरोप है कि इसके बाद आरोपी बैनामा करने से मुकरने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपी ने 11 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया।

शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 3.26 करोड़ की ठगी, तीन गिरफ्तार

- इस मामले में पहले ही 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी
- गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 10वीं पास हैं और लखनऊ और उन्नाव के निवासी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सन्नी कुमार, दुर्गेश कुमार (दोनों निवासी लखनऊ) और विकास कुमार (निवासी उन्नाव) के रूप में हुई है। यह गिरोह रेट फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी का हवाला देकर लोगों को निवेश के बदले भारी लाभ का झांसा देता था।

घटना की जानकारी 12 जून को पीड़ित द्वारा थाना साइबर क्राइम, नोएडा में दी गई थी। शिकायतकर्ता सेक्टर-27, नोएडा का निवासी है, जिसे फर्जी निवेश स्कीम में फंसाकर 3.26 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित बैंक खातों को तत्काल फ्रीज किया और जांच शुरू की।

पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी सन्नी कुमार ने पीड़ित के खाते से 23 लाख रुपये प्राप्त कर अपने साथी विकास को दिए। विकास ने इस राशि का कुछ हिस्सा दुर्गेश और अन्य साथियों में बांट दिया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 10वीं पास हैं और लखनऊ और उन्नाव के निवासी हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यह गैंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहकर भोले-भाले निवेशकों को फंसाता था।

साइबर क्राइम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संस्था से निवेश के नाम पर प्राप्त प्रस्ताव की सत्यता अवश्य जांचें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जा सकती है।

एमिटी विश्वविद्यालय में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा, नोएडा

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत एमिटी विश्वविद्यालय में आज निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एमिटी विश्वविद्यालय के डिबेट डिसिप्लिन क्लब द्वारा किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन डिबेट डिसिप्लिन क्लब की अध्यक्षा डॉ. महिमा गुप्ता और एमिटी विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण उप-डीन डॉ. लक्ष्मी अहूजा ने किया। इस अवसर पर दोनों शिक्षाविदों ने महिला सशक्तीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।

डॉ. महिमा गुप्ता ने कहा कि मिशन शक्ति का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम करना, उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और समाज में उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों में महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। डॉ. लक्ष्मी अहूजा ने अपने संबोधन में कहा कि एमिटी विश्वविद्यालय में सदैव छात्र-छात्राओं को महिलाओं के सम्मान के संस्कार सिखाए जाते हैं।

मकान मालिक की लापरवाही से पेंटर की करंट लगने से मौत

पायनियर समाचार सेवा, नोएडा

जेवर थाना क्षेत्र के मुकीमपुर सिवारा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर पुताई करते समय पेंटर को वहां से गुजर रहे बिजली के तार से करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गयी। पेंटर के भाई की शिकायत पर मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस घटना की जांच कर रही है। जेवर के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात को मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भाई देवदत्त सात अक्टूबर को अपने साथियों के साथ मुकीमपुर गांव के रहने वाले टीटू के मकान में पेंट करने के लिए गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके भाई और उसके अन्य साथी पुताई का काम कर रहे थे तभी मकान मालिक टीटू ने कहा कि उसके मकान की छत और छज्जे की पुताई कर दो। देवदत्त और उसके साथियों ने कहा कि वहां से 11 हजार वोल्ट की लाइन गुजर रही है और बिजली बंद करने के बाद ही पुताई होगी। शिकायत के अनुसार, इस पर टीटू ने कहा कि उन्होंने बिजली बंद करवा दी है। इसके बाद देवदत्त और उसके साथियों ने पुताई का काम शुरू कर दिया। इसी बीच छज्जे पर पुताई करते समय वहां से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की तार से देवदत्त को करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसे उपचार के लिए जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर टीटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वादी संवाद दिवसः पुलिस की जनसरोकार आधारित पहल को मिल रहा जनसमर्थन

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण	
नगर जोन	99 वादी
ट्रांस हिण्डन जोन	73 वादी
ग्रामीण जोन	95 वादी
कुल वादी संख्या	267

नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 'वादी संवाद दिवस' का आयोजन आज जिले के सभी थानों पर किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त गाजियाबाद जे. रविंदर गौड़ के निर्देशन में सम्पन्न हुआ।

यह जनोन्मुखी पहल प्रत्येक बुधवार को कमिश्नरेट क्षेत्र के सभी थानों पर आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य है झ वादी और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत करना, पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, और न्याय प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना।

वादी संवाद दिवस के दौरान सभी थानों पर उन वादियों को आमंत्रित किया गया जिनके मामले अभी विवेचनाधीन हैं झ जैसे एफआईआर, एनसीआर एवं गुमशुदगी से जुड़े प्रकरण। इन वादियों को उनके प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया गया और उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर देते हुए उन्हें संतुष्ट किया गया।

कार्यक्रम के दौरान संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने-अपने सर्किल के थानों में मौजूद रहे और संवाद प्रक्रिया की निगरानी की।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के अनुसार, वादी संवाद दिवस एक जन-सरोकार आधारित नवाचार है जिसका उद्देश्य है कि कोई भी वादी अपने केस की स्थिति को लेकर अंधेरे में न रहे। इस पहल से जनता में न्याय प्रक्रिया पर विश्वास और पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति पारदर्शिता बढ़ रही है।

34 वर्षीय युवक को बदमाशों ने मुंह में पिस्टल ठूंसकर मारी गोली, इलाके में दहशत का माहौल

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक खौफनाक हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। 34 वर्षीय आसिफ की सरेराह तीन बदमाशों ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी कि हर कोई सन्न रह गया। घटना सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास की है, जहां स्कूटी से घर लौट रहे आसिफ को हमलावरों ने घेर कर पहले मुंह में पिस्टल ठूंसकर गोली मारी, फिर चेहरे पर दो और गोलियां दाग कर मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात को आसिफ स्कूटी से अपने घर लौट रहा था, तभी तीन युवकों ने उसे रोका। पहले दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद एक हमलावर ने पिस्टल सीधे आसिफ के मुंह में ठूंस दी और गोली चला दी। गोली उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। गोली लगते ही आसिफ स्कूटी से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने उसके चेहरे पर दो और गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर हथियार लहराते हुए पैदल ही फरार हो चुके थे। वारदात के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का मानना है कि यह मामला आपसी रंजिश या साजिश का हो सकता है।

मृतक आसिफ के परिवारवालों ने बताया कि उसकी दो शादियां थीं। पहली पत्नी अर्शी डासना में रहती थी, वहीं दूसरी पत्नी जूही के साथ आसिफ रफीकाबाद थाना क्षेत्र के वेव सिटी इलाके में किराए के मकान में रहता था। परिजनों का दावा है कि जूही ने साजिश रचकर आसिफ की हत्या करवाई है। मृतक के छोटे भाई अनवर ने मसूरी थाने में दूसरी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार अब जूही की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

एसीपी लिपि नगाइच ने बताया कि आसिफ का आपराधिक इतिहास रहा है। वह नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था और मसूरी समेत कई थानों में उस पर पांच मुकदमे दर्ज थे। करीब एक साल पहले वह ड्रग्स के मामले में जेल गया था और 7 महीने पहले ही रिहा होकर बाहर आया था।

वहीं, डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि मृतक को कितनी गोलियां लगीं। जांच में सभी एंगल पर काम किया जा रहा है। दो टीमें बनाकर हत्यारों की तलाश की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस बर्बर हत्या के बाद सिकरोड़ा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

हत्या के मामले में पूर्व पार्षद को उम्र कैद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने साल 2004 के एक हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व पार्षद और उसके एक साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 नवंबर 2004 को सिहानी गेट पुलिस थाने में विजय पाल की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में विजय ने आरोप लगाया गया था कि उसके भाई नरेश (42) की राम नगर कॉलोनी स्थित उसके कार्यालय के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और भतीजा जितेंद्र घायल हो गया था। नरेश को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि जितेंद्र ने होश में आने के बाद पुलिस को बताया कि बसपा के पूर्व पार्षद मनीष पंडित और उसके सहयोगी मनोज कुमार उर्फ फौजी ने गोली चलाई थी। जितेंद्र ने बताया था कि गोली चलाने से पहले पंडित ने नरेश से कहा था, तुम्हारी वजह से मैं चुनाव हार गया। यह बात उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़े गए अपने चुनाव हारने का जिक्र करते हुए कही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों में दोषी ठहराया और उम्र कैद तथा 35-35 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई। इस बीच, नरेश के बड़े भाई जोगेंद्र सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया, गोलीबारी की घटना में हमें देर से न्याय मिला है। मनीष पंडित से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। यह हमला पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ था, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार मुन्नी का समर्थन किया था, जबकि पंडित बसपा से चुनाव लड़ रहे थे।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर लगेगा स्वदेशी मेला, स्थानीय उद्यमियों को मिलेगा मंच

10 से 16 अक्टूबर तक लगेगा 'स्वदेशी मेला प्रदर्शनी 2025', लगेंगे 70 स्टॉल

- तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बैठक आयोजित कर दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपद में 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तरह ही प्रदेश के प्रत्येक जनपद में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेला आयोजित किया जाना है। इसी क्रम में जनपद गाजियाबाद में स्वदेशी मेला प्रदर्शनी का आयोजन 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रामलीला ग्राउंड, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद में किया जा रहा है।

इस मेले का उद्देश्य प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकें। साथ ही दीपावली के महापर्व के अवसर पर आम जनता को स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी का अवसर प्राप्त होगा।

मेले में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों, वित पौषित इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य उत्पादकों के लिए कुल 70 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मेले में शासन की विभिन्न जन-उपयोगी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण, संस्कृति विभाग और युवा कल्याण विभाग की ओर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

इस संबंध में उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि स्वदेशी मेला स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन के अनुसार, इस मेले में बड़ी संख्या में आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जा रहे है ताकि नागरिकों को सुविधाजनक अनुभव प्राप्त हो सके।

बैठक में बनी तैयारियों की रूपरेखाः स्वदेशी मेला प्रदर्शनी की तैयारियों के संबंध में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने उद्योग निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, अग्निशमन सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति, यातायात नियंत्रण और जनसुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी, जिसके तहत ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर सूर्यबली मौर्य को, अग्निशमन सुरक्षा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल को, साफ-सफाई, मोबाइल शौचालय और पेयजल व्यवस्था के लिए सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह को, सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए मुख्य अभियंता विद्युत वितरण मंडल प्रथम श्री पवन अग्रवाल को तथा विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विभाग गाजियाबाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि मेले का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों और उद्यमियों को मेले की जानकारी दी जाए और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जाए।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 9 अक्टूबर 2025

बिहार से परे

बिहार चुनाव की गूंज

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के साथ, बिहार एक बार फिर चुनावी उन्माद में डूब गया है। राज्य में दो चरणों में, 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार में कोई भी चुनाव मुद्दों से मुक्त नहीं होता, लेकिन इस बार चुनाव आयोग (एउ) की भूमिका ही सवालों के घेरे में है। राज्य सूचना भंडार पोर्टल के माध्यम से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विवाद ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भाजपा का पक्ष लेने का आरोप लगाया है - यह आरोप राजनीतिक दलों और गैर-राजनीतिक तरीके से काम करने के लिए बनी संवैधानिक संस्थाओं के बीच गहरे अविश्वास को दशार्ता है। अपने अनूठे इतिहास और जातीय समीकरण के साथ बिहार भारत का एक राज्य भर नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक मिजाज का एक सूक्ष्म रूप है।

बिहार के मतदान के तरीके से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश क्या सोच रहा है। जहाँ विपक्षी दल बेबुनियाद आधारों पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर एकजुट हो रहे हैं, वहीं पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ खास नहीं किया है और अपने बचाव में अस्पष्ट और अविश्वसनीय रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, चुनाव आयोग लोगों के मतदान के अधिकार और चुनाव में उनकी भागीदारी का संरक्षक होता है, लेकिन इस समय इसकी विश्वसनीयता खतरे में है।

लाखों मतदाताओं - खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों (जिन्हें अक्सर विपक्ष का वोट बैंक कहा जाता है) - के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के आरोपों से आक्रोश फैल रहा है और चुनाव आयोग पर ही चुनावी हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने अब तक संदेह दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया है। इस बीच, बिहार में चुनाव शुरू होने में बस एक महीना बाकी है और वहाँ पहले से ही काफी राजनीतिक गतिविधियाँ देखी जा रही हैं - नए गठबंधन आकार ले रहे हैं और कई नए खिलाड़ी भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

लेकिन मूल रूप से यह जातिगत गणित है। जातिगत राजनीति बिहार में बहुत पहले से ही हावी रही है, हालाँकि भाजपा और आरएसएस ने इसमें अपनी पैठ बना ली है, लेकिन उन्हें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। भाजपा के लिए, बिहार संसदीय सीटों का खजाना है, और दिल्ली में मजबूत बने रहने के लिए उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा, हालाँकि अभी राज्य में उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव भीड़ खींचने वाले नेता बनकर उभरे हैं, और हाशिये पर खड़ी कांग्रेस, राहुल गांधी की बुलेट रैलियों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार कैसे वोट डालता है। अपने विविध सामाजिक ताने-बाने और जटिल जातीय समीकरणों के साथ, यह राज्य एक अनोखे राजनीतिक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, जहाँ जातीय समीकरण और हिंदुत्व के प्रभाव एक बार फिर टकरा सकते हैं और परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करेंगे।

इसलिए, परिणाम जो भी हों, इस चुनाव को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी पर एक फैसले के रूप में देखा जाएगा। भाजपा की जीत को मोदी के करिश्मे और नीतियों और आरएसएस के बढ़ते सामाजिक प्रभाव की पुष्टि के रूप में देखा जाएगा; हार को क्षेत्रीय प्रतिरोध के पुनरुत्थान और लोकतांत्रिक बहुलता की पुनः पुष्टि के रूप में देखा जाएगा।

टाली जा सकती थी करूर में भगदड़

भारत की राजनीतिक रैलियों के इतिहास में सबसे बड़ी भगदड़ में 18 महिलाओं और 10 बच्चों सहित 41 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह भगदड़, जिसने दर्जनों लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए, केवल एक स्थानीय आपदा नहीं थी, इसने एक अमिट राष्ट्रीय निशान छोड़ा है।

अनुराग ठाकुर
लेखक, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं।

करूर से आई दुखी परिवारों और रैली स्थल पर बिखरी बची हुई चप्पलों की तस्वीरें हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेंगी। 27 सितंबर को टीवीके रैली में जो कुछ हुआ, वह एक रोकी जा सकने वाली मानवीय त्रासदी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा गठित आठ सदस्यीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) तथ्य-खोजी समिति के सदस्य के रूप में, मैंने प्रशासनिक लापरवाही, खुफिया विफलता और भीड़ की बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूर्ण अवहेलना के विनाशकारी परिणामों को अपनी आंखों से देखा। भारत की राजनीतिक रैलियों के इतिहास में सबसे बड़ी भगदड़ में 18 महिलाओं और 10 बच्चों सहित 41 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह भगदड़, जिसने दर्जनों लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए, केवल एक स्थानीय आपदा नहीं थी; इसने एक अमिट राष्ट्रीय निशान छोड़ा है जिसके लिए गंभीर, व्यवस्थित जवाब की आवश्यकता है।

प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राज्यों, दलों और संसद के दोनों सदनों के मेरे सहयोगी शामिल थे; हमारा उद्देश्य ऐसी भयावह घटना का कारण जानना, यह कैसे हुआ, इसकी स्पष्टता, जवाबदेही और ऐसी रैलियों के नियमों में सुधार के लिए संभावित कदम उठाना था ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। जब वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में और भाजपा, शिवसेना और टीडीपी के प्रतिनिधियों वाला हमारा प्रतिनिधिमंडल करूर पहुंचा, तो हमें उम्मीद थी कि हमें जवाब मिल जाएगा। इसके बजाय, हमें नौकरशाही की खामोशी और परेशान करने वाले खुलासे का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन का हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करने से इनकार करना अभूतपूर्व और बेहद परेशान करने वाला था। सार्वजनिक सेवा में अपने सभी वर्षों में, मैंने जवाबदेही से इतनी बेशर्मी से बचने की कोशिश कभी नहीं देखी। हम घायलों, शोक संतप्त लोगों, पहले प्रतिक्रिया देने वालों और अधिकारियों से बात करने और यह समझने के लिए करूर गए कि क्या गलत हुआ।

शोक संतप्त परिवारों, घायल पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के साथ हमारी बातचीत ने व्यवस्थागत विफलता की एक भयावह तस्वीर पेश की। एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया कि वह आयोजन स्थल, जो एक संकरी सार्वजनिक सड़क थी, मात्र 19 फीट चौड़ा था, जबकि अभिनेता से नेता बने विजय का प्रचार वाहन 12 फीट चौड़ा था, जिससे 30,000 लोगों की भीड़ के लिए हिलने-डुलने या भागने की कोई जगह नहीं बची। आपदा का गणित साफ था, फिर भी बुनियादी सुरक्षा मानदंडों की परवाह किए बिना अनुमति दे दी गई। यह एक ऐसा स्थल था जो इतनी बड़ी आपदा का इंतजार कर रहा था। भीड़ के उमड़ने की गतिशीलता, भीड़ का घनत्व, भीड़ के कुचलने के कारण धीरे-धीरे ढहना, भीड़ का व्यवहार मनोविज्ञान, प्रवेश और निकास प्रवाह दर, और अभिनेता विजय के घटनास्थल पर प्रवेश करने के समय उमड़ी भीड़, और भीड़ प्रबंधन और खुफिया जानकारी की ऐसी ही अन्य गतिशीलता को ऐसी रैली की अनुमति देते समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

करूर के अस्पताल में शोकाकुल परिवारों का दृश्य मुझे परेशान करता है। ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। वे आम नागरिक थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जो अभिनेता के प्रशंसक प्रतीत होते थे, जो सिर्फ एक सेलिब्रिटी से नेता बने व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुकता से आए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने एक महत्वपूर्ण क्षण में सत्ता में व्यवधान को याद किया, जिससे दहशत और बढ़ गई। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण माँगा कि बिजली क्यों और किसके आदेश पर काटी गई। भीड़ नियंत्रण उपायों, पुलिस और मार्शलों की अपर्याप्त तैनाती और आयोजन स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की तैयारी को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गईं।

करूर की घटना को व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में रखना आवश्यक है। 4 जून 2025 को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के बाद एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सार्वजनिक समारोहों के दौरान बेंगलुरु में एक अलग, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से समान भीड़-भाड़ वाली दुर्घटना देखी गई: भीड़ के उमड़ने और प्रवेश द्वारों पर भगदड़ और अफरा-तफरी मच जाने से ग्यारह लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। उस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रियाओं ने फिर से उन्हीं खामियों और विवादित बयानों को उजागर किया, जिनमें संस्थागत, पुलिस और खुफिया खामियों को कम करके आंकते हुए आयोजकों की ज़िम्मेदारी पर जोर दिया गया।

कर्नाटक सरकार की स्थिति रिपोर्ट में आरसीबी फ्रैंचाइजी और कार्यक्रम आयोजकों पर इस बात का गंभीर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुलिस और नागरिक एजेंसियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया, जबकि रिपोर्टिंग और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने पुलिस की योजना की विफलताओं, देर से या अपर्याप्त अनुमतियों और एक सुसंगत ऑन-ग्राउंड एसओपी के अभाव को रेखांकित किया। इसलिए, बेंगलुरु की घटना कोई अकेली खेल दुर्घटना नहीं है, बल्कि इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे बड़ी भीड़ + खराब योजना + कमजोर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी हमेशा तबाही का कारण बनती है।

करूर और बेंगलुरु दोनों में एक चिंताजनक समानता यह है कि जांच और सार्वजनिक आख्यानों में आयोजकों पर ही दोष मढ़ने की प्रवृत्ति है, जबकि योजना बनाने, अनुमति देने, पुलिसिंग करने और खुफिया जानकारी प्रदान करने वाली राज्य संस्थाओं की भूमिका को कम करके आंकना या दरकिनार करना है। दोनों ही मामलों में, आधिकारिक बयानों और बाद में दर्ज प्राथमिकियों ने यह धारणा बनाई कि त्रासदी मुख्य रूप से आयोजकों की गलती थी, जबकि साक्ष्य और रिपोर्टिंग ने पुलिस और प्रशासनिक तैयारियों में गंभीर खामियों, अनुमति में देरी या अंतिम समय में बदलाव, और नागरिक एजेंसियों द्वारा जमीनी स्तर पर अराजक निर्णय लेने को उजागर किया। आयोजकों को निशाना बनाने की इस जल्दबाजी ने राज्य की क्षमता, जवाबदेही और खुफिया और भीड़ प्रबंधन प्रणालियों के बारे में कठिन सवालों को बंद कर दिया, जिनसे बड़े पैमाने पर हताहतों को रोका जा सकता था।

जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 19(1)(बी) के तहत शांतिपूर्ण सभा का अधिकार नागरिकों के लिए मौत की सजा में न बदल जाए क्या भीड़ बढ़ने पर बाद के फैसले लेने के लिए कोई वास्तविक समय आकलन किया गया था। हमने भीड़भाड़ और बेहोशी के मामले शुरू होने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों पर स्पष्टता मांगी। हमने आगे सवाल उठाया कि खतरनाक अड़चनों को जन्म देने वाले इस स्थल और मार्ग का चुनाव क्यों किया गया; भीड़ के प्रवाह को कैसे प्रबंधित किया गया, और क्या आयोजकों के कार्यों ने जोखिम को बढ़ा दिया, जिसमें घायलों द्वारा यह परेशान करने वाला विवरण भी शामिल है कि संकट के बीच घनी भीड़ वाले हिस्सों में पानी की बोतलें फेंकी गईं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयोजनों और सामूहिक समारोहों के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश इन विफलताओं को रोकने के लिए एक विस्तृत, व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं: अनिवार्य भीड़ का आकलन और क्षमता आकलन, आयोजन-पूर्व जोखिम ऑडिट, कई प्रवेश/निकास बिंदुओं और बफर जोन के साथ स्पष्ट संचलन योजनाएँ, आयोजकों और अधिकारियों के लिए सूचीबद्ध ज़िम्मेदारियाँ, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, वास्तविक समय निगरानी (सीसीटीवी, ड्रोन), चिकित्सा और निकासी योजना, संचार प्रोटोकॉल, पूर्वाभ्यास किए गए एसओपी, और कार्रवाई के बाद की रिपोर्टिंग। यह मार्गदर्शिका साझा ज़िम्मेदारी पर जोर देती है—किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले आयोजकों, नगरपालिका एजेंसियों, पुलिस और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को संयुक्त रूप से तैयारियों का प्रमाणन करना होगा। ये वैकल्पिक चेकबॉक्स नहीं हैं; ये जीवनरक्षक प्रणालियाँ हैं। इन सभी की घटनास्थल पर पूरी तरह से उपेक्षा की गई इस त्रासदी से, भविष्य की प्रत्येक राजनीतिक रैली को महत्वपूर्ण सबक लेने चाहिए। पहला, अनिवार्य भीड़ अनुमान ऑडिट लागू किया जाना चाहिए, और पार्टियों को यथार्थवादी अनुमान प्रस्तुत करने चाहिए, और पुलिस को अपने स्वयं के खुफि या तंत्रों, जमीनी परिस्थितियों के अनुसार इनकी समीक्षा और समायोजन करना चाहिए, और जहाँ आवश्यक हो, बिना जरूरी समय गँवाए अतिरिक्त बल बुलाना चाहिए। दूसरा, उचित और प्रभावी बैरिकेडिंग, कई प्रवेश और निकास बिंदुओं का प्रावधान, और संभावित खतरों से सुरक्षित ऊँचे प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से आयोजन स्थल की सुरक्षा को कड़ा किया जाना चाहिए।

तीसरा, ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क और समर्पित नियंत्रण कक्षों का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, ताकि दहशत फैलने से पहले हस्तक्षेप को बढ़ाया जा सके। चौथा, चिकित्सा तैयारियों को एम्बुलेंस से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें मौके पर चिकित्सा दल और आपातकालीन परिदृश्यों के लिए पूर्व अभ्यास शामिल हों। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, और ऐसी किसी भी त्रासदी को प्रबंधित करने और टालने के लिए, संभावित भीड़ की संख्या का अनुमान लगाने, आयोजन स्थल पर भीड़ के घनत्व का अध्ययन करने, भीड़ के बढ़ने के पैटर्न, प्रवेश और निकास या स्थिर प्रवाह और दबाव बिंदुओं आदि के लिए एआई को एक प्रभावी तकनीकी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंत में, साझा ज़िम्मेदारी जरूरी है।

उपेक्षा की शिकार भारत की पुरातात्विक धरोहर

सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहासकारों, भाषाविदों और पुरातत्वविदों को आज भी आकर्षित करती रही है। मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर अंकित इसकी अपठित लिपि चार सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है।

अशोक कुमार **कौशल किशोर**

दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहासकारों, भाषाविदों और पुरातत्वविदों को आज भी आकर्षित करती रही है। मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर अंकित इसकी अपठित लिपि चार सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 21वीं सदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ, इस प्राचीन लिपि को डिकोड करने की संभावना ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि इस कांस्य युगीन सभ्यता के उत्खनित खंडहर मुख्यतः उत्तरी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, हाल ही में दक्षिणी भारत से भी क्रिप्टोग्राफि क अनुसंधान को प्रायोजित करने में सक्रियता आई है, यहाँ तक कि इस लिपि को सफलतापूर्वक डिक्रिप्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को लाखों डॉलर के इनाम की घोषणा भी की गई है।

क्रिप्टोग्राफर भरत राव, जिन्हें यजनदेवम के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को समझने के उनके निरंतर प्रयास संकेत देते हैं कि वे एक सफलता के करीब हैं। यदि यह संभव हो जाता है, तो यह भारतीय इतिहास की हमारी समझ को मौलिक रूप से नया रूप दे सकता है, विशेष रूप से बहुचर्चित आर्यन आक्रमण सिद्धांत का प्रतिकार करने में। उनके शोध के अनुसार, सिंधु लिपि वास्तव में ब्राह्मी लिपि की प्रारंभिक पूर्ववर्ती हो सकती है, जिसका प्रयोग बाद में संस्कृत में लिपिबद्ध करने के लिए किया गया।

हालांकि, इस बौद्धिक उत्साह के बीच एक दुखद विडंबना छिपी है। सिंधु घाटी अनुसंधान में वैश्विक रुचि जहाँ बढ़ रही है, वहीं इन रहस्यों को उजागर करने वाली वास्तविक कलाकृतियाँ उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। इस विरोधाभास का एक प्रमुख उदाहरण हरियाणा के झज्जर में स्थित अल्पज्ञात स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है।

आचार्य भगवान देव - जिन्हें बाद में स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से जाना गया - द्वारा 1960 में स्थापित इस संग्रहालय में हजारों अमूल्य कलाकृतियाँ हैं, जिनमें से कुछ 5,000 साल से भी पुरानी हैं। इसके संग्रह में हड़प्पाकालीन मुहरें, टेराकोटा मूर्तियाँ, सिक्के, तांबे और कांसे के हथियार, पांडुलिपियाँ और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उत्खनन स्थलों से एकत्रित मूर्तियाँ शामिल

हैं। इनमें राखीगढ़ी की सामग्री शामिल है, जो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, साथ ही जर्मन पुरातत्वविद् पॉल एलन यूल द्वारा उत्तर भारत के कॉपर होर्ड्स जैसे अकादमिक कार्यों में वर्णित वस्तुएं भी शामिल हैं। 1980 और 1990 के दशक में यूल के व्यापक शोध, जिसका एक हिस्सा आपातकाल के दौरान और उसके बाद संग्रहालय के नरेला में अस्थायी स्थानांतरण के दौरान किया गया था, ने इन संग्रहों के वैश्विक महत्व को उजागर किया। अपने चरम पर, संग्रहालय ने पाँच लाख से अधिक कलाकृतियाँ एकत्र कीं, जिनमें 150,000 सिक्के और 250 हथियार शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे महाभारत काल के हैं। क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों के लिए, यह संग्रह एक सोने की खान है। विशेष रूप से हड़प्पा की मुहरें सिंधु लिपि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विरासत की इस चौंका देने वाली संपत्ति के बावजूद, संग्रहालय पतन के कगार पर खड़ा है। 2014 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण के लिए 17 लाख रुपये आवंटित किए और इसके निदेशक के लिए 50,000 रुपये मासिक मानदेय स्वीकृत किया। हालाँकि, मात्र 20 महीनों के भीतर, मानदेय बंद कर दिया गया, जिससे संस्थान एक बार फिर घटते संसाधनों की दया पर निर्भर हो गया।

मनोहर लाल खट्टर, जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने, ने भी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान संग्रहालय की प्रशंसा की थी, यहाँ तक कि इसे ₹हरियाणा का पहला संग्रहालय₹ भी कहा था।

आज, संग्रहालय का प्रबंधन लगभग पूरी तरह से इसके 80 वर्षीय निदेशक, आचार्य विरजानंद दैवकृणी के कमजोर कंधों पर टिका है। पाँच दशकों से भी अधिक समय से, वे इस विशाल विरासत के संरक्षक रहे हैं, दुर्लभ आगंतुकों को सूचीबद्ध, संरक्षित और मार्गदर्शन करते रहे हैं। जिसे कभी अनुसंधान और शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जाता था, वह वास्तव में एक ₹एक-व्यक्ति संग्रहालय₹ बन गया है। झज्जर के संग्रहालय की यह दुर्दशा कोई अकेला मामला नहीं है।

उत्तर प्रदेश के चंदौसी में पंडित सुरेन्द्र मोहन मिश्र संग्रहालय, जो पुरावशेषों का एक और निजी तौर पर निर्मित भंडार है, भी इसी तरह की दुर्दशा का सामना कर रहा है। दोनों ही संस्थानों का जन्म 20वीं सदी में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और जन सहयोग से हुआ था, लेकिन निरंतर सरकारी सहायता के अभाव ने उन्हें अप्रासंगिकता के कगार पर धकेल दिया है। वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर लोकेश चंद्र ने अक्सर याद किया है कि कैसे स्थानीय समुदायों ने इन संग्रहालयों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उदारतापूर्वक कलाकृतियाँ और संसाधन दान किए थे। संस्कृति और विरासत के प्रति गहरी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, संस्थापकों ने इन संग्रहों का निर्माण लाभ के लिए नहीं, बल्कि भारत के अतीत के संरक्षण के लिए किया था। हालाँकि, आज ये विरासतें ढह रही हैं। संस्थागत समर्थन के बिना, इनके खजाने के क्रिस्टी या सोथबी जैसे अंतरराष्ट्रीय नीलामी घरानों के हाथों में पड़ने का खतरा है, जैसा कि पहले कई भारतीय पुरावशेषों के साथ हुआ है।

संग्रहालय केवल कलाकृतियों के भंडार नहीं हैं; वे इतिहास की जीवंत कक्षाएँ हैं। उचित प्रबंधन के साथ, वे अनुसंधान, शिक्षा और सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। हरियाणा के लिए, झज्जर का संग्रहालय वैश्विक सिंधु घाटी अध्ययन का केंद्र बन सकता था। इसके बजाय, इसके खजाने धूल भरे हॉल में छिपे हुए हैं, चोरी, क्षति और अंततः लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। संग्रहालय प्रबंधन की चुनौतियाँ केवल झज्जर तक ही सीमित नहीं हैं। दुनिया भर में, ऐसे संस्थानों को बनाए रखने के लिए संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

आप की बात

अमेरिका की सक्रियता और शांति

पिछ्ले करीब दो साल से अशांत गाजा में फिलहाल शांति की उम्मीद बंधी है कारण इजरायल एवं हमास आज चाहे भले हि पूरी तरह से लड़ाई खत्म करने को सहमत न हों पर आज अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में अब इजरायल गाजा पर हमले रोकने पर सहमत हो गया है तो इधर अब हमास भी इजरायली बंधकों को लोटाने पर सहमत हो गया है, अतः कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प का दबाव फिलहाल काम कर रहा है कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में शांति बहाली के लिए जिन बीस सुत्रीय योजना की घोषणा की थी अब उस दिशा में आज प्रगति दिखाई दे रही है। पिछ्ले दो साल से जारी इस संघर्ष में गाजा में लगभग सत्तर हजार फिलिस्तीनी मारे गये है, अतः यहां शांति की शुरूआत के लिए सभी उत्सुक हैं यही कारण है कि युरोपीयन देशों सहित स्वयं भारत ने भी इस योजना का स्वागत किया है, बहरहाल याद रखना चाहिए कि भारत ने पिछ्ले संयुक्त राष्ट्र महा सभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था जो फिलिस्तीनी मुद्दे के शांति पूर्ण हल का समर्थन करता है कारण स्वयं भारत भी गाजा के हालात पर चिंता व्यक्त करता रहा है। अतः कह सकते हैं कि जब तक गाजा के मामले में राष्ट्रपति ट्रम्प सक्रिय न थे तब तक यहां काफी नर संहार होता रहा है परंतु आज जब अमेरिका ने इस मामले में रूचि लेकर आज काम करना शुरू किया है।

– **मनमोहन राजावतराज**, शाजापुर

राहुल की विदेश यात्रा का रहस्य

राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं देश में चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य से तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही पर्दा उठा सकते हैं। उनकी यह विदेश यात्रा इसलिए भी रहस्य का विषय बनता है क्योंकि जब भी देश के किसी राज्य में अथवा केन्द्रीय चुनाव होते हैं तो राहुल विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। संसद में राहुल गांधी से पहले भी लोक सभा में विपक्ष के नेता हुए हैं किन्तु किसी भी नेता के साथ ऐसा संयोग नहीं था। उनकी विदेश यात्रा से देश को कोई आपत्ति नहीं है और न ही होनी चाहिए। किन्तु जब उनकी विदेश यात्रा देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कारण बनती है तो हर भारतीय को उनकी ऐसी यात्राओं पर आपत्ति होगी ही।वे देश में घूम - घूमकर पिछ्ले 11 वर्षों से जिस झूठ को प्रतिष्ठापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उसी झूठ का रोना कि भारत में लोकतन्त्र और संविधान पर संकट है विदेशी धरती पर करने निकल पड़ते हैं। वैसे तो कुछ चुनिंदा विदेशी विश्वविद्यालयों तक ही उनकी यह विदेश यात्रा सीमित रहती है,जो उनके समर्थकों द्वारा प्रायोजित होती है,किन्तु क्या देश के बाहर देश की व्यवस्थाओं पर टिप्पणी करना एक विपक्षी नेता को अपेक्षित है? क्या यह कृत्य राष्ट्र विरोधी नहीं है? यदि नहीं तो राहुल को अपनी पार्टी के अतीत में भी झांककर देख लेना चाहिए।

– **डॉ नरेंद्र टोंक**, मेरठ

शीर्ष अदालत में जूता प्रकरण

विगत दिनों देश के उच्चतम न्यायालय में हुए जूता प्रकरण ने जहां देश की लोकतांत्रिक सुदृढ़ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, वहीं हर घटना में राजनीति खोजने वाले राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को भी उजागर कर दिया है। निसंदेह न्यायपालिका की गरिमा को आघात पहुंचाने वाले कृत्य को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु बिना किसी प्रमाण के न्यायपालिका के माननीयों की जाति खंगालकर प्रत्येक घटना को जातीय रंग देने प्रयास भी कम निंदनीय नहीं है। अनेक दलों एवं संगठनों द्वारा घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन करके यह सिद्ध कर दिया, कि उनके लिए हर घटना राजनीति चमकाने का अवसर है। यदि ऐसा न होता तो अनेक अवसरों पर अराजकता का परिचय देने वाली आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को न्यायपालिका के अपमान के साथ दलित के अपमान से न जोड़ती। अवैध निर्माण के प्रति दोहरेपन का परिचय देने वाली न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में है। न्यायपालिका द्वारा धार्मिक आस्थाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण टिप्पणियाँ, निष्पक्ष न्याय को नकारकर भेदभाव पूर्ण न्याय, आधार कार्ड द्वारा प्रमाणित परिचय को छिपाकर समाज में व्यापार करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले निर्णय, निराधार तथ्यों के आधार पर समाज को विघटित करने के दुस्साहस को स्वतः संज्ञान में न लेकर अराजक तत्वों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण कहीं न कहीं इस प्रकार के उच्छृंखल आचरण का आधार बन रही है।

– **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के पच्चीस वर्ष एक ऐतिहासिक सफर है। यह सफर समर्पण, संघर्ष और सिद्धि का अनूठा उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रनिर्माण के केंद्र में पहुँचने की अद्भुत गाथा। गुजरात के सफल मुख्यमंत्री से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तक का सफर। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को जीवन का ध्येय बनाया। भारत की गौरवशाली विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं का सशक्त संयोजन। गरीबों, वंचितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास। विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा को नई ऊँचाइयां दीं। नए भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक नीतिगत सुधारों और योजनाओं का क्रियान्वयन। राष्ट्रप्रथ की भावना से ओत-प्रोत एक ऐसा नेतृत्व जो प्रेरणा का स्रोत है। यह 25 वर्षों का सफर राष्ट्रनिर्माण के नए अध्याय की नींव है। यह पथबोध हर किसी को, खासकर युवाओं को, सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

– **भगवानदास छारिया**, सोमानी नगर, इंदौर

पाठकगण अपने विचार **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

सोना पहली बार 4,000 डॉलर के पार

रॉयटर्स

बढ़ रही चमक

- सोने में इस साल अब तक करीब 54 फीसदी की उछाल दर्ज हुई है
- विश्लेषकों का कहना है कि साल 2026 की तीसरी तिमाही के आखिर तक सोना 4,530 डॉलर पर पहुंच सकता है
- ट्रेडरों को इस महीने फेड की तरफ से ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद
- चांदी भी सोने की तेजी का फायदा उठाते हुए 2.4 फीसदी बढ़कर 48.97 डॉलर प्रति औंस हो गई

बुधवार को सोना पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से बचाव के लिए इस सुरक्षित परिसंपत्ति पर निवेशकों के दांव बढ़ाने से इसमें रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। साथ ही निवेशकों ने अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती पर भी दांव लगाया।

दोपहर 2.09 बजे तक हाजिर सोना 1.5 फीसदी बढ़कर 4,041.71 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था। दिसंबर डिलिवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.5 फीसदी बढ़कर 4,063.70 डॉलर पर पहुंच गया। चांदी भी सोने की तेजी की राह पर चलते हुए 2.3 फीसदी बढ़कर 48.92 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। यह उसके सर्वाधिक ऊंचे स्तर 49.51 डॉलर से बस थोड़ा ही कम है।

परंपरागत रूप से सोने को अस्थिरता के समय खरीदकर रखने का चलन रहा है। 2024 में 27 फीसदी की वृद्धि के बाद हाजिर सोना इस वर्ष अब तक लगभग 54 फीसदी चढ़ चुका है। यह 2025 की सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में से एक है, जो वैश्विक शेयर बाजारों और बिटकॉइन की बढ़त से आगे निकल गया है जबकि अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल में इस वर्ष गिरावट दर्ज की गई है।

यह तेजी कई कारणों से आई है। इनमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता जारी करहने, केंद्रीय बैंकों की स्वर्ण खरीदारी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में बढ़ता निवेश और कमजोर होता डॉलर शामिल है। स्टोनएक्स विश्लेषक रोना ओ'कोनेल ने कहा, भू-राजनीतिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि पहले जैसी ही है औ इसमें अब (अमेरिकी) सरकारी शटडाउन भी जुड़ गया है।

उन्होंने कहा, इससे मजबूत इक्विटी में बाधा नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी बुलियन के माध्यम से जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार का शटडाउन बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा और इस कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के जारी होने में देरी हुई है। लिहाजा, निवेशकों को फेड दरों में कटौती के समय और दायरे के आकलन के लिए गैर-सरकारी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

बाजार फेड की आगामी बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती मानकर चल रहा है। उसे दिसंबर में भी इसी तरह की कटौती की उम्मीद है। पश्चिम एशिया के संघर्ष और यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक संकटों ने भी सराफा की मांग वृद्धि में योगदान दिया है। इसके अलावा फ्रांस और जापान की राजनीतिक उथल-पुथल ने सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ओर रुझान और बढ़ा दिया है। डॉयचे बैंक में बहुमूल्य धातु के विश्लेषक माइकल हसुए ने कहा कि पांच वर्षों में पहली बार विकसित बाजार में ईटीएफ का नवीकृत संचय भी इस तेजी को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक है।

विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश इस वर्ष अब तक 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया है जिसमें अकेले सितंबर में हुआ 17.3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निवेश शामिल है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि सोना समर्थित ईटीएफ में मजबूत निवेश, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और कम अमेरिकी ब्याज दरें 2026 में भी सोने की कीमतों को बढ़ावा देंगी। प्रमुख बैंक इस तेजी को लेकर आशावादी हो गए हैं।

विजडम ट्री में कमोडिटी रणनीतिकार नितेश शाह ने कहा, हमें उम्मीद थी कि वर्ष के अंत तक सोना 4,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा। मात्रा की दिशा हमारे व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप बनी हुई है। उन्होंने अपना पूर्वानुमान दोहराते हुए कहा कि 2026 की तीसरी तिमाही के अंत तक कीमतें 4,530 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी।

विश्लेषकों का कहना है कि कहीं छूट न जाएं, का डर भी इस तेजी को बढ़ावा दे रहा है। यूबीएस के विश्लेषक जियोवानी स्टानोवो ने कहा, सोने के लिए एक बड़ी बाधा यह होगी कि फेड सोने के प्रति और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए। लेकिन फिलहाल ट्रंप अमेरिका में ब्याज दरों में कमी देखना चाहते हैं और इससे सोने का आकर्षण बढ़ता रहेगा।

एचएसबीसी ने बुधवार को सोने की ऊंची कीमतों, निवेशकों की बढ़ती मांग और अस्थिर व्यापार की आशंका का हवाला देते हुए 2025 के लिए चांदी की औसत कीमत का अनुमान बढ़ाकर 38.56 डॉलर प्रति औंस और 2026 के लिए 44.50 डॉलर प्रति औंस कर दिया।

सोने की तेजी का असर अन्य कीमती धातुओं पर भी पड़ा और प्लैटिनम 3.1 फीसदी बढ़कर 1,668.28 डॉलर पर पहुंच गई।

बाजार में तेजी थमी, सेंसेक्स व निफ्टी टूटे

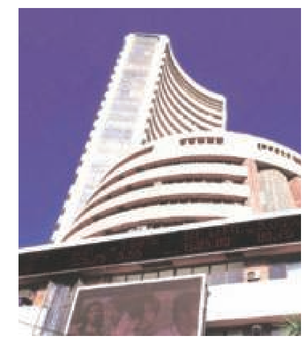

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 153.09 अंक यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 81,773.66 अंक पर बंद हुआ

शेयर बाजार में बुधवार को पिछले चार कारोबारी सत्रों से चली आ रही तेजी पर विराम लगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 153 अंक टूटा, जबकि एनएसई निफ्टी 62 अंक फिसला। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 153.09 अंक यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 81,773.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, इसमें 611.66 अंक की घट-बढ़ हुई। ऊंचे में यह 82,257.74 अंक तक गया और नीचे में 81,646.08 अंक तक आया।

उधर, एनएसई निफ्टी 62.15 अंक यानी 0.25 फीसदी टूटकर 25,046.15 अंक पर बंद हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि वाहन, रियल एस्टेट और बैंक शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं।

दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में टाइटन, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शामिल हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, प्रमुख सूचकांकों में उतार-चढ़ाव रहा। इसका कारण तेज उछाल के बाद मुनाफावसूली है। कंपनियों के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। बाजार प्रतिभागी मूल्यांकन और वृद्धि संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, बुधवार को बाजारों में उतार-चढ़ाव रहा और हाल की तेजी के बाद यह हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक स्थिर शुरुआत के बाद निफ्टी ज्यादातर समय एक सीमित दायरे में रहा और अंततः दिन के निचले स्तर 25,046.15 अंक के पास बंद हुआ।

बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.74 फीसदी और छोटी कंपनियों के स्मॉलकैप में 0.42 फीसदी की गिरावट आई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में 2,434 शेयरों में गिरावट आई जबकि 1,740 में तेजी रही। वहीं 156 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई और हॉन्गकॉन्ग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.16 फीसदी बढ़कर 66.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। *भाषा*

शेयर उधार लेने-देने के ढांचे की होगी समीक्षा

खुशबू तिवारी
मुंबई, 8 अक्टूबर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सिक्योरिटीज लेंडिंग ऐंड बॉरोइंग (एसएलबी) ढांचे यानी शेयर उधार लेने और देने की व्यवस्था की समीक्षा करेगा। इसका मकसद इस व्यवस्था को निवेशकों और कारोबारियों के अधिक अनुकूल बनाना है। यह जानकारी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने बुधवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान दी। हालांकि शेयरों की उधारी को लेकर पहले से ही एक नियामकीय ढांचा बना हुआ है। लेकिन घरेलू बाजार पर इसका प्रभाव सीमित ही रहा है।

इस व्यवस्था के तहत निवेशक या संस्थान, जिनके डीमैट खाते में शेयर होते हैं, उन्हें शुल्क लेकर उधार दे सकते हैं। यह लेनदेन स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। इसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन काउंटर-गारंटी देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उधार लेने वाले आमतौर पर ऐसे शेयरों का इस्तेमाल शॉर्ट-सेलिंग या निपटान डिफॉल्ट से बचने के लिए करते हैं। इस प्रणाली में शेयर मालिक को निष्क्रिय शेयरों पर अतिरिक्त आय कमाने की सुविधा मिलती है जबकि उधार देने का यह तंत्र समूचे बाजार की दक्षता बढ़ाता है।

नारायण ने कहा, 'हम यह परखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजारों में एसएलबी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। फिलहाल, ज्यादातर लोग शॉर्टिंग के लिए वायदा बाजार का इस्तेमाल करते हैं। हम यह संभावना टटोल रहे हैं कि क्या हम प्रक्रिया के साथ-साथ डिजाइन के नजरिये से भी बाजार कारोबारियों के लिए एसएलबी लेनदेन को आसान और बेहतर बना सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ताओं के ज्यादा अनुकूल एसएलबी ढांचा नकद बाजार में भी कारोबार की मात्रा बढ़ा सकता है।

सेबी ने तैयार की 'क्वांटम सेफ कंप्यूटिंग' की कार्य योजना

सेबी चेयरमैन ने कहा कि सभी वित्तीय क्षेत्रों में पासवर्ड सुरक्षित बनाने की जरूरत

खुशबू तिवारी
मुंबई, 8 अक्टूबर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि बाजार नियामक ने नियमन वाली अपनी व्यवस्था में क्वांटम तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। साथ ही क्षमता-निर्माण के उपाय भी किए गए हैं। पांडेय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोल रहे थे।

सेबी प्रमुख ने कहा कि नियामक 2028-2029 में परिचालन शुरू करने के लक्ष्य के साथ 'क्वांटम सेफ कंप्यूटिंग' पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा एन्क्रिप्शन मानकों के तहत पूरे वित्तीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड गंभीर जोखिम में हो सकते हैं क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग काफी एडवांस होती जा रही है।

कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक के साथ एक पैनल चर्चा के दौरान पांडेय ने कहा, 'उद्योग के रूप में हम स्वयं को क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी के लिए कैसे तैयार करें, इस बारे में कार्य योजना के आधार पर हम खोजेंगे, तैयार करेंगे और फिर अगले दो से चार साल के भीतर उस पर अमल करेंगे।' वाई2के चुनौती से तुलना करते हुए पांडेय ने समय पर सिस्टम की तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया।

कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा, 'अभी हम जो पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी करते हैं, जिससे हम पासवर्ड बनाते हैं, चाहे वह 128 एन्क्रिप्टेड हो या कुछ और, क्वांटम कंप्यूटिंग से वह टूट जाएगा। क्रिप्टो-प्रूफ पासवर्ड को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी पीक्यूसी या फिर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्यूकेडी कहा जाता है। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। धीरे-धीरे, सभी प्रणालियों में हमें यह देखना होगा कि पासवर्ड का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है और फिर हमें उन्हें बदलना होगा।'

पांडेय का कहना है कि फिनटेक कंपनियां सेबी के इनोवेशन सैंडबॉक्स के तहत प्रतिभूति बाजार में ब्लॉकचेन ऐप्लीकेशनों की टेस्टिंग कर रही हैं। एआई के बारे में उनका मानना है कि इसमें व्यापक अवसर हैं औरसाथ ही संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कारगर तरीके से अमल के लिए आरबीआई और आईआरडीएआई जैसे दूसरे नियामकों के साथ तालमेल का आग्रह किया।

पांडेय ने कहा, 'जैसे ही हम इस बदलाव की यात्रा के अगले दौर में जाएंगे तो फिनटेक से संबंधित नवाचार और नियामकीय दूरदर्शिता के बीच सहयोग से यह तय होगा कि हम कितनी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही यह भी कि हम कितने सुरक्षित रूप से बढ़ रहे हैं।'

सेबी चेयरमैन ने बाजार में धोखाधड़ी से निपटने और निवेशकों को घोटालों और गुमराह करने वाले तत्वों से बचाने के उपायों की भी रूपरेखा बताई। उन्होंने बताया कि नियामक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कैसे प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है, ऑफसाइट निरीक्षण कर रहा है, वास्तविक समय में मध्यस्थों की निगरानी और बाजार हेरफेर और नेटवर्क-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई/एमएल मॉडल विकसित कर रहा है।

उन्होंने साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ तैयारी के महत्त्व पर जोर दिया जो सिस्टम में बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'एक भी डेटा उल्लंघन या परिचालन संबंधी गड़बड़ी का आपस में जुड़ी प्रणालियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे-जैसे बाजार कारोबारी थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं और क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, जोखिम के नए आयाम भी उभर रहे हैं।'

सेबी ने ब्लॉक डील के नियम आसान बनाए

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को ब्लॉक डील विंडो से जुड़े नियमों में ढील दी ताकि ट्रेड को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। बाजार नियामक ने ब्लॉक डील के लिए ऑर्डर का न्यूनतम आकार 25 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।

अब दो ब्लॉक डील सत्र होंगे - सुबह 8:45 से 9:00 बजे तक एक विंडो और दोपहर 2:05 से 2:20 बजे तक दूसरी विंडो। ऐसे लेनदेन के लिए संदर्भ मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 3 फीसदी कम या ज्यादा हो सकता है। सेबी ने इस विंडो के माध्यम से किए गए सौदों के लिए उसी दिन निपटान की भी अनुमति दी है। *बीएस*

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को 3.3 गुना आवेदन

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बंद होने से एक दिन पहले बुधवार को 3.3 गुना आवेदन मिले। इस निर्गम के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं और 34 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इससे निवेशकों की जबरदस्त मांग का पता चलता है।

निवेशकों की संस्थागत श्रेणी को 2.6 गुना, एचएनआई श्रेणी को 7.6 गुना और खुदरा श्रेणी को लगभग दोगुना आवेदन मिले। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईपीओ के लिए 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर का कीमत दायरा तय किया है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर निर्गम का आकार 11,607 करोड़ रुपये है जिससे दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख की भारतीय इकाई का मूल्यांकन करीब 77,400 करोड़ रुपये बैठता है।

यह आईपीओ पूरी तरह से मूल कंपनी का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) है जो अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि इस इश्यू की कीमत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आकर्षक है।

सेंट्रम ब्रोकिंग ने एक नोट में कहा, 1,140 रुपये के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2025 के प्रति शेयर आय (ईपीएस) के करीब 35 गुना के पीई पर उचित है जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियां काफी अधिक गुणकों पर कारोबार कर रही हैं। हम इस इश्यू को 'सब्सक्राइब' रेटिंग देते हैं।

भारत में एलजी का मुकाबला सैमसंग, वोल्टास, हैवेल्स, गोदरेज, ब्लू स्टार, हायर, व्हर्लपूल, फिलिप्स और सोनी से है। सैमसंग के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है। *बीएस*

टाटा कैपिटल के आईपीओ को 2 गुना आवेदन

टाटा कैपिटल का 15,512 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ घरेलू बाजार में चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है। पर इसे केवल दो गुना आवेदन मिले। इसके साथ दो बड़े ऑफरों के भी लॉन्च होने से नकदी की किल्लत हो गई। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 3.4 गुना, एचएनआई श्रेणी में दो गुना, खुदरा श्रेणी को 1.1 गुना तथा कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणी को 2.9 गुना आवेदन मिले। कुल मिलाकर इस इश्यू को 21,230 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं और लगभग 24 लाख आवेदन प्राप्त हुए। खुलने से एक दिन पहले टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों को 4,641 करोड़ मूल्य के शेयर आवंटित किए।

आईपीओ में टाटा समूह की इस कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो उसकी बुक वैल्यू का लगभग 3.5 गुना है। विश्लेषकों का कहना है कि टाटा कैपिटल के फंडामेंटल और वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हैं। लेकिन मौजूदा मूल्य निर्धारण निकट भविष्य में इसके लाभ को प्रभावित कर सकता है। एक साल पहले ही गैर-सूचीबद्ध बाजार में इस शेयर का भाव 1,000 रुपये प्रति शेयर से ऊपर था। *बीएस*

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५ के अंतर्गत गठित)

शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉर्पोरेट सेन्टर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

वेबसाइट: https://bank.sbi **ई-मेल:** investor.seva@sbi.co.in

फोन नं: 022-2274-0849 / 2403 / 1483

तत्काल ध्यान दें : शेयरधारक
100 दिवसीय अभियान: सक्षम निवेशक
केवाईसी अद्यतनीकरण, भुगतान न किए गए लाभांश और शेयरों का दावा

दूसरी सूचना

प्रिय शेयरधारकों,

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28.07.2025 से 06.11.2025 तक 100 दिनों का अभियान ''सक्षम निवेशक'' शुरू किया गया है। **इसका उद्देश्य शेयरधारकों में केवाईसी अद्यतनीकरण, अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश और शेयरों के दावे के बारे में जागरूकता पैदा करना है।**

हम अपने सम्मानित शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास और यदि शेयर डीमैट रूप में हैं तो संबंधित डीपी के पास **अपना केवाईसी** (ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण) अपडेट करें, ताकि **विभिन्न संचार प्राप्त हो सकें और लाभांश का भुगतान निर्बाध रूप से हो सके।**

कृपया ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में ट्रान्सफर कर दिया गया है। कृपया इसके लिए दावा उनके पोर्टल: http://iepf.gov.in/IEPF/refund.html पर दर्ज करें। इसके अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए, कृपया बैंक के आरटीए को निम्नलिखित पते पर अनुरोध भेजें:

आरटीए का पता: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट-भारतीय स्टेट बैंक, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 ईमेल आईडी: einward.ris@kfintech.com, टोल फ्री: 1800 309 4001; वेबसाइट: www.kfintech.com

किसी भी सहायता/मामले को आगे बढ़ाने के लिए, कृपया हमें नि:संकोच कॉल करें या ईमेल भेजें **investor.seva@sbi.co.in**

हम भौतिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को डीमैट (अमूर्त) रूप में परिवर्तित करा लें ताकि हानि, क्षति, गलत स्थान पर रखे जाने आदि के जोखिम से बचा जा सके और साथ ही सभी संबंधित जानकारी और लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त किए जा सकें।

कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2025 द्वारा अधिसूचित और 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, ऐसे सभी शेयर जिनके लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या जिन पर लगातार सात वर्षों से दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम उचित दावेदारों से अनुरोध करते हैं कि वे बैंक के आरटीए/हमारे पास सहायक दस्तावेज़ जमा करके जल्द से जल्द ऐसे लाभांश का दावा करें।

भारतीय स्टेट बैंक हेतु

(मनोज कुमार सिन्हा)
महाप्रबंधक
(शेयर एवं बॉण्ड)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.10.2025

'आईपीओ की भरमार से बाजार में सीमित तेजी'

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर

बर्नस्टीन के विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। सुस्त वृहद आर्थिक परिदृश्य, औसत कॉरपोरेट आय और भू-राजनीतिक बदलावों से इस साल उनके सकारात्मक दृष्टिकोण पर असर पड़ा है। उन्होंने एक निवेशक सम्मेलन के बाद हाल में जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही।

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज ने निफ्टी के 2025 के अंत तक 26,500 का स्तर छूने का लक्ष्य बरकरार रखा है जो मौजूदा स्तर से मुश्किल से 5 प्रतिशत अधिक है। उसका मानना है कि आईपीओ लाने की मारामारी से बाजार में तेजी की संभावना सीमित हुई है। बर्नस्टीन भारत के जिन सेक्टर पर 'ओवरवेट' है, उनमें फाइनैंशियल, टेलीकॉम और खपत श्रृंखला शामिल है। आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में 74 कंपनियों ने प्राथमिक बाजार से 85,241.08 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें हाल में सब्सक्रिप्शन के लिए खुले तीन बड़े आईपीओ शामिल नहीं हैं। कैलेंडर वर्ष 2025 में प्राथमिक बाजार से जुटाई गई पूंजी की मात्रा पिछले पांच वर्षों में तीसरी बार सबसे अधिक है।

वीवर्क इंडिया, टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ का सामूहिक रूप से 30,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने का लक्ष्य है। प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार टाटा कैपिटल की 15,511.87 करोड़ रुपये, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की 11,607 करोड़ रुपये और वीवर्क इंडिया की लगभग 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

बाजार जोखिम

बर्नस्टीन के प्रबंध निदेशक और भारत में शोध प्रमुख वेणुगोपाल गैरे ने अपने नोट में कहा कि निवेशक सम्मेलन से एक बात सामने आई कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की दिलचस्पी नहीं बची है। इसका संकेत इस वर्ष 18 अरब डॉलर की निकासी से मिलता है। भारतीय बाजारों का प्रदर्शन एशिया में अपेक्षाकृत कमजोर रहा है और कैलेंडर वर्ष 2025 में इसमें लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि कोस्पी (48 प्रतिशत ऊपर), ताइएक्स (17.3 प्रतिशत) और शांघाई कम्पोजिट (16 प्रतिशत) ने भारत के मुख्य बेंचमार्क को काफी पीछे छोड़ दिया है।

भारत की आर्थिक वृद्धि के तीन स्तंभ- निर्माण, सेवा और डिजिटलीकरण- जोखिम का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से भू-राजनीति से जुड़ा है, लेकिन यह नवाचार पर संगठित ध्यान की कमी और राष्ट्रीय चैंपियन बनाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन की कमी के कारण भी है। यदि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो तो चाइना-प्लस-वन रणनीति विफल हो सकती है और संभावित रूप से भारत को सच्चे प्रतिस्पर्धी के बजाय चीनी उत्पादों और निवेशों का गंतव्य बना सकती है।

भारतीय बाजार में तेजी

बर्नस्टीन के विश्लेषकों का कहना है कि 'भारत में तेजी' चाहने वाले लोगों को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ देश के व्यापार विवाद का जल्द समाधान होने से टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह जाएगा जो अधिक स्वीकार्य होगा। विनिर्माण क्षेत्र को निवेश आकर्षित करना जारी रखना चाहिए और बेहतर चीन-भारत संबंध प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच को सुगम बना सकते हैं, जिससे नौकरी सृजन में अल्पावधि से मध्यावधि का लाभ मिल सकता है।

PGIM India Mutual Fund

PGIM India Asset Management Private Limited
4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 6159 3000. **Fax:** +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 **Toll Free No.:** 1800 266 7446
Website: www.pgimindia.com/mutual-funds/

NOTICE

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulation 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular dated June 27, 2024, the unit holders of all the Scheme(s) of PGIM India Mutual Fund ('Fund') are requested to note that the half yearly portfolio of all the Scheme(s) of the Fund for the half year ended September 30, 2025, are hosted on the website www.pgimindia.com/mutual-funds/ and www.amfiindia.com.

The unit holders can submit a request for a physical or electronic copy of the statement of scheme portfolio of the Fund for the half year ended September 30, 2025, by calling on 1800 209 7446 or by sending an email to care@pgimindia.co.in or by writing to PGIM India Asset Management Private Limited at 4th Floor, C Wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

For PGIM India Asset Management Private Limited
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date : October 08, 2025

Sd/-
Authorized Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 200

अप्रासंगिक होती बहुपक्षीय व्यवस्था!

क्या बहुपक्षीय व्यवस्था में अभी दुनिया को देने के लिए कुछ शेष है? अपनी तमाम खामियों और अक्षमताओं के बावजूद यह हाल तक एक ऐसी व्यवस्था बनी रही जिसके तहत वैश्विक महत्त्व के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और उठाया जाता रहा है। इस व्यवस्था में खामियां तब पैदा हुईं जब अमेरिका ने उन दशकों के दौरान स्थापित मानदंडों को भंग किया जब वह निर्विवाद रूप से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में था। चीन के एक विघटनकारी शक्ति के रूप में उभरने के बाद ये दरारें और गहरी हो गईं। अब जबकि डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने बहुपक्षीयता की अवधारणा के विरुद्ध सक्रिय रुख अपना लिया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापक आर्थिक स्थिरता, व्यापार प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी विवाद जैसे प्रमुख लंबित मुद्दों को अब बहुपक्षीय प्रणालियों के जरिये नहीं सुलझाया जा रहा है।

वृहद आर्थिक स्थिरता की बात करें तो विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर निर्भर रही है। बीते दशकों में आईएमएफ ने ही अर्जेंटीना को कई बार उबारा। पाकिस्तान के अलावा लैटिन अमेरिका का यह देश ही एक ऐसा मुल्क है जिसे बार-बार फंड की मदद की जरूरत पड़ी है। वह एक बार फिर मुश्किल में है। इस बार संकट अधूरे सुधारों और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न हुआ है। परंतु इस बार अमेरिकी वित्त विभाग ने इस मुल्क को बचाने के लिए खुद दखल दिया है। गत सप्ताह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने कहा कि अमेरिका और अर्जेंटीना 20 अरब डॉलर के एक पैकेज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके चलते अर्जेंटीना की मुद्रा में तेजी आई। बेसंट ने कहा कि अमेरिका, अर्जेंटीना को संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। तथ्य यह है कि आईएमएफ में ऐसा ऋण कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता है और वह अर्जेंटीना को बेपटरी होने से बचाने के लिए जवाबदेही ढांचा तैयार कर सकता है। अमेरिकी वित्त विभाग के पास यह क्षमता नहीं है लेकिन उसके पास वह राजनीतिक प्रभाव है जो आईएमएफ के पास नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार यह दावा किया है कि उनमें युद्ध समाप्त करवाने की क्षमता है। उन्होंने कई संघर्षों का उल्लेख भी किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि उनकी मध्यस्थता के कारण वहां शांति स्थापित हुई। यहां तक कि गत सप्ताह उन्होंने गाजा के लिए एक नई शांति योजना पेश की। ट्रंप के दावों में कितनी सचाई है यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि उन्होंने अमेरिकी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सब खुद करने का प्रयास किया है। वह इसे अपनी निजी सौदेबाजी क्षमता की देन मानते हैं। सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र इकलौता ऐसा बहुपक्षीय संस्थान नहीं है जिस ट्रंप के कदमों ने अनुपयोगी सा बनाया हो। उन्होंने नए व्यापार समझौतों पर भी ध्यान दिया है। उनमें से कई ऐसे तैयार किए गए हैं कि वे अमेरिकी व्यापार और शुल्क नीतियों को असाधारण रूप से तवज्जो देते हैं। यह विश्व व्यापार संगठन के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी एमएफएन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ध्यान रहे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में यह एक बुनियादी सिद्धांत रहा है। वह पहले ही विवाद निस्तारण के मंच के रूप में अपनी ताकत गंवा चुका था। अब व्यापार नीति में सभी देशों के साथ समान व्यवहार की बुनियादी भावना भी समाप्त हो चुकी है।

विश्व युद्ध के बाद की बहुपक्षीय व्यवस्था का उद्देश्य था शक्ति को यथासंभव सीमित रखना। शीत युद्ध के द्विध्रुवीय विश्व में इस प्रणाली की कुछ उपयोगिता थी, विशेष रूप से नए आजाद हुए और उपनिवेश-मुक्त देशों के संदर्भ में। एकध्रुवीय व्यवस्था के दशकों में इसने कुछ हद तक अमेरिका की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन अब जबकि अमेरिका ने एक विघटनकारी रास्ता अपना लिया है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रणाली की अपनी कोई शक्ति नहीं है। इसकी शक्ति हमेशा उतनी ही रही, जितनी कि महाशक्ति ने उसे दी। अब जब व्हाइट हाउस यह मानता है कि वह समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है, तो बहुपक्षीय प्रणाली के पास करने को बहुत कुछ बचा नहीं है।

इंजीनियरों की राष्ट्र निर्माण में बढ़े भूमिका

सक्षम इंजीनियरों को यदि नेतृत्व में रखा जाए, तो यह हमारे देश में घटिया काम को सहन करने और जुगाड़ की संस्कृति का उत्सव मनाने की प्रवृत्ति समाप्त कर सकता है। बता रहे हैं टीएन नाइनन

स्टैनफर्ड के हूवर हिस्ट्री लैब के डैन वांग ने अपनी पुस्तक 'ब्रेकनेकः चाइनाज क्वेस्ट टु इंजीनियर द फ्यूचर' के माध्यम से व्यापक तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें वह तर्क देते हैं कि चीन एक 'इंजीनियरिंग राज्य' है, जबकि अमेरिका 'वकीलों का राज्य' है। यह विश्लेषण नया नहीं है। द इकॉनमिस्ट के अनुसार, 1998 में चीन की यात्रा के दौरान बिल क्लिंटन ने कहा था, 'आपके पास बहुत सारे इंजीनियर हैं, और हमारे पास बहुत सारे वकील... चलिए अदला-बदली कर लेते हैं!'

आज अगर आप चीन जाएं तो उसकी इंजीनियरिंग की सफलताएं आपको चौंका देंगी। आपका यह स्तंभकार एक दशक बाद पिछले महीने चीन गया तो उसे ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। आपने चीन के बारे में कितना भी पढ़ा हो, वहां के विशाल हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों, पुलों, ऊंची इमारतों और बुलेट ट्रेनों को देखना और महसूस करना एक अलग अनुभव था। खासतौर पर तब जबकि यह उत्कृष्ट शहरी नियोजन और सार्वजनिक सुविधाओं के उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण के स्पष्ट कौशल के साथ जुड़ा है। यह एक सुव्यवस्थित समाज है जिसने अभूतपूर्व पैमाने पर निर्माण किया है, और वह भी अत्यंत उत्कृष्टता के साथ।

यह कमाल इंजीनियरों ने किया है। 20वीं सदी के मध्य में सोवियत संघ ने भी ऐसा ही किया था जो इस समय चीन कर रहा है। उसके राजनीतिक नेतृत्व में इंजीनियरों का दबदबा है। चीन के विशेषज्ञों ली चेंग और लिन व्हाइट के मुताबिक चीन के प्रांतों, प्रमुख शहरों और स्वायत्त क्षेत्रों के 80 फीसदी गवर्नर, मेयर और पार्टी सचिव टेक्नोक्रेट हैं।

ऐसा हमेशा नहीं था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आरंभिक नेता मुक्ति संग्राम की उपज थे। इंजीनियर तीसरी पीढ़ी से प्रभावशाली हुए जिन्हें तंग श्याओफिंग ने चुना। इस समूह का नेतृत्व च्यांग चेमिन के हाथों में था जो स्वयं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके अलावा झू रोंग्जी, हू चिंताओ और शी चिनफिंग भी इसी श्रेणी में हैं जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई की।

वान गांग का उदाहरण भी हमारे सामने है। माओ की सांस्कृतिक क्रांति के उत्पीड़न के शिकार वान पीएचडी के लिए जर्मनी जाने में सफल रहे और वहां उन्होंने ऑडी में काम करना शुरू कर दिया। एक चीनी मंत्री ऑडी के दौरे पर गए और वहां उन्होंने वान से मुलाकात के बाद उन्हें वापस चीन आमंत्रित किया। वान बिजली से चलने वाले वाहनों यानी ईवी के शुरुआती पैरोकार बने। चीन की सरकार के इकलौते गैर कम्युनिस्ट सदस्य के रूप में उन्होंने इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाया। आज चीन इस कारोबार में अग्रणी है। इसके अलावा शु गुआंगशियान कोलंबिया से स्नातक करने के बाद पीकिंग विश्वविद्यालय लौटे और बाद में दुर्लभ धातुओं पर शोध के लिए प्रयोगशाला स्थापित की। अब इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है। शु को चीन के दुर्लभ धातु उद्योग का पितामह माना जाता है।

मामला सिर्फ यह नहीं है कि प्रवासी वापस लौटे हैं। चीन के भीतर, एसटीईएम (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के छात्र हर साल देश की लगातार उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों से स्नातकों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। ये छात्र चीन की निर्णय लेने वाली उच्च स्तरीय संस्थाओं में स्थान पाते हैं, जो अमेरिका या भारत में नहीं होता, हालांकि भारत एसटीईएम स्नातकों की संख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने 2022 में रिपोर्ट किया था कि 117वीं कांग्रेस में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या उतनी ही थी जितनी रेडियो टॉक-शो होस्ट्स की! सबसे अधिक उपस्थिति वकीलों और कारोबारियों की थी।

भारत का भी यह अनुभव रहा है कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो वे भी निर्माण कर सकते हैं। इसके आरंभिक उदाहरणों की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग और बांध निर्माण में एम विश्वेश्वरैया, परमाणु ऊर्जा में होमी भाभा, कृषि में एम. एस. स्वामीनाथन, अंतरिक्ष कार्यक्रम में विक्रम साराभाई और सतीश धवन तथा दुग्ध क्रांति लाने वाले मेकैनिकल इंजीनियर वर्गीज कुरियन शामिल हैं। कारखानों और संगठनों का निर्माण करने वाले अन्य इंजीनियरों में मंतोष सोढ़ी (स्टील), वी कृष्णमूर्ति (इलेक्ट्रिकल मशीनरी) और डी.वी. कपूर (बिजली उत्पादन) शामिल हैं। मेट्रो मैन ई. श्रीधरन का नाम इसी सिलसिले का हिस्सा है।

देश के सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग की नींव इंजीनियरों ने रखी। शुरुआत एफसी कोहली से हुई जिन्होंने कनाडा से इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर एमआईटी से सिस्टम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लार्सन ऐंड टुब्रो एक तकनीकी गहराई वाली कंपनी है जिसे दो डेनिश इंजीनियरों ने बनाया और बाद में एएम नाइक इसे आगे ले गए। दुनिया की सबसे जटिल तेल रिफाइनरी बनाने वाले मुकेश अंबानी एक केमिकल इंजीनियर हैं। इन्फोसिस से निकले नंदन नीलेकणी ने डिजिटल अधोसंरचना में काफी योगदान किया।

ऐसे बहुत अधिक उदाहरण नहीं हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि भारत के शुरुआती नेता अधिवक्ता थे (गांधी, नेहरू, पटेल, आंबेडकर)। नेहरू वैज्ञानिक मानसिकता के तगड़े हिमायती थे और वह 'आधुनिक भारत के मंदिर' बनाना चाहते थे लेकिन सरकारी संस्कृति में विषय विशेषज्ञता को प्रशासनिक क्षमता से कमतर माना जाता था।

हालांकि, यह विडंबना ही है कि भारत ने दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्री तैयार किए और दुनिया की सबसे बुरी वृहद आर्थिक नीतियां भी। परंतु 1991 में पी.वी. नरसिंह राव (जो स्वयं अधिवक्ता रहे थे) के नेतृत्व में अर्थशास्त्री ही सुधारों के वाहक बने। उनमें से कुछ तो भौतिकी पढ़ने के बाद अर्थशास्त्री बने थे।

अब परिवर्तन आ रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंजीनियरों की तादाद दो दशक पहले के 30 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो चुकी है। परंतु इस करियर में आगे नहीं बढ़ने के कारण वे भी बस सामान्य बनकर रह जाते हैं।

यद्यपि नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास करते हैं लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में ऐसा बदलाव अभी आना है। उनके वरिष्ठ सहयोगियों में राजनाथ सिंह और अमित शाह विज्ञान के छात्र रहे हैं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्यान सांस्कृतिक बदलाव पर है। निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्री जबकि पीयूष गोयल लेखाकार हैं। अश्विनी वैष्णव इंजीनियर हैं।

वर्ष2021 में मंत्री बने 36 केंद्रीय मंत्रियों का विश्लेषण दिखाता है कि इसमें अधिवक्ताओं का बोलबाला है। इसके अलावा इसमें बिजनेस की डिग्री वाले, डॉक्टर और दो आईएएस शामिल रहे। कुछ इंजीनियर भी हैं लेकिन उनकी संख्या नहीं पता। कांग्रेस में एकमात्र उल्लेखनीय इंजीनियर जयराम रमेश हैं। वहीं आईआईटी स्नातक अरविंद केजरीवाल को देखकर पता लगता है कि इंजीनियर के राजनेता बनने के क्या जोखिम हो सकते हैं।

देश के कारोबारी जगत में पारंपरिक व्यापारियों या साहूकार जातियों का दबदबा है। मसलन बिड़ला परिवार की पारंपरिक पार्थ लेखा प्रणाली। यह निस्संदेह कारोबारी क्षेत्र की बड़ी ताकत रही है। वहीं आज कारोबारी समूहों के कुछ सदस्य सुशिक्षित हैं और इंजीनियरिंग उद्योग चला रहे हैं।

तुलनात्मक रूप से देखें तो पारसी, ब्राह्मण, लिंगायत और पंजाबी खत्री जैसे अन्य समुदायों से आए लोगों ने जब व्यवसाय में कदम रखा, तो उन्होंने शुरुआत से ही इंजीनियरिंग पर अधिक ध्यान दिया। जैसे टाटा और गोदरेज, टीवीएस और किर्लोस्कर, कल्याणी और महिंद्रा। वहीं, आंध्र प्रदेश के समृद्ध तटीय क्षेत्र ने निर्माण क्षेत्र में कई अगुआ दिए हैं। पेशेवर वर्ग के बेहतरीन इंजीनियर विदेश जाते हैं और प्रबंधन डिग्री हासिल करते हैं, इसके बाद वे परामर्श या वित्त क्षेत्र में जाते हैं जहां अधिक वेतन-भत्ते मिलते हैं।

इंजीनियर कोई जादू नहीं कर सकते। परंतु वे तार्किक ढंग से समस्याएं हल करने के लिए प्रशिक्षित रहते हैं। वहीं अधिवक्ताओं का ध्यान न्यायालय में विपक्ष से निपटने पर रहता है। आश्चर्य नहीं कि चीन ने वित्त और आर्थिक ढांचे में बड़ी गलतियां कीं। लेकिन यदि सक्षम इंजीनियरों को नेतृत्व में रखा जाए, तो यह हमारे देश में घटिया काम को सहन करने और जुगाड़ की संस्कृति का उत्सव मनाने की प्रवृत्ति को समाप्त कर सकता है।

भारत जब प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र और गुणवत्तापूर्ण भौतिक संरचना बनाने के लिए जूझ रहा है, हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि इसे किस हद तक इंजीनियरिंग आधारित देश बनना है और इंजीनियर देश की राजनीति और प्रशासन के साथ कारोबार और उद्योग जगत में किस तरह की नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकते हैं।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के संपादक और चेयरमैन रह चुके हैं)

पाकिस्तानी सत्ता के हालिया कदमों से भारत के लिए चुनौतियां

नीति नियम

मिहिर शर्मा

इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान सभी वस्तुनिष्ठ मानदंडों के हिसाब से एक नाजुक देश है, इसलिए इसे विश्व मंच पर नजरअंदाज और खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, हाल के सप्ताहों में अमेरिका और चीन, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और आंतरिक निवेश बढ़ाने के लिए उसके साथ नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनके अलावा सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ऐतिहासिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा भले ही अंतिम ओवर में छक्का लगाकर भारत के लिए एशिया कप जीतने के लिए मैदान में डटे रहे हों, लेकिन भू-राजनीति के खेल में, जैसा कि क्रिकेट कमेंटेटर अक्सर कहते हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने शानदार प्रदर्शन किया है।

आइए पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की हालिया उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। इस साल की शुरुआत में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए क्रूर आतंकी हमले के बाद भारत को उचित समर्थन मिलने के बावजूद, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय कार्रवाई के प्रति समर्थन की अभिव्यक्ति को कम से कम कराने में कामयाब रहा। उसकी सेना ने वैश्विक स्तर पर यह प्रचारित करने में कामयाबी हासिल की कि उसने भारतीय हमलों को नाकाम कर दिया, यहां तक कि चीनी और पश्चिमी हथियारों के बीच कुछ बेतुकी तुलनाएं भी शुरू कर दीं।

अमेरिका के साथ पाकिस्तानियों ने अपेक्षाकृत अनुकूल व्यापार समझौता करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे उस देश पर टैरिफ पहले के 29 फीसदी से घटकर 19 फीसदी रह गया है और देश के कथित जीवाश्म ईंधन भंडार में अमेरिकी निवेश भी तय हो गया है। इसके सेना प्रमुख ने हाल के दिनों में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से दो बार मुलाकात की है, एक बार उम्मीद से ज्यादा लंबे चले लंच के लिए और दूसरी बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ, जिसके दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान के पास मौजूद महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों का प्रदर्शन किया गया।

यह निश्चित है कि यूएस एक्जिम बैंक ने पाकिस्तान में खनन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लाखों डॉलर देने की प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसमें रेको दिक में सोने और तांबे की खदान भी शामिल है। उन्होंने ट्रंप की जमकर प्रशंसा की है, उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए पात्र बताया है और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति का उस देश के लिए एक निश्चित झुकाव हो गया है जिसकी उन्होंने कभी अविश्वसनीय कहकर आलोचना की थी। एक 'झुकाव', जैसा कि अमेरिकी 1970 के दशक में कहा करते थे।

चीन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने 'लौह मित्रों' के लिए भले ही कुछ उत्साह खो दिया हो, लेकिन वे पूरी तरह से अपनी उम्मीदें नहीं तोड़ रहे हैं। पिछले महीने शरीफ की पेइचिंग यात्रा के साथ ही यह खबर भी आई कि 8.5 अरब डॉलर के एक नए निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हालांकि इसमें वास्तव में कितना आएगा और पाकिस्तानी जनता को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह स्पष्ट नहीं है। बेशक, पाकिस्तान के लिए चीन की बड़ी योजनाओं के बारे में ऐसे सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिले। वहां कुछ मौजूदा चीनी निवेशों को सह-वित्तपोषित किया गया है या अधिक पारंपरिक बहुपक्षीय स्रोतों द्वारा अधिग्रहीत किया गया है। लेकिन अमेरिका के साथ शांत संबंध वास्तव में पाकिस्तान में चीन की गतिविधियों में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी प्रेस में ऐसी खबरें आई हैं कि हाल ही में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन-नियंत्रित ग्वादर बंदरगाह में निवेश करने में रुचि दिखाई है, संभवतः वहां एक टर्मिनल बनाकर जो अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खेप प्राप्त कर सके।

यहां तक कि रूस, जिसे किसी भी उचित मानदंड से भारत का आभारी होना चाहिए कि उसने उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग नहीं होने दिया, उसने भी हाल ही में कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस को 'स्वाभाविक सहयोगी' बताया और पाकिस्तान को रूस का 'एशिया में पारंपरिक साझेदार' कहा है। यह समझना मुश्किल है कि यह बात आखिर क्यों कही जा रही है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि पुतिन किसी भी समय क्या सोचते हैं। रूस ने तो भारत को जैपड सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान को 'पर्यवेक्षक' के रूप में स्वीकार करने की मुश्किल स्थिति में डाल दिया, जिसमें भारतीय सेना ने (चीन और 15 से ज्यादा अन्य देशों के साथ) हिस्सा लिया था।

और अंत में, यह चौंकाने वाली खबर आई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें पारस्परिक सुरक्षा शामिल है। हम इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि रावलपिंडी का परमाणु छत्र खाड़ी तक फैल गया है। यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना वरिष्ठ भागीदार है। लेकिन यह निश्चित रूप से पिछले एक दशक की तुलना में कुछ हद तक सुधार दर्शाता है, जिस दौरान यमन में हूतियों के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब के साथ शामिल होने से पाकिस्तान के इनकार ने संबंधों में खटास पैदा कर दी थी।

पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान बदनाम, अलोकतांत्रिक और अपव्ययी रहा है। वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था चला रहा है जो खुद में निवेश करने और उत्पादक क्षमता विकसित करने में स्पष्ट रूप से विफल रही है। लेकिन उसने एक के बाद एक इन उपलब्धियों को आखिर कैसे हासिल किया? आंशिक रूप से तो इसकी वजह यह है कि वे वादे करने और ट्रंप जैसे नेताओं की उस तरह से तारीफ करने को तैयार हैं जो भारतीय नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन आंशिक रूप से यह पुराने जमाने का लचीलापन है, यानी ऐसे तरीके खोजना जिनसे वे कई साझेदारों के लिए उपयोगी हो सकें। भारत ने बहुध्रुवीयता, प्रतिरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के युग का जोरदार स्वागत किया होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस खेल में विजेता पाकिस्तान है, हम नहीं।

आपका पक्ष

घटना के पहले क्यों नहीं बरती जाती सतर्कता

कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत से भारत की 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में प्रतिष्ठा पर आंच पहुंची है। देश की छवि को गहरा धक्का लगा है। यह चिंताजनक ही है कि डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन जो केवल औद्योगिक उपयोग के हैं उनको औषधीय उत्पादों में मिलाया जा रहा है और यह नियामकीय असावधानी को उजागर करता है। यह वही लापरवाही है जिसने वर्ष 2022 में गांबिया और उज्बेकिस्तान में भी कई बच्चों की जान ली थी। मुनाफाखोरी के लिए गुणवत्ता मानकों की अनदेखी, निरीक्षण प्रक्रिया की शिथिलता और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सीमित जवाबदेही इसके मूल कारण हैं। सरकार द्वारा बाद में जांच, प्रतिबंध और निरीक्षण के आदेश दिए जाना स्वागतयोग्य है पर यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। औषधि निर्माण इकाइयों की नियमित, पारदर्शी और तकनीकी निगरानी के बिना ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। भारत को अपनी औषधि गुणवत्ता प्रणाली को विश्वस्तरीय मानकों पर पुनर्संरचित करना होगा ताकि 'जन औषधि' की पहचान, 'जन दुर्घटना' में न बदल जाए। बार-बार होने वाले इस तरह के हादसे बड़े आर्थिक नुकसान की वजह भी बनते हैं। ऐसे में प्रभावी कदम सरकार को उठाना चाहिए।

अमृतलाल मारू, इंदौर

कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हुई मौत ने भारत की 'दुनिया की फार्मेसी' की छवि को धूमिल किया है

तकनीक से बेरोजगारी नहीं बल्कि यह एक अवसर भी

लेख 'टेक बेरोजगारी और अतीत से मिले सबक' आधुनिक दुनिया में एआई के उपयोग के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट उजागर करता है। एआई के कारण बेरोजगारी एक चिंताजनक पहलू है लेकिन इसका समाधान भी उसी में निहित है। बेरोजगारी किसी भी देश में व्याप्त होती है लेकिन यहां मामला कम और ज्यादा का है। लेख में कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें नई तकनीक या मशीनरी आने से बेरोजगारी का डर सताने लगता है। उदाहरणस्वरूप कपड़े की मशीनें आने से हथकरघा उद्योग पर इसकी आंच आन पड़ी थी। विभिन्न मौके पर नई तकनीक के खिलाफ आवाज भी उठाई गई है लेकिन आधुनिक युग तकनीक को अपनाता चला गया। आज भी देश में एआई के कारण बेरोजगारी बढ़ने की चिंता करना वाजिब है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखें तो एआई की मदद से वह काम किए जा रहे हैं जो एक मनुष्य नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इसके कारण बेरोजगार होने वाले लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे वह एआई जनित नौकरियों पर बखूबी काम कर सकें। इससे पहले भी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं जब वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है। कंपनियों को उनके काम के मुताबिक कुशल छात्र नहीं मिल पाते हैं तथा उन्हें ऐसे छात्रों को अलग से प्रशिक्षित करना पड़ता है। अतः तकनीक अपनाने तथा इससे होने वाली बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार, शिक्षण संस्थानों तथा कंपनियों को पहले से तैयारी पूरी करने की जरूरत है, जिससे लोगों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

वायुसेना दिवस के अवसर पर बुधवार को रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौ सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव, एक्सपो एवं अवाड्र्स 2025 आज भारत मंडपम में

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी होंगे मुख्य अतिथि, देश-विदेश के उद्योग, नीति और नवाचार जगत के दिग्गज करेंगे एमएसएमई के भविष्य पर मंथन, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी पहुंचेंगे

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को नई दिशा देने, उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाने और "वोकल फॉर लोकल" के विजन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमर उजाला आज भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव, एक्सपो व एवं अवाड्र्स 2025 का आयोजन कर रहा है।

यह कार्यक्रम अमर उजाला के एमएसएमई मंथन की उस ऐतिहासिक श्रृंखला का समापन है, जो सितंबर माह में 8 राज्यों के 26 शहरों में आयोजित हुई थी और जिसमें 5000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर्स और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया था। इस अवसर पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतनराम मांझी मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे।

आयोजन न केवल एमएसएमई के लिए एक प्रेरणादायक मंच बनेगा, बल्कि यह भारत के उद्यमों को स्थानीय से वैश्विक स्तर तक आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास भी देगा।

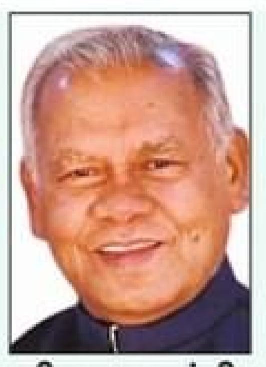

जीतनराम मांझी
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

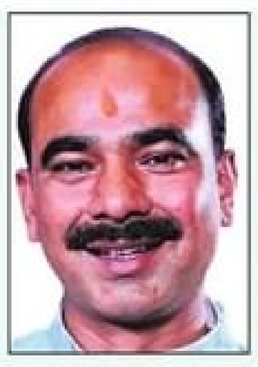

अजय टम्टा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री

अवार्ड समारोह और एक्सपो के आकर्षण

कार्यक्रम के विशेष आकर्षण एक्सपो में विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी भारतीय और वैश्विक कंपनियां अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के समापन सत्र में 15 कैटेगरी में 60 विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवाड्र्स से सम्मानित किया जाएगा।

प्रवेश संबंधी निर्देश

- मेट्रो से आने वाले प्रतिभागी गेट नंबर 10 से प्रवेश करें।
- कार से आने वाले प्रतिभागियों के लिए गेट नंबर सात से एंट्री होगी।

देश के शीर्ष विशेषज्ञ और लीडिंग इंडियन क्रिकेटर रखेंगे विचार

कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले आठ विचार-सत्रों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, परेश रावल, डॉ. विकास चतुर्वेदी, अनुराग सिंघी, अनिल भारद्वाज, नितिन जोशी, शुभ्रांशु सिंह, विनीत विजयवर्गीय, निनाद कार्पे, इरविन आनंद, रजनीश कुमार, थम्पी कोशी, मनीष शाह, डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य, सुनील चोपड़ा, अशोक सहगल, संजय कथूरिया, डॉ. आर.के. सिंह, यतिन शाह, सरवना कुमार, विशाल कौशिक और आरती रामकृष्णन जैसे उद्योग, नीति, नवाचार और डिजिटल जगत के अग्रणी चेहरे अपने विचार साझा करेंगे।

पूंजी, नीति और नवाचार पर केंद्रित पहला सत्र

- **फंडिंग का फ्यूचर :** सत्र में डॉ. शुभ्रांशु आचार्य, रजनीश कुमार और मनीष शाह एमएसएमई के लिए निवेश और पूंजी जुटाने के अवसरों पर विचार साझा करेंगे।
- **फ्यूचर रेडी एमएसएमई :** सत्र में अशोक सैगल, अनिल भारद्वाज और आर.के. सिंह नीति, प्रौद्योगिकी और विकास को जोड़ने की रणनीतियां बताएंगे। आरती रामकृष्णन और अनुराग सिंघी प्रेरक संबोधन देंगे
- **एमएसएमई रिइन्वेंशन :** सत्र में सरवना कुमार और निनाद कार्पे बताएंगे कि उद्यम 'सर्वाइवल से सस्टेनेबल स्केल' तक कैसे पहुंच सकते हैं। इन सत्रों का उद्देश्य उद्यमियों को पूंजी, नीति और नवाचार के व्यावहारिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है।

दूसरा हाफः ब्रांडिंग, ग्लोबल विस्तार और प्रेरक संवाद

- 'ब्रांड डिस्कवरी से लास्ट-माइल डिलीवरी तक : ओएनडीसी के थम्पी कोशी, इरविन आनंद और कैडी वेंचर्स के विशाल कौशिक डिजिटल वितरण और ब्रांड रणनीति पर चर्चा करेंगे।
- लोकल टू ग्लोबल : नितिन जोशी और डॉ. विकास चतुर्वेदी एमएसएमई को विश्वस्तरीय बनाने की रणनीतियां साझा करेंगे।
- फायरसाइड चैट में अभिनेता परेश रावल और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ अपने अनुभवों के माध्यम से प्रेरक संवाद करेंगे।

सम्मान समारोह और समापन

दिनभर चलने वाले इस आयोजन का समापन अवार्ड समारोह से होगा, जिसमें 15 श्रेणियों के 60 उत्कृष्ट उद्यमियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

ये प्रतिष्ठित संस्थान बने आयोजन के सहयोगी

इस आयोजन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारें राज्य साझेदार हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग सह-प्रायोजक है। मूर सिंघी नॉलेज पार्टनर, किआ ड्रिवेन बाय पार्टनर, निंबसपोस्ट शिपिंग एवं पूर्ति साझेदार, एक्सलरेट मीडिया इंफ्लुएंसर मार्केटिंग पार्टनर, 360 वन वेल्थ और मध्य प्रदेश सरकार एसोसिएट पार्टनर के रूप में जुड़ी हैं।

अपराध संक्षेप

कंधा टकराने के विवाद में युवक पर हमला

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के सरोजनी नगर में कंधा टकराने के विवाद में युवक पर नुकीले हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 25 वर्षीय रितिक बुरी तरह घायल हो गया। उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित दो अक्तूबर को रात खाना खाकर बाहर घूमने गया था। लक्ष्मीबाई नगर स्थित नवयुग पब्लिक स्कूल की तरफ से वापस लौटते समय मिनी मार्केट के पास एक परिचित युवक नौशाद से उसका कंधा टकरा गया। दोनों में बहस हो गई। इस बीच आरोपी के 6-7 साथी भी पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर नौशाद ने रितिक को थप्पड़ मार दिया। रितिक उसे धक्का देकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा किया और नौशाद ने उसके मुंह पर किसी नुकीली चीज से हमला करके उसे घायल कर दिया। ब्यूरो

लूटपाट में युवक को मारा चाकू, साथी को लगा

नई दिल्ली। बवाना इलाके में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कन्हैया कुमार (19) नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के बचाव करने पर चाकू बदमाश के साथी सलमान को ही जा लगा। पकड़े जाने के डर से युवक से मोबाइल लूटने वाले दो बदमाश भाग गए, जबकि घायल बदमाश को पीड़ित ने लोगों की मदद से दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला दर्ज कर पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। बवाना थाने में दर्ज प्राथमिकी में कन्हैया ने बताया कि दो अक्तूबर की सुबह फैक्टरी से नाइट शिफ्ट करने के बाद घर जाते समय तीन युवकों ने घेर लिया और मोबाइल फोन मांगा। नहीं देने चाकू मारने की धमकी दी। कन्हैया के विरोध करने पर दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। जेब से फोन निकालने के बाद जब बदमाश ने चाकू मारा तो वह पीछे हो गया, जिससे चाकू उसे पकड़े बदमाश को लग गया। ब्यूरो

एक्सिस बैंक में लगी आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में बुधवार तड़के एक्सिस बैंक में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग में कुर्सी और एक पंखा जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। दमकल विभाग के अनुसार बुधवार तड़के 4.12 बजे पिलर संख्या 672 के पास एक्सिस बैंक में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने देखा कि आग भूतल पर स्थित एक्सिस बैंक के एक केबिन में कुर्सियों और पंखे में लगी है। आस पास मौजूद लोगों ने बताया कि तड़के बैंक से धुआं निकलते देख घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मी तुरंत आग बुझाने में जुट गए। करीब आधे घंटे में आग पर काबू कर लिया। ब्यूरो

ढाई हजार लीटर से अधिक मिलावटी घी जब्त

पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, कई लोकप्रिय ब्रांड के लेवल का इस्तेमाल कर लोगों को खिला रहे थे घी के नाम पर मिलावट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए बुद्ध विहार, रोहिणी और दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों में चल रहे अवैध मिलावटी देसी घी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और इसके निकटवर्ती हरियाणा में 2,600 लीटर से अधिक मिलावटी घी जब्त कर राकेश गर्ग (38) और मुकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को दो गोदामों में छापा मारा। मिलावटखोर यहां मिलावटी घी को कई लोकप्रिय ब्रांड के लेवल के जरिये खपा रहे थे। एक माह के भीतर दिल्ली में मिलावटी घी की यह तीसरी बरामदगी है।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर पुखराज सिंह की टीम ने कुल 2,651 लीटर मिलावटी घी जब्त किया है। इनमें से 2,241 लीटर घी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बुद्ध विहार स्थित एक गोदाम में मिला।

इस गोदाम का मालिक राकेश गर्ग (38) है जबकि 410 लीटर घी हरियाणा के जींद में एक अन्य व्यक्ति मुकेश के गोदाम से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि जींद इकाई को सील कर दिया गया है और मिलावटी घी निर्माताओं के खिलाफ अपराध शाखा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मिलावटी घी खपाया जा रहा था। दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग भी छापेमारी में शामिल था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गर्ग पिछले दो वर्षों से इस अवैध व्यापार में कथित तौर पर शामिल है और हाल में उसने अपने कारोबार का विस्तार किया है।

विनिर्माण इकाई का संचालन करने वाला मुकेश हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में मिलावटी घी की आपूर्ति कर रहा था।

बरामद नकली घी और पुलिस की गिरफ्त में मिलावटखोर। अमर उजाला

ऐसे बनाते थे : थोक में घटिया गुणवत्ता वाला डालडा (वनस्पति घी), रिफाइंड तेल खरीदते थे, जिन्हें गर्म करके शुद्ध देसी घी जैसा बना दिया जाता था। असली स्वाद के लिए रसायन आधारित फ्लेवरिंग एसेंस यानी सुगंध, सिंथेटिक रंग और असुरक्षित पदार्थ मिलाए जाते थे। इस उत्पाद को देसी घी के प्रतिष्ठित ब्रांडों जैसे मदर डेयरी, अमूल, पतंजलि आदि के पैकेटों में पैक किया जाता था और डेयरियों, दुकानों और छोटे वितरकों को आपूर्ति की जाती थी।

150 रुपये प्रति लीटर मिलावटखोर, थोक विक्रेता कमा रहे थे 200 से 300

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपियों ने खुलासा किया कि मिलावटी देसी घी की उत्पादन लागत लगभग 200 रुपये प्रति लीटर आती है। वे इसे थोक विक्रेता को करीब 350 रुपये में बेच रहे थे। थोक विक्रेता करीब 200 से 300 रुपये का फायदा लेकर इसे फुटकर दुकानदारों को बेच रहे थे। अमूल घी 600 से 700 रुपये लीटर है। इसी तरह अन्य ब्रांड के घी का मूल्य भी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2025 को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से कुल 1,625 किलो और 15 सितंबर को 7,600 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था।

तो नकली घी पी रही दिल्ली...रहें सवाधान

घर पर ऐसे करें असली-नकली की पहचान

- **हथेली पर पिघलाकर देखें:** शुद्ध घी शरीर के तापमान पर तुरंत पिघल जाता है। अगर देर तक ठोस रहे या तेल जैसा चिपचिपा एहसास दे, तो उसमें वनस्पति तेल मिला हो सकता है।
- **खुशबू और रंग पहचानें:** असली घी की महक हल्की और मनभावन होती है, जबकि नकली में तेज या कृत्रिम गंध आती है। इसका रंग सुनहरा पीला और बनावट दानेदार होती है।
- **उबालने का तरीका:** शुद्ध घी उबालने पर हल्की मीठी खुशबू देगा और तुरंत पिघल जाएगा। नकली घी में बदबू आएगी और परतें अलग-अलग दिखेंगी। बहुत सस्ता घी अक्सर मिलावटी होता है।
- **फ्रिज टेस्ट:** घी को फ्रिज में रखें। अगर यह समान रूप से जम जाए तो शुद्ध है। परतें या अलग-अलग स्तर बनें तो मिलावट की आशंका।
- **आयोडीन टेस्ट:** पिघले घी में एक-दो बूंद आयोडीन डालें। अगर नीला रंग बने तो उसमें स्टार्च मिला है।

सेहत के साथ गाड़ी से भी कर रहे खिलवाड़

कंझावला में बना रहे थे नकली मोबिल ऑयल पांच गिरफ्तार, 2600 लीटर लुब्रिकेंट भी बरामद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कंझावला में नकली लुब्रिकेंट/मोबिल ऑयल निर्माण इकाई का भंडाफोड़ करते हुए दो मालिकों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2,600 लीटर नकली लुब्रिकेंट ऑयल और मशीनरी बरामद की हैं। बरामद नकली ऑयल की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि शाखा की आईएससी में तैनात इंस्पेक्टर कमल कुमार को कंझावला क्षेत्र में नकली लुब्रिकेंट/इंजन ऑयल निर्माण की सूचना मिली थी। जांच में पुलिस को पता चला कि सकलान अहमद उर्फ प्रिंस, अपने भाई सोहिद उर्फ अल्लू के साथ मिलकर निर्माण इकाई चला रहा है। पुलिस टीम ने छापा डाला और 2,600 लीटर नकली तेल, पैकेजिंग सामग्री जब्त की। अवैध निर्माण और वितरण नेटवर्क में शामिल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी गिरफ्तार तीन आरोपियों के नाम शकीलुद्दीन उर्फ शकील (38), शान मोहम्मद (36) और मोहम्मद सलमान (25) हैं। ये यहां काम करते थे।

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि इस इकाई का संचालन आगरा, यूपी निवासी प्रिंस और सोहिद अहमद उर्फ अल्लू नामक दो भाई कर रहे थे।

सांकेतिक

मशीनरी भी बरामद, नकली ऑयल की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई

फैक्ट्री परिसर मई 2025 में कंझावला निवासी अजीत से किराए पर लिया गया था। इससे पहले आरोपी 2022 से दिल्ली में ऐसी एक अवैध इकाई चला रहे थे। प्रतिष्ठित ब्रांडों के जाली लेबल, होलोग्राम और पैकेजिंग का उपयोग करके, वे असली जैसे दिखने वाले नकली उत्पाद बनाते थे। फिर नकली तेल को स्थानीय ऑटो दुकानों, वर्कशॉप और थोक विक्रेताओं को रियायती दरों पर बेचा जाता था।

आरोपी हर महीने आरोपी लगभग 8,000-10,000 लीटर नकली तेल (10 बोतलों वाले 800-1000 कार्टन) बनाकर बेचते थे, जिससे उन्हें लगभग 2.5 लाख प्रति माह की कमाई होती थी। नकली पैकेजिंग लगभग मूल ब्रांडिंग जैसी ही होती थी, जिससे आम खरीदारों या मैकेनिकों के लिए उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता था। शान मोहम्मद स्नातकोत्तर (एम.एससी. केमिकल इंजीनियरिंग) है। पहले वह फार्मा कंपनी में काम करता था।

युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की युवती की हत्या

दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना इलाके में युवती की हत्या के बाद पूछताछ करती पुलिस। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर (केएम पुर) में मंगलवार रात एक युवक ने अपनी महिला दोस्त की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी युवक फरार है।

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर आरोपी युवक की तलाश तेज कर दी है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मूलरूप से मस्जिद मोठ, एंड्रयू गंज, हौज खास, नई दिल्ली की रहने वाली 25 वर्षीय साक्षी प्रताप गली, नानक चंद बस्ती, कोटला मुबारकपुर में अकेली रहती थी। वह ओखला में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। सात अक्तूबर को रात 9.19 बजे घटना के संबंध में कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी। उसके मकान में किरायेदार महिला रहती है । उसका किसी से झगड़ा हो रहा है और आवाजें आ रहीं हैं।

दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में हुई वारदात, आरोपी फरार

पुलिस मौके पर पहुंची तो सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे के अंदर फर्श पर एक महिला का शव पड़ा मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित युवती एक युवक के साथ करीब तीन दिन से रह रही थी। पुलिस को मौके पर चाकू मिला है।

कमरे में चारों ओर खून बिखरा था और कमरे से शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस ने युवती के साथ को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। युवती के माता-पिता के बारे में पता नहीं लगा है।

ट्रैक्टर सवारों ने एएसआई को पीटकर किया अधमरा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। द्वारका नार्थ इलाके में चालान के लिए ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करने पर नाराज ट्रैक्टर मालिक ने दो साथियों के साथ एएसआई राजकुमार को पीट दिया। सिर पर डंडा लगने से राजकुमार बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे बिंदापुर थाने के एक सिपाही ने उन्हें हमलावरों से छुड़ाया। ट्रैक्टर मालिक को पकड़ लिया गया जबकि दो आरोपी भाग गए। पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

राजकुमार सपरिवार पालम कॉलोनी में रहते हैं। वह दिल्ली यातायात विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। उनकी तैनाती द्वारका सर्किल में है। द्वारका नार्थ थाने में दर्ज प्राथमिकी में राजकुमार ने बताया कि 6 अक्तूबर को द्वारका मोड़ एनएसयूटी रोड पर वाहनों का चालान कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक नो इंट्री होने के बावजूद जाने लगा। राजकुमार ने चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दी। एएसआई ने वीडियो बना लिया। कुछ दूर जाने पर उसपर सवार मालिक ट्रैक्टर से उतरा और साथियों के साथ मुझसे मारपीट करने लगा। हमलावरों ने डंडे से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसी दौरान सिपाही मोनू ने उसकी जान बचाई। ट्रैक्टर मालिक विरेंद्र सागवान को पकड़ लिया। पुलिस घायल एएसआई राजकुमार को इलाज के लिए पास के अस्पताल में लेकर गई।

द्वारका नार्थ इलाके की घटना, चालान के लिए ट्रैक्टर रोकने का कर रहा था प्रयास

अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी रैकेट पकड़ा, 3 दबोचे

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 808 ग्राम मादक पदार्थ

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तीन लोगों की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली-एनसीआर में चल रहे एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 808 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताा कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों सरोज उर्फ बाबू (30), राजकुमार (25) और दीपाली (22) के कब्जे से दो मोबाइल फोन, एक स्कूटर और नकदी भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि जांच 18 जुलाई को शुरू हुई जब एक टीम ने सीमापुरी इलाके में इकबाल कॉलोनी, पासौंडा, गाजियाबाद, यूपी निवासी सरोज उर्फ बाबू(30) पुत्र बसीर को 789 ग्राम हेरोइन से भरे एक प्लास्टिक बैग के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्लास्टिक पॉलिथीन को फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया, लेकिन हवलदार सिकंदर और टीम ने पीछा करने के बाद उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने दीपाली से यह पदार्थ खरीदा था और इसे गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी शिवम को दिया जाना था।

आरोपी स्थानीय ग्राहकों को छोटे पैकेटों में हेरोइन की आपूर्ति करते थे

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने 19 अगस्त को राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 19 ग्राम हेरोइन बरामद की, जबकि 25 सितंबर को दीपाली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी स्थानीय ग्राहकों को छोटे पैकेटों में हेरोइन की आपूर्ति करते थे। पुलिस ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

संदिग्ध हालात में छत से गिरीं दो महिला मित्र, एक की मौत

आखिरी बार युवती के भाई ने दोनों को छत पर साथ टहलते हुए देखा था

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हौजकाजी इलाके में मंगलवार रात छत पर टहल रहीं दो सहेलियां संदिग्ध हालात में चौथी मंजिल से गिर गई। दोनों को लोकनायक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने सुनीता(25) को मृत घोषित कर दिया। तृप्ति (19) गंभीर है। अभी तक की जांच में पुलिस हादसे की आशंका जता रही है। तृप्ति के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले अपनी बहन को नीचे आने के लिए कहने छत पर गया था तो दोनों बातचीत कर रही थी।

मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को रात पौने नौ बजे एक लड़का और लड़की के छत से छलांग लगाने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सुनीता गंभीर अवस्था में पड़ी मिली। उसके सिर में गंभीर चोट थी। पता चला कि तृप्ति के परिजन उसे लोक नायक अस्पताल ले गए हैं। पुलिस सुनीता को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुनीता अपने परिजनों के साथ रहती थी। पिता का नाम रमेश है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य हासिल किए। अस्पताल पहुंची पुलिस को पता चला कि तृप्ति बयान देने की हालत में नहीं है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सुनीता सीधा गिरी जबकि तृप्ति गिरने के दौरान तार में उलझ गई थी।

सुनीता फाइल फोटो

फरवरी में हुई थी सुनीता की शादी : सुनीता के पिता रमेश ने पुलिस को बताया कि सुनीता की शादी इसी साल फरवरी माह में यूपी निवासी कपिल से हुई थी। शादी के सात आठ दिन बाद सुनीता को लकवा हो गया था। पिता उसे इलाज के लिए दिल्ली ले आए थे तब से वह परिजनों के साथ रह रही थी। आस पास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि दोनों अकसर घरों की छतों पर साथ-साथ टहलती थीं।

वाटर स्टोरेज टैंक की छत टूटी, तीन किशोर घायल

नई दिल्ली। शाहबाद डेयरी के रोहिणी सेक्टर-28 स्थित बागवान अपार्टमेंट में बने वाटर स्टोरेज टैंक की छत अचानक भरभराकर गिर गई। टैंक की छत पर बैठे सार्थक, जितेंद्र और उनका एक और साथी करीब सात फीट गहरे टैंक में गिर गए। तीनों की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। गनीमत रही कि तीनों को मामूली चोट आई। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

रविवार शाम पार्क में बने वाटर स्टोरेज टैंक पर तीन किशोर खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक टैंक की छत टूट गई और तीन किशोर सात फीट गहरे टैंक में गिर गए। गनीमत थी कि उस समय टैंक में पानी कम था। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत टैंक से किशोरों को बाहर निकाला। बागवान अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमर ने बताया कि टैंक के निर्माण डीडीए ने कराया था। उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि घटिया साम्रगी की वजह से टैंक की छत जर्जर थी। शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सुभाष नगर फायरिंग मामले में वांछित आरोपी सदर थाना रोड, पहाड़गंज निवासी साहिल उर्फ मयंक मनचंदा उर्फ जानू (24) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त बलेनो कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी अपने साथी के साथ वारदात के बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए रुड़की, उत्तराखंड भाग गया था।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, दिल्ली में गोलीबारी की एक घटना की सूचना 2 अक्तूबर को मिली थी। इसमें दो अज्ञात हमलावर एक कार से आए और सुभाष नगर, राजौरी गार्डन निवासी व्यक्ति के घर गोलीबारी करके भाग गए। पुलिस को मौके से कई खोखे मिले। अपराध शाखा की जांच में पता लगा कि घटना में मयंक मनचंदा नामक व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने पड़ताल के बाद 4 अक्तूबर को दिल्ली के राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास से उसे एक मुखबिर की सटीक सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसके चाचा (पीड़ित) उसके पिता मनोज कुमार मनचंदा की हत्या के मुकदमे में समझौते का दबाव बना रहे था। पिता की 2022 में पहाड़गंज, दिल्ली में जोगिंदर शर्मा और अन्य लोगों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में उसने अपने दोस्त ऋषभ पुरी की मदद से चाचा को सबक सिखाने का फैसला किया। ब्यूरो

घरेलू विवाद | दक्षिण दिल्ली में चौंकाने वाली घटना ....पति से विवाद में देर रात महिला ने घटना को दिया अंजाम

पत्नी ने आठ साल के रिश्ते पर डाला खौलता तेल, फिर रगड़ी मिर्च

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के आंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में साधना नाम की महिला ने घरेलू विवाद में सो रहे अपने पति दिनेश पर खौलता तेल डाल दिया और घावों पर लाल मिर्च रगड़ दी। पति चीखने लगा तो महिला ने धमकी दी कि चिल्लाएगा तो और गर्म तेल डाल दूंगी। असहनीय पीड़ा से तड़पते दिनेश की चीख सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे झुलसी हालत में अस्पताल पहुंचाया।

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी हालत गंभीर बताई गई है। चौहान ने बताया कि पति व पत्नी के बीच सीएडब्ल्यू सेल में विवाद चल रहा था। तीन अक्तूबर को 28 वर्षीय दिनेश नाम के युवा को गंभीर रूप से झुलसी हालत में सफदरजंग अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। आंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन पुलिस को दिए बयान में दवा कंपनी में कार्यरत दिनेश ने बताया कि वह दो अक्तूबर को काम से देर रात घर लौटा। खाना खाने के बाद सोने चला गया। पत्नी और बेटी पास में सो रही थीं।

धमकी दी-शोर मचाया तो और गर्म तेल डाल दूंगी, पति की चीखें सुन पहुंचे पड़ोसी

बकौल दिनेश, करीब सवा तीन बजे मुझे अचानक पूरे शरीर में तेज जलन महसूस हुई। आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझ पर खौलता तेल डाल रही है। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए पुकारता, उसने मेरे जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी आए और मुझे अस्पताल ले गए।

पड़ोसी बचाने आए, महिला हो गई घर से गायब

शोर सुनकर पड़ोसी और नीचे वाली मंजिल पर रहने वाले मकान मालिक का परिवार दौड़कर मौके पर पहुंचा। मकान मालिक की बेटी अंजलि ने बताया कि मैं अपने पिता के साथ ऊपर गई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था और अंकल की चीखने की आवाज आ रही थी। हमने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो काफी देर बाद गेट खुला। हमने देखा कि दिनेश अंकल दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी थी। अंजलि ने बताया कि जब मेरे पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो महिला ने कहा वह पति को अस्पताल ले जा रही है। महिला ऑटो बुलाने निकली और दूसरी ओर चली गई। शक होने पर एक ऑटो से पिता जी दिनेश अंकल को अकेले अस्पताल ले गए।

महिला के खिलाफ केस दर्ज सीएडब्ल्यू भी गया था मामला

पीड़ित के अनुसार दंपति की शादी को आठ साल हो चुके हैं और उनके रिश्ते में खटास आ गई है। दो साल पहले उनकी पत्नी ने सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मामला समझौते के जरिये सुलझ गया था। दिनेश की पत्नी पर बीएनएस की धारा 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 124 (तेजाब से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 326 (चोट पहुंचानाए पानी में डुबोना, आग लगाना या विस्फोटक पदार्थ आदि से नुकसान पहुंचना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीयू के रोजगार मेले में उमड़े छात्र

1200 छात्र ऑन द स्पॉट नौकरी के लिए हुए शॉर्टलिस्ट, 61 कंपनियां मेला स्थल पर पहुंचीं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीयू के कैंपस प्लेसमेंट सेल की ओर से बुधवार को आयोजित रोजगार मेले में बड़ी तादाद में छात्र उमड़ पड़े। डीयू स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपरपज हॉल में छात्रों के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव का आयोजन किया गया था। छात्रों को रोजगार देने के लिए 61 कंपनियां पहुंची थी। इसमें 14 कंपनी रोजगार मेले में ऑनलाइन शामिल हुई।

रोजगार मेले में आने वाले छात्र काफी उत्साहित दिखे। छात्र नौकरी पाने के लिए एकदम पेशेवर तरीके से तैयार होकर आए थे। कोई छात्र पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप की तलाश में आया था तो कोई छात्र नौकरी पाने के लिए रोजगार मेले में पहुंचा।

छात्रों के भीड़ देखते हुए टोकन की व्यवस्था की गई थी। मेले में शामिल होने के लिए आने वाले छात्रों को टोकन जारी किया गया। एक छात्र तीन कंपनियों से नौकरी के लिए संपर्क कर सकता था। छात्र अलग-अलग कंपनी के डेस्क पर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन करते दिखे। छात्रों का स्किल टेस्ट भी लिया गया। डीयू डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस बार ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया है। छात्र जब यहां से निकलेंगे तो रोजगार के साथ निकलेंगे। छात्रों और कंपनी के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। छात्रों को नौकरी और कंपनी को एक अच्छा उम्मीदवार मिले।

रोजगार मेले में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेते कंपनी के अधिकारी। ब्यूरो

12 लाख तक का वार्षिक पैकेज

उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में आईटी, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग सहित अलग-अलग क्षेत्र की कई स्टार्ट कंपनियां शामिल हुई। रोजगार मेले में 1500 छात्रों के पास नौकरी और इंटर्नशिप पाने का मौका था। इंटर्नशिप के लिए कंपनियों ने कम से कम 12 हजार रुपये और अधिकतम 30 हजार रुपये प्रस्तावित किए थे। जबकि नौकरी के लिए अधिकतम वार्षिक पैकेज करीब 12 लाख था।

7200 से ज्यादा ने कराया पंजीकरण

डीयू सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की इंचार्ज और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर में ज्वाइंट डीन प्रोफेसर हेना सिंह ने बताया कि एक दिवसीय रोजगार मेले के लिए 7200 से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया था। मगर, छात्रों के उत्साह को देखते हुए बिना पंजीकरण करने वाले छात्रों को भी इसमें शामिल होने का मौका दिया गया। रोजगार मेले शामिल होने के लिए शाम तक चार हजार से ज्यादा छात्र पहुंचे। शाम चार बजे तक ऑन द स्पॉट 1200 छात्रों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया।

साक्षात्कार में हुआ चयन

मैं थर्ड ईयर में हूं और बीए वोकेशनल विषय की पढ़ाई कर रहा हूं। रोजगार मेले में शामिल होने वाली एक कंपनी ने मार्केटिंग एंड सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद साक्षात्कार के दौरान चयन कर लिया है। - **अखंड प्रताप सिंह, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज**

मैं रोजगार मेले में इंटर्नशिप के लिए आई थी। कॉलेज में बीए प्रोग्राम की पढ़ाई कर रही हूं। मेरा मानना है कि जब ग्रैजुएशन करके कॉलेज से निकली तो डिग्री के साथ स्किल भी हो। इंटर्नशिप के दौरान कंपनी के साथ स्किल डेवलप कर सकूंगी। **-सुदीक्षा तिवारी, रामजस कॉलेज**

जामिया और एनआईएसई ने साइन किया एमओयू

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रिड एकीकरण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, कौशल विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

समारोह में जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी और एनआईएसई के महानिदेशक प्रो. मोहम्मद रिहान ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने इस अवसर पर कहा कि यह साझेदारी देश के सतत ऊर्जा भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, पीवी पुनर्चक्रण और ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम पर संयुक्त अनुसंधान करेंगे। साथ ही, एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधन साझा करने की योजना है। ब्यूरो

जामिया में स्प्रिंगर नेचर रिसर्च टूर आयोजित

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने शिक्षा मंत्रालय और आईसीएसएसआर के सहयोग से स्प्रिंगर नेचर रिसर्च टूर 2025 के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी संकाय सभागार में आयोजित इस आयोजन में शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों ने वैश्विक शोध प्रवृत्तियों और शैक्षणिक प्रकाशन के भविष्य पर चर्चा की। यह 37-दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 17 शहरों के 29 संस्थानों को कवर करता है, जिसका उद्घाटन आईसीएसएसआर कार्यालय में फ्लैग-ऑफ समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रिसर्च एंबेसडर्स का सम्मान समारोह था, जिसमें शैक्षिक अध्ययन विभाग के शोधार्थी इंजमामुल हक, एजाज अहमद और अरमान फातमा को स्प्रिंगर नेचर का हॉल ऑफ फेम पुरस्कार मिला। जामिया में कुल चार शोधार्थियों को यह सम्मान मिला, जिनमें तीन विभाग से हैं। इस दौरान कुलपति प्रो. मजहर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रो. महताब आलम रिजवी, आईसीएसएसआर के प्रो. धनंजय सिंह और स्प्रिंगर नेचर के कई अधिकारी उपस्थिति रहे। ब्यूरो

कैंपस डायरी

जामिया की बास्केटबॉल टीम ने उदघोष-2025 में जीता खिताब

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने आईआईटी कानपुर में तीन से पांच अक्तूबर तक आयोजित एशिया के सबसे बड़े कॉलेज खेल महोत्सव उदघोष-2025 में बास्केटबॉल का खिताब अपने नाम किया है। कप्तान मोहम्मद अमन के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन, उत्कृष्ट टीम वर्क और खेल भावना के साथ चैंपियनशिप जीती है। खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने टीम की मेहनत की सराहना की, जबकि रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने भविष्य के टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दीं। खेल निदेशक प्रो. नफीस अहमद ने खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो

जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान शुरू

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी) जेएनयू ने वार्षिक सदस्यता अभियान 2025-26 की औपचारिक शुरुआत कर दी है। यह अभियान 14 अक्तूबर तक चलेगा। इस अवसर पर एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जेएनयू के अधिक छात्रों को उस विचारधारा से जोड़ना है जो छात्र को केवल अकादमिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना से भी संपन्न बनाती है। एबीवीपी छात्र हितों और सकारात्मक परिवर्तन के लिए समर्पित संगठन है। एबीवीपी जेएनयू सचिव प्रवीण पीयूष ने कहा कि यह अभियान छात्रों में जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता जगाने का प्रयास है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील है वह इस सप्ताह चल रहे अभियान में शामिल होकर सेवा, समर्पण और राष्ट्रनिर्माण की इस यात्रा का हिस्सा बनें। ब्यूरो

डीयू में पुस्तकालय एवं पांडुलिपियों की भूमिका विषय पर चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में विकसित भारत में पुस्तकालय एवं पांडुलिपियों की भूमिका विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के कुलाधिपति पद्मश्री डॉ. हरमोहिंदर सिंह बेदी शामिल हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रो. केपी सिंह ने कहा कि भारत में डीयू पुस्तकालय विज्ञान विभाग सबसे बेहतर शिक्षण करने वाला विभाग है जहां स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा के साथ शोध के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। वहीं, डीयू पुस्तकालय विभाग छात्र संगठन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरके भट्ट ने छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया। ब्यूरो

मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के सामाजिक समावेश अध्ययन केंद्र (सीएसएसआई) और अकादमिक मामले के डीन कार्यालय ने कम टुगेदर (कोटो) के सहयोग से 'मेंटल हेल्थः ब्रेकिंग स्टिग्मा एंड प्रोमोटिंग सोशल इनक्लूजन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2025 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इससे जुड़े स्टिग्मा को दूर करने पर चर्चा की। कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी के मार्गदर्शन में प्रो. तनुजा ने इसकी अगुवाई की। मुख्य वक्ता अल्फोंस कन्ननथनम और ऑस्ट्रिया की राजदूत कैथरीना वीसर ने मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक मुद्दा बताते हुए सहयोग और समावेश की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला में इंटरैक्टिव सत्र, गतिविधियां और परामर्श सुविधाओं पर चर्चा हुई। ब्यूरो

स्कूल के छात्रों ने पढ़ा साइबर सुरक्षा का पाठ

नई दिल्ली। जामा मस्जिद स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर-1 (उर्दू माध्यम) में बुधवार को स्कूली छात्रों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। इसमें छात्रों को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित कई दूसरे विषयों के संबंध में जागरूक किया गया।

विद्यालय के प्राचार्य डॉ. गय्यूर अहमद ने कहा कि छात्रों के दैनिक जीवन में साइबर सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है। छात्र डिजिटल नागरिक बनें और अपनी सीख को साथियों एवं परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। इस कार्यक्रम में एसीपी कमल शर्मा, एसएचओ आदेश प्रकाश सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। ब्यूरो

डीयू : वार्षिकोत्सव से लेकर रैली तक के लिए एडवाइजरी जारी

कॉलेज-छात्रावास आयोजनों के संचालन-प्रबंधन के लिए होंगे जिम्मेदार, 72 घंटे पहले पुलिस को देनी होगी सूचना

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सभी कॉलेजों/छात्रावासों/ केंद्रों और संस्थानों में कार्यक्रमों और सभाओं (वार्षिक उत्सव/हॉस्टल नाइट आदि) का सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए डीयू प्रॉक्टर कार्यालय ने सात बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है।

इसमें सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी करने से लेकर लाइजन अधिकारी की नियुक्ति, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन तैयारियां, पुलिस को पूर्व में सूचना देने सहित कई दूसरे बिंदु शामिल है।

सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी करेंगे कॉलेज

कार्यक्रम को लेकर संबंधित कॉलेज सोशल मीडिया पर भी एडवाजरी जारी करेंगे। इसमें कार्यक्रम की प्रकृति, समय, प्रवेश आवश्यकताएं/पास, यातायात व्यवस्था और प्रवेश/निकास का ब्यौरा देना होगा। कॉलेज/छात्रावास परिसर के भीतर या कार्यक्रम स्थल पर आपातकालीन व्यवस्था के लिए प्राथमिक चिकित्सा दल, एक एम्बुलेंस और अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे। वीआईपी और सामान्य लोगों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकासी की व्यवस्था निर्धारित करेंगे। स्वयंसेवकों और निजी सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता से आकस्मिक निकास मार्गों की योजना और पूर्वाभ्यास पहले से किया जाएगा।

सुरक्षा गार्ड व बाउंसर भी हो सकेंगे तैनात

एडवाइजरी में यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में स्थानीय एसएचओ को कार्यक्रम से 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रवेश/निकासी, पार्किंग क्षेत्र की पीए सिस्टम से घोषणा करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे। किसी भी कॉलेज/छात्रावास या संस्थान के परिसर में होने वाले आयोजनों के संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी खुद की होगी। दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। आयोजक प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड और बाउंसर तैनात कर सकेंगे। पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में मदद के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती भी अनिवार्य होगी।

एडवाइजरी के अनुसार सभी जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, सभाओं, समारोहों और कार्यक्रमों के संबंध में कॉलेज, संस्थान और छात्रावास दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक समर्पित लाइजन अधिकारी नियुक्ति कर सकते है। अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान हर समय उपलब्ध रहना होगा। स्थानीय पुलिस के साथ आवश्यक विवरण साझा करना होगा। इसमें कार्यक्रम का समय से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति, अपेक्षित भीड़, प्रवेश के तरीके, कार्यक्रम का स्वरूप, उपस्थिति पर प्रति घंटा अपडेट और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस व करुणा का अद्भुत संगम : सिरसा

पर्यावरण मंत्री ने खालसा कॉलेज में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में लिया हिस्सा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस, करुणा, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक भाईचारे का अद्भुत संगम है। दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में गुरु तेग बहादुर स्टडी सेंटर स्थापित कर रही है जहां गुरु साहिब के जीवन, दर्शन और योगदान पर गहन अध्ययन व शोध होंगे। बुधवार को ये जानकारी पर्यावरण मंत्री और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी।

सिरसा ने खालसा कॉलेज में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लिया। इसमें दुनियाभर के प्रमुख इतिहासकार, विद्वान व शिक्षाविद शामिल हुए और गुरु साहिब के जीवन, दर्शन व बलिदान पर विचार साझा किए। बृहस्पतिवार को भी सेमिनार जारी रहेगा। सेमिनार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमन मिलकर कर रहे हैं। इस मौके पर मौके पर डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलों, एनपीएस चड्ढा, विक्रमजीत सिंह साहनी, सुखबीर सिंह कालरा, प्रो हरबंस सिंह सहित सभी कॉलेजों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

सेमिनार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा। अमर उजाला

यहां बोलना गौरव की बात : सिरसा

उद्घाटन सत्र में सिरसा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व का क्षण है कि जिस कॉलेज से उन्होंने शिक्षा पाई उसमें गुरु तेग बहादुर के जीवन और संदेश पर इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होने का उन्हें मौका मिला। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार नवंबर में लाल किले पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये वही जगह है जहां गुरु साहिब ने शहादत दी थी। यहां प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लेजर शो के जरिए गुरु साहिब के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

उपराष्ट्रपति से मिले दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति

नई दिल्ली। डीयू कुलपति योगेश सिंह ने भारत के उपराष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की।

उन्होंने उपराष्ट्रपति को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, उन्नत शोध कार्य, छात्राओं के बढ़ते नामांकन, हॉस्टल निर्माण, नए कॉलेज व परिसरों की स्थापना सहित कई दूसरे विषयों के बारे में अवगत कराया। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने शिक्षा के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए छात्रों से नशे, तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों से दूर रहने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन से खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। ब्यूरो

उपराष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति । अमर उजाला

एमएड में दाखिले के लिए ओपन हाउस आज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी के एमएड (स्पेशल एजुकेशन) प्रोग्राम में दाखिले के लिए द्वारका कैंपस में बृहस्पतिवार को ओपन हाउस का आयोजन किया जाएगा।

उम्मीदवार को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम 96 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ में लाने होंगे। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। काउंसलिंग के दिन ही दस्तावेज सत्यापन के बाद सीटों का आवंटन होगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है।

कथक के जरिए प्रस्तुत हुईं साहस भरी कहानियां

नई दिल्ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टेन ऑडिटोरियम में बुधवार को दो दिवसीय ललितअर्पण महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस वर्ष इस महोत्सव को 'अंतः शक्तिः साहस और आशा' थीम के साथ दर्शकों के बीच पेश किया गया। बीती शाम के आयोजन में कथक की प्रस्तुति के माध्यम से साहस, संघर्ष और जीवन को केंद्र में रखते हुए तीन कहानियों को पेश किया गया।

अग्निपंख नाम से प्रस्तुत इस कथक कहानी में तीन साहसी व्यक्तित्वों को दर्शाया गया। इसमें एक ऑटिस्टिक पियानो वादक, एक ट्रांसजेंडर, और एक एसिड अटैक सर्वाइवर की वास्तविक कहानियां शामिल थीं। इन कहानियों को कलाकार ने बहुत ही खूबसूरत कथक के माध्यम से जीवंत किया। दिखाया गया कि कैसे तीनों ने अपने साहस के बलबूते विपरीत परिस्थितियों में भी समाज एक जगह बनाई।

इसके बाद नृत्यश्री अलकनंदा ने अपनी एकल प्रस्तुति में भाव, लय और ऊर्जा के अद्भुत संतुलन से यह सिद्ध किया कि जीवन की कठिनाइयां भी साधना बन सकती हैं। उनका कैंसर से संघर्ष के बाद मंच पर लौटना उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण रहा। संवाद

महोत्सव में नृत्य की प्रस्तुति देतीं नृत्यांगना शोवना नारायण । भूपिंदर सिंह

जीएनआईओटी को बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट इन इंडिया अवार्ड

ग्रेटर नोएडा (वि)। जीएनआईओटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जीआईएमएस को बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट इन इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। संस्था को दिल्ली में एलाइट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एजुकेशन कॉनक्लेव 2025 सह नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश पचौरी ने यह खिताब प्रदान किया। कार्यक्रम एलाइट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा हिमालयन आशियाना ट्रस्ट (एचएटी) के सहयोग से किया गया। संस्था की ओर से वाइस प्रेसीडेंट सीआरसी जितेंद्र वशिष्ठ ने अवार्ड प्राप्त किया। सीईओ स्वदेश कुमार सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय फैकल्टी, स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया। चैयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता और वाइस चेयरमैन गौरव गुप्ता ने जीएनआईओटी परिवार का धन्यवाद किया। निदेशक डॉ. भूपेंद्र सोम ने कहा कि सम्मान हम सभी के लिए गौरव का विषय है।

ट्रेंड

सौभाग्य व ऊर्जा का प्रतीक मानतीं हैं पूर्वांचल की महिलाएं

करवा चौथ पर पूर्वांचल की सुहागिनों में बढ़ा संतरंगी सिंदूर का क्रेज

काजल कुमारी

नई दिल्ली। राजधानी की बाजारों में करवा चौथ का त्योहार आते ही चहल-पहल बढ़ गई है। सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, साकेत और नेहरू प्लेस , चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, सदर बाजार जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारी का माहौल चरम पर है।

खास बात यह है कि इस बार पूर्वांचल की सुहागिनों के बीच संतरंगी(ऑरेंज शेड) वाले सिंदूर का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। बिहार, उत्तरप्रदेश और झारखंड की महिलाओं का मानना है कि यह रंग न सिर्फ पारंपरिक लाल का विकल्प है, बल्कि इसे सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक भी है।

तैयारी करवाचौथ की

बाजारों में सजी दुकानों पर महिलाएं पारंपरिक साज-सज्जा का सामान खरीदने में व्यस्त हैं। पूजा के करवे, छन्नी, रंग-बिरंगी थालियां, दीये और चुनरियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि करवा चौथ से 10 दिन पहले ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी और अब हर दिन सैकड़ों महिलाएं खरीदारी करने आ रही हैं। लाजपत नगर की दुकानदार रीना शर्मा बताती हैं कि इस बार महिलाएं पारंपरिक सिंदूर की जगह संतरंगी शेड को ज्यादा पसंद कर रही हैं।

यह न सिर्फ नया ट्रेंड है, बल्कि सुहाग का आधुनिक प्रतीक भी बन गया है। वहीं, सरोजिनी नगर में पूजा सामग्री बेचने वाले विक्रेता श्याम का कहना है कि इस साल करवा और थालियों की बिक्री में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

संतरंगी सिंदूर। संवाद

शाम होते ही बाजारों में बढ़ जाती है रौनक

शाम होते ही बाजारों में रौशनी और साज-सज्जा से माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। महिलाएं सजी-धजी दुकानों के सामने अपनी सहेलियों संग सेल्फी लेती नजर आती हैं। हर चेहरे पर करवा चौथ की उमंग, आस्था और अपने जीवनसाथी के लिए शुभकामनाओं की झलक दिखाई देती है। यह त्योहार न सिर्फ सौंदर्य और परंपरा का संगम है, बल्कि प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है।

रखीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

करवा चौथ के उपलक्ष्य में सजी रंगारंग सांस्कृतिक शाम

नई दिल्ली। करवाचौथ के उपलक्ष्य में एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर परिसर में बुधवार को एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला कर्मचारियों ने पारंपरिक परिधानों में सजे-संवरे हुए नृत्य, गीत-संगीत और रस्मों के माध्यम से करवाचौथ के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को खूबसूरती से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने मेहंदी लगवाकर उपस्थित महिलाओं को करवाचौथ की शुभकामनाएं दीं और कहा कि करवाचौथ केवल व्रत या परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में समर्पण, प्रेम और परिवार के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। ऐसे आयोजन कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष रेखा रानी सहित निगम की कई महिला अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहीं। उन्होंने सभी को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करवाचौथ नारी शक्ति और भारतीय परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जिसे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। ब्यूरो

आरंभ की संध्या में गूंजे युवा कलाकारों के सुर

नई दिल्ली। इंडिया हैबिटैट सेंटर बुधवार की शाम सुरों और रागों की मधुर छटा से सराबोर रही। रजा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित श्रृंखला आरंभ के 30वें संस्करण में युवा कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीत लिया।

बता दें, कि आरम्भ रजा फाउंडेशन की एक विशेष पहल है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और वादन के क्षेत्र में नई पीढ़ी को मंच देना साथ ही, परंपरा और नवाचार के संगम को सहेजना है। अब तक इस श्रृंखला के 29 आयोजनों में 75 से अधिक युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। संध्या का आगाज वायलिन वादक साकेत साहू ने राग पूर्या धनश्री से किया। उनके सधे हुए सुरों और नाद के विस्तार ने सभागार में अद्भुत संगीत वातावरण रचा। सुर और लय के इस सुंदर संवाद में तबले पर उनका साथ दे रहे थे जहीन खान, जो उस्ताद अकरम खान के शिष्य हैं।

वहीं, साकेत की प्रस्तुति के बाद मंच पर आईं कोल्हापुर की युवा गायिका चिन्मयी आठले ओक। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने माहौल को और भी सुरीला बना दिया। उन्होंने राग तिलक कमोद में मोरी पथ राखो की भावनात्मक प्रस्तुति दी, जिसके बाद द्रुत एकताल में तराना गाकर अपनी गायकी की गहराई दिखाई। साचो तेरो नाम और चतुर सुघर बलमा जैसी रचनाओं ने उनकी गायन शैली में निहित परंपरा और नव्यता का सुंदर संगम दर्शाया। ब्यूरो

संयम और समय, दोनों ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। -लियो टॉल्स्टॉय

जिन वैज्ञानिकों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनका क्वांटम टनलिंग संबंधी शोध, जिसके अनुसार अति सूक्ष्म कण दीवार को भेदते हुए ऐसे गुजरते हैं, जैसे उसमें कोई सुरंग हो, क्वांटम भौतिकी के अधिक जटिल रहस्यों को सुलझाने की दिशा में यकीनन एक प्रस्थान बिंदु बनेगा।

सुरंग से रोशनी

तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों-जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को क्वांटम टनलिंग के क्षेत्र में अपने जिस शोध के लिए वर्ष 2025 के भौतिकी के नोबेल सम्मान के लिए चुना गया है, वह क्वांटम भौतिकी के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में यकीनन एक मील का पत्थर है। उल्लेखनीय है कि यह शोध इस बारे में है कि क्या परमाणु, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण किताबों और गेंद जैसी आकार में बड़ी वस्तुओं की तुलना में अलग व्यवहार करते हैं। इसको यों समझें कि गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम के जादुई संसार में सूक्ष्म कण दीवार को ऐसे पार कर लेते हैं, मानो वहां कोई अवरोध ही न हो। हालांकि, यह कोई जादू नहीं, बल्कि इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं और यह प्रक्रिया प्रकृति में हर समय चलती रहती है। गौरतलब है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होने में भी यही प्रक्रिया काम करती है। सूर्य के केंद्र में, हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जुड़ना होता है, लेकिन वे आम तौर पर एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्वांटम टनलिंग उन्हें इस अवरोध को पार करने और संलयित होने में मदद करती है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जो हमारे सौरमंडल को रोशन करती है। अब से पहले यह माना जाता था कि टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण जैसे क्वांटम प्रभाव केवल परमाणुओं या फोटॉनों जैसे कणों के साथ ही होते हैं, यानी ऐसे कण, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस की वैज्ञानिकत्रयी ने साबित किया कि क्वांटम की दुनिया के कायदे उन वस्तुओं में भी काम कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि दिखाई दे रहे हमारे संसार और क्वांटम की दुनिया के बीच की सीमा उतनी कठोर नहीं भी हो सकती है, जितनी समझी जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत में भी 2023 में क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम

संचार प्रणालियां और क्वांटम सेंसर विकसित करना है। देश भर के अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय इस अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन प्रणालियों के व्यवहार में आने पर संचार, औषधि, मौसम पूर्वानुमान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में देश बड़ी छलांग लगा सकता है। विज्ञान की जटिल उपलब्धियां अक्सर आम लोगों की समझ से दूर होती हैं, लेकिन इस बार का भौतिकी का नोबेल पुनः याद दिलाता है कि शोध का सौंदर्य 'वर्तमान में उपयोगिता' न होकर 'दीर्घकालिक समझ' में होता है। जैसे एक्स-रे की खोज ने चिकित्सा का चेहरा बदला, उसी तरह क्वांटम टनलिंग का यह शोध भविष्य में निस्संदेह भौतिकी की सीमाओं को ही पुनर्परिभाषित करेगा।

लंबे युद्ध के सबक

निश्चित रूप से फलस्तीन पीड़ित है, लेकिन इसका कारण हमास है। जो लोग इस्राइल विरोधी रैलियां निकालकर 'तत्काल युद्ध विराम' का राग अलाप रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सात अक्तूबर, 2023 से पहले तक युद्ध विराम ही था, जिसका हमास ने सबसे भयावह तरीके से उल्लंघन किया।

हालांकि यह तय नहीं है, लेकिन अगर इस हफ्ते गाजा में युद्ध रुक जाता है, तो मेरा मानना है कि इससे मिलने वाले सबक को लेकर एक अन्य बहस छिड़ सकती है। माया एंजेलो की चेतावनी पर वर्ष 1988 में ही यकीन करना चाहिए था, जब हमास ने अपनी स्थापना के वक्त ही यहूदियों का कत्लेआम करने की मंशा जाहिर की थी। लेकिन वैचारिक सुविधा के कारण इस्राइल हमास को बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए विभाजित फलस्तीनी राजनीति अनुकूल थी और अंतरराष्ट्रीय जगत भी हमास को उखाड़कर फेंकने के प्रति अनिच्छुक था। इस दुर्दांत समूह को सात अक्तूबर, 2023 तक बर्दाश्त किया गया, जबकि उस दिन मारे गए 1,200 लोगों के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

ब्रेट स्टीफेंस
द न्यूयॉर्क टाइम्स

हमास और इस्राइल के बीच लगातार संघर्ष के बावजूद गाजा पर नियंत्रण करने की इस्राइल की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि जैसा कि *व्हाइल इस्राइल स्लीप्ट* नामक किताब के सह-लेखक याकोव काट्ज ने मुझे लिखा, आयरन डोम जैसी तकनीकों के चलते इस्राइल इस भ्रम में रहा कि 'वह अभेद्य' है। लेकिन सात अक्तूबर को इस्राइल की सिग्नल इंटेलिजेंस, मिसाइल इंटरसेप्टर, दुरुस्त बाड़ और भूमिगत अवरोध जैसी उच्च तकनीकें हमास के कम तकनीकी क्षमता वाले पैराग्लाइडरों और बुल्डोजरों के आगे अनुपयोगी साबित हुईं।

डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था, 'कमजोरी उत्तेजक होती है।' लेकिन कमजोरी का आभास भी उत्तेजक होता है। हमास के दिवंगत नेता याह्या सिनवार ने तभी इस्राइल की कमजोर ग्रंथि का अंदाजा लगा लिया था, जब इस्राइल ने अपने सिर्फ एक सैनिक गिलाद शलित के बदले में उसे और अन्य सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। लेकिन सात अक्तूबर के हमले से कुछ महीनों पहले तक इस्राइल इतना कमजोर कभी नहीं दिखा था, क्योंकि नेतन्याहू सरकार ने न्यायिक 'सुधार' के लिए काफी जोर लगाया था।

इस्राइल की सरकार से बेहतर तो वहां के आम लोग हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण साठ वर्षीय सेवानिवृत्त जनरल नोआम टिबोन हैं, जो अपनी पत्नी गैली के साथ गाड़ी चलाकर अपने बेटे आमिर और उसके परिवार को बचाने के लिए किबुत्ज पहुंचे थे, जिस पर हमास का कब्जा हो गया था। अगले दिन टिबोन ने *द टाइम्स* से कहा था, 'हम जानते थे कि अगर हम उन्हें बचाने नहीं गए, तो कोई नहीं जाएगा।' नोआम ने अपने परिवार को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि गैली ने घायल इस्राइलियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ऐसी कई कहानियां हैं। सामुदायिक जिम्मेदारी के ताल्मुद विचार-'सभी इस्राइली एक-दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं'-ने ही सात अक्तूबर को यहूदियों को बचाया था।

विडंबना है कि मॉन्ट्रियल से लेकर मेलबर्न तक के इस्राइल-विरोधी, जो यूरोपीय भाषाएं बोलते हैं और ऐसी जमीन पर रहते हैं, जो अक्सर मूल निवासियों से छीनी गई थी, हिब्रू भाषी इस्राइल को उपनिवेशवाद का प्रतीक मानने लगे हैं। इस्राइली समर्थकों को एक यहूदी राज्य के रूप में अपने अस्तित्व के अधिकार के बारे में दलील देने की जरूरत है। यह आयरिश लोगों के आयरिश राज्य या यूनानियों के ग्रीक राज्य के अधिकार से अलग नहीं है। यह बहस का विषय नहीं हो सकता कि यहूदी ज्यादा पीड़ित हैं या फलस्तीनी। इस्राइल का जन्म यहूदियों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए हुआ था, न कि उसे प्रदर्शित करने के लिए।

यहूदी लोगों के प्रति शत्रुता यहूदी-विरोध को जन्म देता है और यहूदी-विरोध यहूदी लोगों के प्रति शत्रुता पैदा करता है। बीते हफ्ते योम किप्पुर के दिन जिहाद अल-शमी नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने मैनचेस्टर के एक यहूदी उपासना गृह में अपनी कार घुसा दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि वह 'हमले के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रही है।' वाकई, यह हमला दर्शाता है कि कैसे अकादमिक सेमिनारों और वामपंथी पत्रिकाओं के बाहर 'यहूदी' और 'यहूदीवाद' के बीच का अंतर उन लोगों के लिए या तो अदृश्य है या दिखावटी, जो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

निश्चित रूप से फलस्तीन पीड़ित है, लेकिन इसका कारण हमास है। बीते दो वर्षों से जो लोग इस्राइल विरोधी रैलियां निकालकर 'तत्काल युद्ध विराम' का राग अलाप रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सात अक्तूबर, 2023 से पहले तक युद्ध विराम ही था, जिसका हमास ने सबसे भयावह तरीके से उल्लंघन किया। जो लोग फलस्तीनी नागरिकों की पीड़ा की निंदा करते हैं, उन्हें इसकी भी निंदा करनी चाहिए कि हमास लगातार और जानबूझकर आम गाजावासियों को युद्ध छेड़कर खतरे में डालता रहा है। बीते दो वर्षों में यदि हमास ने हथियार डाल दिए होते, तो यह युद्ध कब का समाप्त हो गया होता, जिससे वह अब भी कतरा रहा है। इस्राइल से लगातार युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी यह मांग हमास से क्यों नहीं करते?

यदि हमास या कोई अन्य आतंकी समूह सैन्य या राजनीतिक ताकत के रूप में बचे रहेंगे, तो कोई फलस्तीनी राज्य नहीं होगा। हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य कम महत्व के देशों ने इस्राइल पर दबाव बनाने के लिए फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने का निरर्थक कूटनीतिक कदम उठाया है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्थायी फलस्तीनी राज्य का एकमात्र व्यावहारिक उपाय फलस्तीनियों के बीच एक सांस्कृतिक क्रांति है, जो इस्राइल के विनाश की कल्पना को हमेशा के लिए समाप्त कर दे।

तमाम भयावहताओं के बावजूद यह युद्ध मुक्तिदायक के रूप में याद किया जाएगा। यह युद्ध लेबनानियों के लिए मुक्तिदायक रहा है, जिन्हें दो पीढ़ियों में पहली बार हिजबुल्ला के क्रूर नियंत्रण से मुक्त होने का अवसर मिला है। सीरियाई लोग बशर अल-असद के शासन को उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं होते, अगर इस्राइल ने हिजबुल्ला समेत असद के मददगारों का सफाया न किया होता। दक्षिणी सीरिया के ड्रूज के लिए भी यह मुक्तिदायक है, जिन्हें इस्राइली सेना द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। यह गाजावासियों के लिए मुक्तिदायक है, जो हमास के युद्ध शुरू करने की इच्छा के कारण पीड़ित थे, जिन्हें पता था कि इससे पीड़ा होगी। तीन हजार वर्षों के इतिहास के बावजूद यहूदियों की हालत पहले जैसी संकटपूर्ण है। अच्छे दोस्त और साथियों के बावजूद वे आज भी अकेले हैं।

©The New York Times 2025

जीवन धारा

हेनरी थॉमस हैंबलिन

जीवन की चुनौतियों में जो लोग विजय प्राप्त करते हैं, ईश्वर उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं। सचमुच आसान जिंदगी केवल उस मजबूत आत्मा की होती है, जिसने कठिनाइयों पर जीत हासिल की हो।

क्या सुख पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है

लोग अक्सर एक आरामदायक जीवन, दुख और चिंता से मुक्ति की तलाश करते हैं। लेकिन, अपनी सारी खोज के बावजूद वे कभी वह नहीं पाते, जो वे चाहते हैं। उनके सुख में हमेशा एक कमी रह जाती है, कुछ ऐसा जो उन्हें सच्ची खुशी से वंचित कर देता है या संभवतः परिस्थितियों का संयोजन उनकी सभी योजनाओं को बिगाड़ने की साजिश रचता है। जीवन एक विरोधाभास है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, फिर भी यदि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें सुख मिलता है। जो लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं और साल-दर-साल, हर जगह सुख की तलाश करते हैं, वे उसे पाने में असफल रहते हैं।

दूसरी ओर, जो लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, वे बिना खोजे ही सुख प्राप्त कर लेते हैं। पुराने जमाने में, लोग भगवान को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते थे। वे सोचते थे कि वे बिना अनुशासन के, बिना मेहनत के जीवन जी सकते हैं और जब मुसीबत आए या चीजें उनके मन मुताबिक न हों, तो भगवान से प्रार्थना करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज भी यही सोच बनी हुई है, ताकि उनकी समस्याएं हल हो जाएं। वे अब यह नहीं मानते कि प्रार्थना से भगवान का विशेष अनुग्रह लिया जा सकता है, लेकिन वे दृढ़ता से मानते हैं कि अपनी मांगों से जो चाहें, वह प्राप्त कर सकते हैं। उनका मतलब है कि वे बिना किसी परेशानी, कठिनाई या विपत्ति के एक आसान और मजेदार जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी आसान जिंदगी कभी मिलती नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। जीवन की चुनौतियों में जो लोग विजय प्राप्त करते हैं, ईश्वर उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं। सचमुच आसान जिंदगी केवल उस मजबूत आत्मा की होती है, जिसने कठिनाइयों पर जीत हासिल की हो। उनकी जिंदगी वास्तव में आसान नहीं होती, लेकिन उनकी ताकत की वजह से वह ऐसी दिखती है। ज्यादातर लोग जीवन के सागर में बिना दिशा के बहने वाले यात्री हैं। वे कभी इधर, कभी उधर बहते रहते हैं। लेकिन कुछ ही लोग यह समझते हैं कि उनके अंदर अनंत शक्ति है, जिसके बल पर वे अपनी सभी कठिनाइयों और कमजोरियों को पार कर सकते हैं और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

एक इन्सान की सफलता सबसे ज्यादा उसकी आस्था पर निर्भर करती है। हर बाधा को पार करने की उसकी क्षमता में उसका विश्वास। अगर उसका विश्वास कमजोर है, तो उसकी जिंदगी भी कमजोर और उपलब्धियों से खाली होगी। अगर उसका विश्वास मजबूत है, तो उसकी जिंदगी में वह शक्ति भी उतनी ही अधिक दिखाई देगी। सबसे कमजोर और डरपोक व्यक्ति भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जीवन में कठिनाइयां और मुसीबतें आएंगी। लेकिन अपने अंदर की शक्ति को जगाकर, टूटी हुई उम्मीदों के मलबे से भी मजबूत और बेहतर बनकर उभरा जा सकता है।

लगातार मेहनत करते रहें

सूत्र

बगैर मेहनत के आरामदायक जीवन नहीं मिलता है, असल में आरामदायक कुछ नहीं है, जीवन संघर्ष है। लेकिन इन चुनौतियों का समाना करना ही अंत में हमें आनंद या सुख देता है। हरेक चीज आप पा सकते हैं, हरेक इन्सान के जीवन में खुशी ला सकते हैं, बस स्वयं में विश्वास रखें। लगातार मेहनत करते रहें।

दूसरा पहलू

मिजोरम में बांस में फूल आने से चूहों की आबादी बढ़ रही है, जिससे इस राज्य में अकाल की आशंका पैदा हो गई है।

बांस में फूल और चूहों का प्रकोप

मिजोरम में अचानक चूहे बढ़ गए हैं। कहावत है, 'जब बांस फूलता है, तो मृत्यु और विनाश उसके पीछे-पीछे आते हैं।' चूहों के प्रकोप को 'थिंगटम' या खास प्रजाति के बांस में फूल आने का लक्षण माना जा रहा है, जो इस बार समय से पहले ही आ गया। थिंगटम, बांस बाहुल्य उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग हर 30 वर्ष में होने वाली ऐसी त्रासदी है, जिसमें बांस में फूल आते हैं। हालांकि, यह 'माउताम' से भिन्न है, लेकिन विनाशकारी परिणाम समान होते हैं, बस फर्क होता है, तो फूल खिलने वाली बांस की प्रजाति का। 'माउताम' की मार मिजोरम 2008 में झेल चुका है, जबकि थिंगटम आखिरी बार 1977 में कहर बरपा कर गया था।

पंकज चतुर्वेदी

'माउताम' की मार मिजोरम 2008 में झेल चुका है, जबकि थिंगटम आखिरी बार 1977 में कहर बरपा कर गया था।

'माउताम' में माउटक यानी 'मेलोकाना बैक्सीफेरा' प्रजाति के बांस में फूल आते हैं, जबकि इस समय रीथिंग या 'बेंबुसा तेलुडा' प्रजाति के बांस पर फूल आ रहे हैं। जब बांस का सामूहिक पुष्पण होता है, तो सारा जंगल बीजों से ढक जाता है। ये बीज पोषक और चूहों का पसंदीदा आहार होते हैं, बीज गिरते ही चूहे इन्हें खाते हैं, प्रजनन क्षमता के कारण इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। बांस के बीजों के कारण चूहों की बढ़ती आबादी को 'चूहों का सैलाब' कहा जाता है। कुछ महीनों तक, चूहे बांस के बीजों पर जीवित रहते हैं। बांस के फूलने का चक्र पूरा होते ही बीजों का भंडार अचानक समाप्त हो जाता है। तंदुरुस्त हो चुके लाखों भूखे चूहे भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकलकर निकटतम उपलब्ध खाद्य स्रोत, यानी खेतों, विशेषकर धान के खेतों और घरों में रखे अनाज पर हमला करते हैं, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतीत गवाह है कि इसके चलते मिजोरम और आसपास के राज्य में खेती तबाह हुई और प्लेग जैसी बीमारियों से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। मिजोरम के कुल 21,000 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में से 6,000 वर्ग किलोमीटर में बांस बेतहाशा उगता है, जो भारत की आठ करोड़ टन वार्षिक बांस फसलों का 40 प्रतिशत है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था बांस के इर्द-गिर्द घूमती है। बीज गिरने का अर्थ है कि बांस के पेड़ की मौत, जो कि व्यापक स्तर पर लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है। मिजोरम में लगभग 50 वर्षों के अंतराल पर अकाल पड़ने का रिकॉर्ड रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि मिजोरम राज्य ने भी उसी समय अकाल का सामना किया, जब बांस में फूल लगे। राज्य में खेती पर पहले से ही संकट है और यदि जंगलों से बांस बीजों को उठाने और चूहा नियंत्रण के प्रभावी तकनीकी कदम नहीं उठाए गए, तो बहुत से उत्तर पूर्वी राज्यों को भारी कीमत चुकानी होगी।

कुछ महीनों तक, चूहे बांस के बीजों पर जीवित रहते हैं। बीज खत्म होते ही चूहे भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर धान के खेतों और घरों में रखे अनाज पर हमला करते हैं, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

आंकड़े

कहां के बैंक धनी

मुद्रा व्यवस्था का संचालन और उनका नियमन संबंधित देशों के केंद्रीय बैंक करते हैं। इन बैंकों की जमा राशि से पता चलता है कौन कितना अमीर है।

चीन	34.56
जापान	12.31
अमेरिका	9.10
स्विट्ज़रलैंड	9.09
भारत	6.43

आंकड़े केंद्रीय बैंकों के पास जमा राशि के, खरब डॉलर में | स्रोत : The World Factbook, 2024

भक्ति में सब संभव है

महात्मा मस्तराम को भेड़िया काट रहा था, तो वह बोले, 'बेटा, आज पेट भर खा ले।' उनका घाव अगले दिन ठीक हो गया। वह हिंसक जीवों में भी ईश्वरीय दर्शन करते थे।

अनूपशहर में उच्च कोटि के संत महात्मा मस्तराम जी रहते थे। जब भी वह अनूपशहर के बाजार जाते, तो बालकों की भीड़ उनके पीछे लग जाती थी। बच्चों से महात्मा जी का विशेष लगाव था। कभी-कभी महात्मा जी किसी हलवाई की दुकान से मिठाई उठाकर बच्चों में बांट देते थे और कभी सर्राफ की दुकान से पैसे के ढेर से मुट्ठियां भरकर लुटा देते थे। बाजार का यह दृश्य सभी को अत्यंत मनमोहक लगता था।

जिस दुकानदार का सामान महात्मा मस्तराम जी बांटते, वह स्वयं को भाग्यशाली मानता था। कहते हैं कि एक ही दिन, एक ही समय में महात्मा जी कभी अनूपशहर में, तो कभी कोलकाता में दिखाई देते थे। लोग इस विषय में पूछते कि आप एक ही समय में दो स्थानों पर कैसे दिखाई देते हैं। महात्मा जी कहते, 'भगवान की भक्ति में सब संभव है, यह सब उनकी कृपा है।' महात्मा जी जल्दी किसी से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वह बोलते, तो उनकी बातें सत्य होती थीं।

अंतर्यात्रा
संकलित

एक दिन महात्मा मस्तराम जी अनूपशहर के निकट हरचनौरी नामक स्थान पर घूम रहे थे कि एक भेड़िया आया और उसने उनकी जांघ में काट लिया। महात्मा जी वहीं बैठ गए और बोले, 'बेटा, आज पेट भर खा ले, इसके बाद तुझे मनुष्य का मांस खाने को नहीं मिलेगा।' उनका घाव अगले दिन ठीक हो गया। बताते हैं कि महात्मा मस्तराम जी हिंसक जीवों में भी ईश्वरीय दर्शन करते थे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 09 अक्तूबर, 1958

पाकिस्तान में पार्टियों के दफ्तर सील, अखबार भी बंद

राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर सील: अखबारों के मुंह भी बंद

पाकिस्तान में मार्शल-लॉ के मुख्य प्रबंधक जनरल मोहम्मद अयूब खान ने समाचार पत्रों को आदेश दिया है कि वे मार्शल लॉ पर कोई भी टिप्पणी प्रकाशित न करें। कुछ राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर सील भी लगाई गई।

अगर विविधता का उत्सव मनाना हो

विविधता का सम्मान करना हो, तो लोगों की वेशभूषा, उनकी बोली-बानी, उनकी उम्र, सभी का आदर जरूरी है।

क्षमा शर्मा

मुद्दा

लगभग डेढ़ दशक से अधिक समय से विदेश जाती रही हूं। कई देशों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं में अक्सर महसूस करती हूं कि अगर विविधता देखनी हो, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से अच्छी जगह कोई नहीं है। तमाम तरह के लोग। अनेक भाषाएं बोलते। देशों से इधर-उधर की आवाजाही। अपने देश में विविधता में एकता को सेलिब्रेट करने की बात कही जाती है। इससे ज्यादा एकता क्या होगी कि सब एक ही जगह बैठे हैं, सो रहे हैं, खा-पी रहे हैं। एक ही जहाज में अपने-अपने गंतव्यों की तरफ जाने के लिए बैठे हैं। एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा भी रहे हैं। लाइन से आ-जा रहे हैं। जहाज के गेट पर हाथ में बोर्डिंग पास पकड़े, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कोई लाइन तोड़ना नहीं, कोई लड़ाई-झगड़ा, दंगा-फसाद नहीं।

एक बात और भी है कि पहले अनेक देशों की महिलाएं अपने-अपने देश की वेशभूषा में नजर आती थीं। पुरुष तो तब भी शर्ट-पेंट पहनते थे। यानी कि

कुछ एक देशों को छोड़कर, पूरे विश्व में पुरुषों का यही पहनावा हो चुका है, लेकिन स्त्रियां कुछ अलग नजर आती थीं। भारत में भी बहुत-सी स्त्रियां साड़ियां पहने दिखती थीं। सलवार-कुर्ता, केरल की स्कर्टनुमा पोशाक भी नजर आती थी।

लेकिन अब हवाई अड्डों या उनके बाहर भी साड़ियां पहने स्त्रियां बहुत कम नजर आती हैं। कुछ साल पहले तक साड़ी किसी आयोजन में पहनने के लिए निकाली जाती थी, लेकिन अब वह भी नहीं रहा। इसकी जगह पहले कुर्ता-सलवार ने ली थी। लेकिन इन दिनों किसी किशोरी और किसी उम्रदराज स्त्री की वेशभूषा में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। हालांकि, इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि कपड़ों का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता। अब भारत में स्त्रियों के माथे से बिंदी भी गायब हो गई है। सिंदूर पहले ही गायब हो चुका है। जब से स्त्री के सौंदर्य को बनाने का ठेका तमाम अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य ब्रांड्स ने उठाया है, तब से स्त्री को त्वचा में बदल दिया गया है।

आपको वह विज्ञापन तो याद ही होगा-अरे उसकी त्वचा से तो उसकी उम्र का पता ही नहीं लगता। और इस उम्र को छिपाना है, तरह-तरह के ब्रांड्स का इस्तेमाल करके। यही बात कपड़ों के बारे में भी है। भारत के हवाई अड्डे हों, या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 99 प्रतिशत लड़कियां और स्त्रियां वेस्टर्न पहनावे में ही दिखती हैं। यहां तक कि उनके बाल बनाने का तरीका भी लगभग एक जैसा है।

पिछले दिनों इटली में जन्मे, अपने ब्रांड्स के लिए मशहूर, अरमानी का निधन हुआ है। अरमानी का एक बार लंबा साक्षात्कार पढ़ा था। उनसे पूछा गया था कि आपने जीवन में कौन-सा सबसे बड़ा ट्रेंड चलाया है। तब उन्होंने कहा था कि मैंने लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना दिए। आज ये कपड़े सशक्त स्त्रियों की पहचान माने जाते हैं। एक बार पिछली सदी की शुरुआत में एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने भी ऐसा ही किया था। उन दिनों अमेरिका में भी स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती थीं। इस सिगरेट निर्माता ने एक बड़े प्रोपेगैंडिस्ट की मदद से इतवार के दिन सड़क पर सिगरेट पीती स्त्रियों का जुलूस निकाला। इन्हें आजादी की मशालें कहा गया। तब से सिगरेट पीना भी सशक्त औरतों का प्रतीक मान लिया गया।

कहने का अर्थ यह कि एक तरफ हम विविधता को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अपने व्यापारिक हितों के लिए उसे नष्ट भी करते जा रहे हैं। एक बात और, जो इन हवाई अड्डों पर बहुत शिद्दत के साथ महसूस होती है, वह है, यहां काम करने वाले कर्मचारियों की उम्र। चाहे एअरहोस्टेस हों, केबिन क्रू या हवाई अड्डों पर भाग-दौड़ करते लोग, सब तीस की उम्र से भी कम नजर आते हैं। वे ऊर्जा और शक्ति से भरे दिखते हैं। सिवाय पायलेट्स और सरकारी कर्मचारियों के कोई और बड़ी उम्र का नजर ही नहीं आता।

सोचिए कि जब ये युवा कुछ उम्रदराज हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा? क्या इन्हें नौकरियों से हटाकर इनकी जगह, इनकी आज की उम्र के लोगों को ले आया जाएगा? आखिर तब ये कहां जाएंगे? उम्र के प्रति इस तरह का रवैया बेहद नकारात्मक है। यही देखकर लगता है कि क्यों कोई उम्रदराज भी हमेशा बहुत से रसायनों का इस्तेमाल करके युवा दिखना चाहता है, क्योंकि उम्रदराज किसी को भी पसंद नहीं आते। यह भी एक तरह से विविधता को नष्ट करना है। सिर्फ युवा ही क्यों चाहिए, बाकी कोई और क्यों नहीं? आज भी अनुभव का कोई विकल्प नहीं माना जाता। विविधता का सम्मान करना हो, तो लोगों की वेशभूषा, उनकी बोली-बानी, उनकी उम्र, सभी का आदर जरूरी है।

edit@amarujala.com